



योजना

जून 2016

विकास को समर्पित मासिक

₹ 22

तरक्की भारत की

सशक्तीकरण से संवृद्धि

चरण सिंह

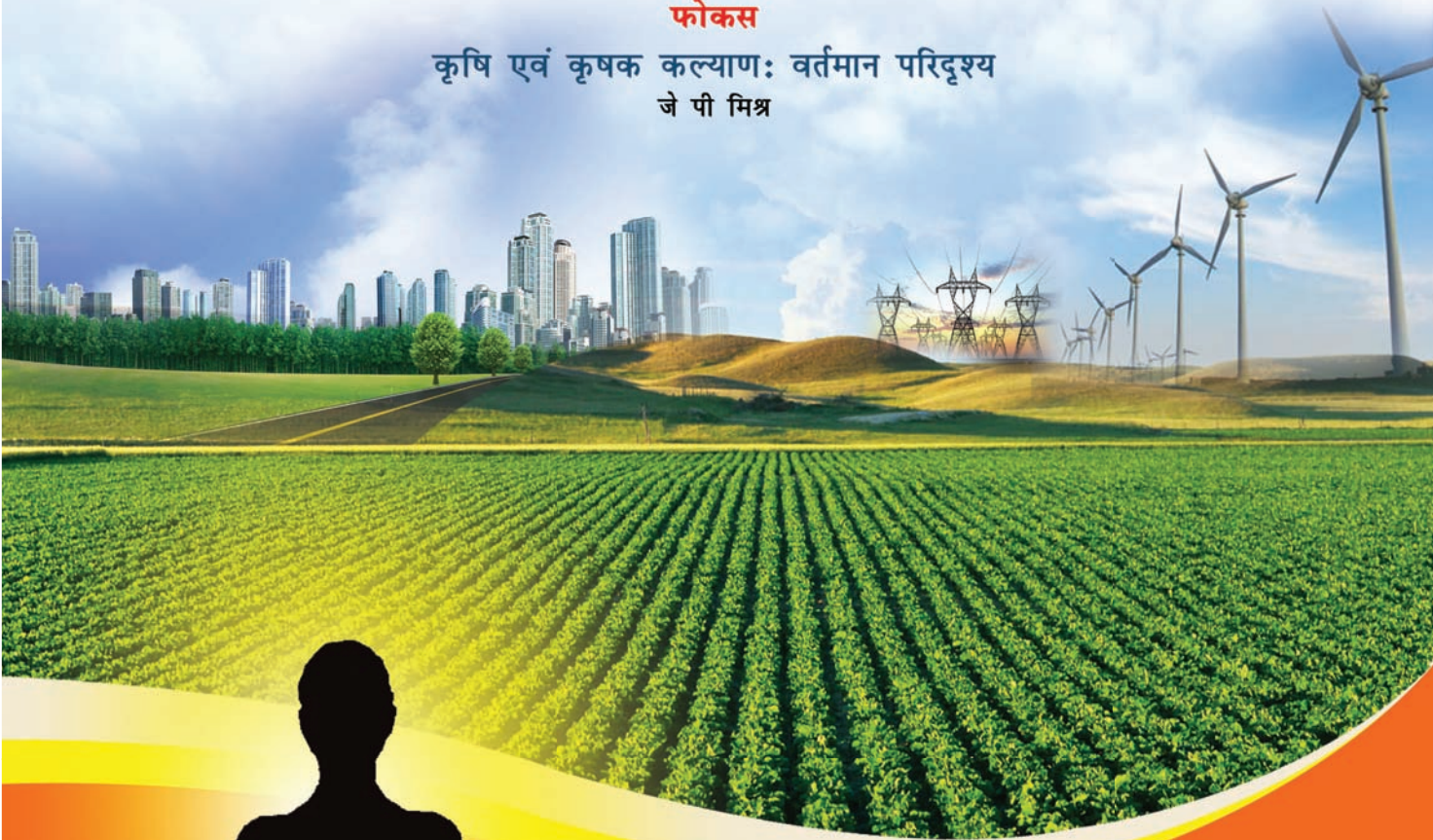
अधिकतम शासन: ई-शासन के माध्यम से जनपहुंच

रंजीत मेहता

फोकस

कृषि एवं कृषक कल्याण: वर्तमान परिदृश्य

जे पी मिश्र



योग पर विशेष

योग: स्वस्थ व तनावमुक्त जीवन का संतुलन
ईश्वर एन आचार्य

योग: आधुनिक जीवनशैली व अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता
आई बासवरेड्डी

विशेष आलेख

योग साधकों का मूल्यांकन व प्रमाणन
रवि पी सिंह, मनीष पांडे

दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना

यह योजना शहरी व ग्रामीण गरीबों के उन्नयन के लिए बनाई गई है। कौशल विकास एवं अन्य साधनों से आजीविका के अवसर बढ़ाकर सशक्त करते हुए शहरी और ग्रामीण गरीबों के उन्नयन की यह अतिमहत्वपूर्ण योजना है। योजना के मुख्य घटक हैं -

- प्रत्येक शहरी गरीब पर 15,000 से 18,000 रुपये खर्च कर कौशल सिखाना।
- व्यक्तिगत परियोजना के लिए 2 लाख रुपये की और समूह उद्यमों के लिए 10 लाख रुपये की ब्याज सब्सिडी के साथ व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम एवं समूह उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार को बढ़ावा देना। सब्सिडी के साथ ब्याज की दर 7 प्रतिशत होगी।
- शहरी नागरिकों की

आवश्यकताओं पूरी करने के लिए शहरी गरीबों को नगर आजीविका केंद्रों के माध्यम से बाजार केंद्रित कौशल का प्रशिक्षण देना। प्रत्येक केंद्र को 10 लाख रुपये का पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। ● शहरी गरीबों को वित्तीय एवं सामाजिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए स्वयं-सहायता समूह बनाने के लिए तैयार करना और प्रत्येक समूह को 10-10 हजार रुपये की सहायता देना, ताकि बदले में प्रत्येक समूह को बैंकों से मदद मिल सके। ● आपूर्तिकर्ताओं के कौशल का विकास करने के अलावा उनके बाजारों का विकास करना तथा ● शहरी बेघरों के लिए स्थायी आश्रयगृहों का निर्माण एवं अन्य आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था।

वनबंधु कल्याण योजना

वनबंधु कल्याण योजना की परिकल्पना पांचवीं अनुसूची में शामिल राज्यों के पिछड़े हुए क्षेत्रों को स्पष्ट बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के साथ आदर्श क्षेत्र के रूप में विकसित करना, ताकि विकास का अभियान और आगे बढ़े तथा निम्नलिखित बातें सुनिश्चित हों:

- गुणात्मक एवं सतत रोजगार
- गुणवत्तायुक्त शिक्षा एवं उच्च शिक्षा पर जोर
- आदिवासी क्षेत्रों का त्वरित आर्थिक विकास
- सभी के लिए स्वास्थ्य

- सभी के लिए आवास
- सभी के लिए दरवाजे पर ही सुरक्षित पेयजल
- क्षेत्र के अनुरूप सिंचाई की सुविधाएं
- सभी मौसमों में चालू रहने वाली सड़कों के जरिये नजदीकी शहरों से संपर्क
- बिजली की चहुंओर उपलब्धता
- शहरी विकास
- विकास के रथ को लगातार चलते रहने के लिए टोस संस्थागत प्रणाली
- आदिवासी सांस्कृतिक धरोहर का संवर्द्धन एवं संरक्षण
- आदिवासी क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम बालिकाओं को जीवित रखने, सुरक्षित रखने एवं सशक्त बनाने के लिए समन्वित एवं केंद्रित प्रयास सुनिश्चित करने हेतु आरंभ किया गया था। इसे एक राष्ट्रीय अभियान एवं सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में कम सीएसआर वाले 100 चुने गए जिलों में संकेंद्रित बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम के जरिये क्रियान्वित किया जा रहा है।

कार्यक्रम के उद्देश्य हैं:

- लैंगिक भेदभाव के कारण बालिकाओं की हत्या रोकना
- बालिकाओं का जीवन एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना
- बालिकाओं की शिक्षा एवं सहभागिता सुनिश्चित करना।



सुकन्या समृद्धि योजना

बालिकाओं के लिए लघु बचत योजना सुकन्या समृद्धि खाता 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना का ही अंग है।

सुकन्या समृद्धि खाता बालिका के जन्म लेने से लेकर उसकी आयु 10 वर्ष होने तक किसी भी समय उसके नाम से खुलवाया जा सकता है।

आरंभ में न्यूनतम 1,000 रुपये जमा कराने होते हैं और उसके बाद 100 रुपये के गुणक में कोई भी राशि जमा कराई जा सकती है। इस योजना के आरंभ होने से एक वर्ष पहले जो बालिका 10 वर्ष की हो चुकी थीं, वे भी इस योजना के अंतर्गत खाते खुलवा सकती हैं।

नयी मंजिल

इस योजना का उद्देश्य पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके या मदरसों जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में पढ़े 17 से 35 वर्ष के अल्पसंख्यक युवाओं को कक्षा आठवीं या दसवीं तक औपचारिक शिक्षा तथा प्रमाणपत्र के साथ कौशल प्रशिक्षण देकर लाभ पहुंचाना है ताकि वे संगठित क्षेत्र में बेहतर रोजगार प्राप्त करने लायक हो जाएं और बेहतर जीवन जी सकें। कम से कम 30 प्रतिशत सीटें अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए रखी गई हैं। इसमें 9 से 12 महीने का गैर-आवासीय कार्यक्रम भी है, जिसमें उनकी शिक्षा

के लिए (कक्षा आठवीं या कक्षा दसवीं के लिए) प्राथमिक सेतु कार्यक्रम चलाया जाता है तथा और लगातार एवं लाभकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए किसी कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। योजना पूरे देश में क्रियान्वित हो रही है। पहले पांच वर्ष के लिए 650 करोड़ रुपये की लागत से इस योजना को मंजूरी दी गई है। विश्व बैंक ने 5 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता मंजूर कर दी है और विकास संबंधी ऐसी ही चुनौतियों से जूझ रहे अफ्रीकी देशों को भी यह योजना लागू करने की सिफारिश की है।



योजना

वर्ष: 60 • अंक 6 • जून 2016 • ज्येष्ठ-आषाढ़, शक संवत् 1938 • कुल पृष्ठ: 68

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित

प्रधान संपादक: दीपिका कच्छल
संपादक: ऋतेश पाठक
संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष (प्रधान संपादक): 24362971
ईमेल: yojanahindi@gmail.com
वेबसाइट: www.yojana.gov.in
www.publicationsdivision.nic.in
http://www.facebook.com/yojanahindi

संयुक्त निदेशक (उत्पादन): वी के मीणा

सहायक निदेशक (प्रसार): पद्म सिंह
(प्रसार एवं विज्ञापन)

ईमेल: pdjuicir@gmail.com
आवरण: जी पी धोपे

पत्रिका मंगवाने, सदस्यता, नवीकरण,
पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के
लिए मनीऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर
'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग' के
नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें:

सहायक निदेशक (प्रसार एवं विज्ञापन)
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 48-53
भूतल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष: 011-24367453

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के
लिए हमारे निम्नलिखित विक्रय केंद्रों पर भी
संपर्क किया जा सकता है।

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

शहर	पता	पिनकोड	दूरभाष
नयी दिल्ली	सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	23890205
नवी मुंबई	701, सी-विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर	600090	24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	2330650
हैदराबाद	ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली	500001	24605383
बंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज	226024	2225455
अहमदाबाद	अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर	380007	26588669
गुवाहाटी	के. के. बी. रोड, नयी कॉलोनी, कमान संख्या-7, चेनीकुटी	781003	2665090

इस अंक में

- **संपादकीय** 7
- सशक्तीकरण से संवृद्धि
चरण सिंह 9
- **फोकस**
कृषि और किसानों का कल्याण:
वर्तमान परिदृश्य
जे पी मिश्र 13
- अधिकतम शासन: ई-शासन के
माध्यम से जनपहुंच
रंजीत मेहता 17
- समावेशी विकास और दूरगामी
परिणाम का राजनय
अचल मल्होत्रा 21
- सरकार, सुशासन और सामाजिक
न्याय
स्वदेश सिंह 25
- ई-शासन: पारदर्शिता, सुगमता
और जनसंवाद
शिवानंद द्विवेदी 29
- सूखा प्रबंधन में कदमताल की
कोशिश
अरविंद कुमार सिंह 36
- समकालीन भारतीय संदर्भ में
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
दिशा नवानी 39
- ताकि कल-कल बहे गंगा-यमुना
गीता चतुर्वेदी 43
- कौशल विकास और निजी क्षेत्र
प्रमोद भसीन 47
- **क्या आप जानते हैं?** 50
- योग: आधुनिक जीवनशैली व
अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता
ईश्वर वी बासवरेड्डी 51
- **विशेष आलेख**
योग साधकों का मूल्यांकन एवं
प्रमाणन
रवि पी सिंह, मनीष पांडे 55
- योग: स्वस्थ व तनावमुक्त जीवन
का संतुलन
ईश्वर एन आचार्य, राजीव रस्तोगी 59
- योग: स्वास्थ्य एवं जीवनशैली का
विकास
एच आर नागेंद्र 63

- योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।
- योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।
- प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं है।

दरें: वार्षिक: ₹ 230 द्विवार्षिक: ₹ 430, त्रिवार्षिक: ₹ 610



आपकी राय



पूर्वोत्तर में जिज्ञासा बढ़ी

पत्रिका योजना का अप्रैल 2016 अंक में प्रकाशित आलेख पूर्वोत्तर की ओर अग्रसर कौशल मिशन ज्ञानवर्धक लगा। वर्तमान समय में युवा वर्गों में पूर्वोत्तर के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ रही है। पूर्वोत्तर में नए जिलों में कौशल विकास केंद्र और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की स्थापना करते हुए पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर स्किल इंडिया पहल का प्रारंभ किए जाने की घोषणा की है। त्रिपुरा तेजी से प्रगति कर रहा है, शेष भारत से कहीं ज्यादा तेज गति से अपने लोगों को शिक्षित कर रहा है। पूर्वी भारत के परंपरागत घरेलू बाजार तक पहुंच वाली अपनी सामरिक अवस्थिति की वजह से विशेष लाभ की स्थिति में है। बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों से निकटता के कारण यह क्षेत्र दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के बाजारों के लिए लाभप्रद प्रवेश द्वार भी है। पूर्वोत्तर के पास उपजाऊ कृषि भूमि और प्रतिभाशाली लोगों का विशाल समूह है, जो इसे भारत के सबसे खुशहाल क्षेत्रों में तब्दील कर सकता है। मेघालय में अगरवुड के वृक्षारोपण के जरिए रोजगार के अवसर ज्यादा तेजी से सृजित किए जा सकते हैं।

अशोक कुमार ठाकुर
मालीटोल, अदलपुर, दरभंगा (बिहार)

जरूरी है एक्ट ईस्ट

योजना का अप्रैल 2016 का अंक 'विकास के क्षितिज पर पूर्वोत्तर' पूर्वोत्तर के विकास एवं विकास की भौगोलिक दशाओं पर केंद्रित था। भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति को कारगर रूप से लागू करने के लिए पूर्वोत्तर का विकास आवश्यक है।

पूर्वोत्तर भारत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से अनोखा है। यहां स्टार्ट अप की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। इसके लिए पूर्वोत्तर में संपर्क मार्गों की समस्या को दूर करने की आवश्यकता है, जिससे पूर्वोत्तर सुखी और समृद्ध होगा और हमारा देश उन्नति करेगा।

तनु सिंह
गौसगंज, हरदोई (उत्तर-प्रदेश)

सामान्य अध्ययन के लिए रामबाण

पूर्वोत्तर पर केंद्रित योजना का अप्रैल, 2016 का अंक पढ़ा। अंक से पूर्वोत्तर की बेमिसाल प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक विविधता से परिचय हुआ। मैं स्नातक प्रथम वर्ष की छात्रा हूं और भारतीय सिविल सेवा की तैयारी कर रही हूं। इस पत्रिका से मिलने वाली जानकारियां प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन विषय के लिए रामबाण हैं।

इस अंक से हमने जाना कि पूर्वोत्तर के अंतर्गत 8 राज्य: असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा सिक्किम आते हैं। इन्हें प्यार से सात बहन कहा जाता है। असम को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है।

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल अधिसूचना द्वारा एक नया स्वशासी जिले का निर्माण कर

कृपया ध्यान दें

सदस्यता संबंधी पूछताछ अथवा पत्रिका प्राप्त न होने की स्थिति में कृपया वितरण एवं विज्ञापन व्यवस्थापक से इस पते पर संपर्क करें:

वितरण एवं विज्ञापन व्यवस्थापक

प्रकाशन विभाग, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003, फोन नं: 011-24367453
ई-मेल: pdjucir@gmail.com

सकता है। किसी भी स्वशासी जिले के क्षेत्र में कमी या वृद्धि कर सकता है। पूर्वोत्तर भौगोलिक रूप से हिमालय, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, ब्रह्मपुत्र एवं बराक घाटी मैदान तथा मेघालय की पहाड़ियों आदि में विभक्त है। यह क्षेत्र भारत-मलय, भारत-चीनी एवं भारतीय जैव भौगोलिक क्षेत्र के संगम पर अवस्थित हैं। अंत में कहना चाहूंगी:

पूर्वोत्तर है भारत की विविधता की पहचान,
यह है भारत की शान
इससे बढ़ता है भारत का मान-सम्मान,
इससे मिलता है भारतीय संस्कृति का ज्ञान,
पूर्वोत्तर पर हमें है अभिमान॥

नेहा कुमारी
हाजीपुर, वैशाली (बिहार)

योजना ने लिखना सिखाया

पूर्वोत्तर पर आधारित योजना का अप्रैल 16 का अंक पढ़ा। अंक से पूर्वोत्तर के बारे में जानकारी मिली। संपादकीय ज्ञानवर्धक और पूर्वोत्तर की समस्याओं के प्रति ध्यान दिलाने वाला रहा। मैं विगत आठ महीनों से योजना की नियमित पाठक हूँ। इस पत्रिका के अध्ययन से मैंने अपनी लेखन शैली का विकास किया है। यह पत्रिका भारत की संस्कृति एवं विकास को प्रस्तुत करती है।

पूर्वोत्तर के अंतर्गत आठ राज्य आते हैं: असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और सिक्किम। पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वारा असम को कहा जाता है। भारत सरकार प्रति वर्ष अपने बजट में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त धन का प्रावधान करती है। इस वर्ष के बजट में सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए 2400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वित्त परिषद के लिए बजट आवंटन 30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये दिया गया है। इससे स्टार्ट अप इंडिया कार्यक्रम को बल मिलेगा।

संजय हजारिका, एन.सी. सक्सेना, सौरभ कुमार दीक्षित, राजेश राय सहित सभी लेखकों के लेख ज्ञान में वृद्धि करने वाले रहे।

पूजा गुप्ता
ब्रह्मपुरा, मुजफ्फरपुर, बिहार

कब थमेगे अदालत के आंसू!

भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की आंख हाल में आंसू से भर आए जब वे दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने गए थे।

भारत में हर रोज लगभग हजारों लोग अपनी न्याय की आश से न्यायालय के दरवाजा

खटखटाते हैं, परंतु कुछ लोगों को न्याय मिलने में काफी दिन लग जाते हैं और यह बात आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी है कि इसाफ में देरी इसाफ न मिलने के बराबर होती है। इन्हीं प्रमुख चिंताओं की वजह से हमारे मुख्य न्यायाधीश अपनी आंसू की धार को पोंछते हुए अपनी भावना सरकार के समक्ष रखा और कहा कि आखिर कब तक जजों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने वर्तमान और पिछले सभी सरकारों को कटघरे में इस मुद्दे पर ला खड़ा किया है। उनका कहना था कि जब 1987 में लॉ कमीशन ने जजों की संख्या बढ़ाने की बात कही थी, तो आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। क्या इसे हम अपना दुर्भाग्य समझे। अब देखना है कि कैसे वर्तमान सरकार उन सभी संवैधानिक अड़चनों को दूर कर सुप्रीम कोर्ट में कब तक जजों की संख्या बढ़ाने में न्यायपालिका की मदद करती है।

चूँकि सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है कि मामला देश के सबसे बड़े न्याय के उस मंदिर का है जिसके अंदर बैठे भगवान की आंख में आंसू की छलक अपने लिए नहीं बल्कि देश की दशा के लिए छलक उठी है।

सोहन दास
भेड़वा नावाडीह, मधुपुर, देवघर
(झारखंड)

अब ऑनलाईन सब्सक्राइब करें



लॉग ऑन करें योजना
<http://publicationsdivision.nic.in/>
सहयोग: bharatkosh.gov.in



Most trusted & renowned
institute among IAS aspirants

हिंदी माध्यम के IAS/PCS टॉपर्स क्या कहते हैं
'दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे' पत्रिका के बारे में...



निशांत जैन (IAS - राजस्थान कैडर)

'दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे' स्वयं में एक अनूठी और बहुआयामी पत्रिका है। इसका सभी विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध होना प्रतियोगिता जगत की एक बड़ी ज़रूरत पूरी करता है। मैंने खुद इस पत्रिका का लाभ उठाया है।

सिविल सेवा परीक्षा पर ही पूरी तरह केन्द्रित यह पत्रिका कई मायनों में विशिष्ट है। इंटरव्यू खंड, निबंध खंड, एथिक्स आदि पर विशेष ध्यान देना इस पत्रिका को बाकी पत्रिकाओं से अलग बनाता है। समसामयिक घटनाओं का सिविल सेवा परीक्षा के नज़रिये से विश्लेषण और फिर उनकी बिन्दुवार प्रस्तुति बेहद उपयोगी और प्रासंगिक है।

'दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे' आपकी सफलता में सार्थक भूमिका निभाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

राजेन्द्र पेंसिया (IAS - उत्तर प्रदेश कैडर)



हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि पत्रिका कौन सी पढ़ी जाए? इसके लिये सबसे अच्छा, श्रेष्ठ, प्रामाणिक और सारगर्भित स्रोत 'दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे' के माध्यम से मिलता है। इंटीग्रेटेड एप्रोच से तैयारी के लिये हिंदी माध्यम में ऐसी किसी पत्रिका का अभाव था जो प्रिलिम्स, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की ज़रूरतों को पूरा कर सके। विकास सर के मार्गदर्शन में यह पत्रिका निश्चित ही इन सभी मानकों पर खरी उतरती है। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी गूगल ट्रांसलेट डेव मैटिरियल पढ़ने की बजाय यह पत्रिका पढ़ें जो पूर्णतः मौलिक व अनुभवी टीम की मेहनत का परिणाम है। मुझे विश्वास है कि यह पत्रिका उनके लिये निश्चित रूप से वरदान साबित होगी। शुभकामनाएँ।



मनीष कुमार (IPS)

यह पत्रिका (दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे) हिन्दी माध्यम में उपलब्ध पाठ्य सामग्री की कमी को पूरा करने की एक गंभीर कोशिश है। इसके सभी खंडों का व्यवस्थित अध्ययन तैयारी को संपूर्णता प्रदान करता है। पत्रिका के 'समसामयिक मुद्दों पर संभावित प्रश्नोत्तर' खंड से मुझे मुख्य परीक्षा की तैयारी में विशेष मदद मिली थी।



अकित तिवारी (IRS IT)

'दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे' एक सारगर्भित एवं विविध आयामी पत्रिका है जो सिविल सेवा परीक्षा के तीनों चरणों- प्रिलिम्स, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिये आवश्यक पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराती है। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिये सबसे बड़ी चुनौती समसामयिक मुद्दों पर प्रामाणिक कंटेंट की उपलब्धता की थी परंतु 'दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे' ने इस चुनौती को स्वीकारते हुए उत्कृष्ट एवं प्रामाणिक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई है, जो सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिये वरदान साबित हो रही है। समसामयिक मुद्दों पर 'प्रश्नोत्तर खण्ड' तो मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु विशेष रूप से उपयोगी है। विकास सर का सम्पादकीय लेख अभ्यर्थियों को निरंतर प्रोत्साहित करता रहता है।



विवेक यादव (UPPCS, I-Rank)

राज्य व संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की दृष्टि से यह पत्रिका मुझे बहुत उपयोगी लगी। यह पत्रिका समसामयिक घटनाचक्र के विषयों में आपकी समझ बढ़ाने के साथ ही साथ उस विषय पर बहुआयामी दृष्टिकोण का सृजन करती है। इस पत्रिका का निबंध व मार्क इंटरव्यू खण्ड तमाम डाउट्स को क्लियर करने में सहायक है।

आई.ए.एस., पी.सी.एस. तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को समर्पित पत्रिका

ISSN 2455-6025



करंट अफेयर्स टुडे

बर् / अंक 12 जून 2016

महत्त्वपूर्ण लेख

- ❖ गहराते नेपाल-चीन संबंध और भारत के लिये मुश्किलें
- ❖ रियल एस्टेट क्षेत्र में सुधारों की मजबूत पहल
- ❖ भारतीय दंड संहिता में सुधारों की प्रासंगिकता
- ❖ कितना उचित है आवार?
- ❖ गहराते भारत-सऊदी अरब संबंध

सुपरफास्ट रिवीज़न सीरीज़

- ❖ आई.ए.एस. (प्रारंभिक) परीक्षा हेतु 'भारत एवं विश्व का भूगोल' पर अति महत्त्वपूर्ण एवं सारगर्भित सामग्री

प्रिलिम्स विशेष

- ❖ पी.टी. एक्सप्रेस : प्रारंभिक परीक्षा के लिये संभावित प्रश्नोत्तरों का संकलन
- ❖ सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस पेपर

इंटरव्यू एवं वाद-विवाद

- ❖ नज़रिया : इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ जटिल प्रश्न और उनके उत्तर (जोया खड)
- ❖ मॉक इंटरव्यू और मूल्यांकन
- ❖ क्या स्वस्थ समाज के निर्माण के लिये शराब पर पूर्ण प्रतिबंध सर्वथा उचित कदम होगा?



और भी बहुत कुछ...



प्रदीप कुमार (IRS)

'दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे' एक मानक पत्रिका है। पिछले दो अंकों में तो इसने 'गागर में सागर' भर दिया है। वस्तुतः बाज़ार में उपलब्ध स्तरहीन सामग्री ने अभ्यर्थियों को दिशा-भ्रमित ही किया है। ऐसे में 'दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे' ने विद्यार्थियों की राह आसान कर दी है।



जय प्रकाश (IRTS)

विद्यार्थियों के समक्ष उच्च स्तर की पाठ्य सामग्री का सदैव अभाव रहा है जिसके कारण हिंदी भाषी छात्र हीन भावना का शिकार रहते हैं। यह पत्रिका (दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे) इस मानक पर खरी उतरती है। इसमें परीक्षा के अनुरूप बहुआयामी समसामयिक खंडों को विश्लेषित करने तथा रोचक ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता है। खास तौर पर निबंध, एथिक्स और इंटरव्यू के लिये किया गया प्रयास इसे अन्य पत्रिकाओं से बेहतर बनाता है जो अवश्य ही विद्यार्थियों की सफलता में निर्णायक सिद्ध होगा। मैं दृष्टि परिवार की अनुकरणीय पहल का आभार व्यक्त करता हूँ।



आदित्य प्रजापति (UPPCS, II-Rank)

मुख्य व प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पत्रिका मुझे बहुत उपयोगी लगी। पत्रिका के लेख, निबंध व एथिक्स खण्ड परीक्षार्थियों के लिये निश्चित रूप से बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे।



641, 1st Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9

E-mail: info@drishtiias.com, drishtiacademy@gmail.com * Website: www.drishtiias.com

Contact : 87501 87501, 011-47532596

प्रगति पथ पर राष्ट्र

कि

सी राष्ट्र के विकास पर आर्थिक, सामाजिक, मानव संसाधन, पर्यावरण जैसे विभिन्न कारकों का प्रभाव पड़ता है, जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इनमें से प्रत्येक मानदंड स्वयं में महत्वपूर्ण है। इन कारकों के अलग-अलग मिश्रण के कारण अधिकतर विकासशील देशों के सामने विकास से जुड़ी अलग-अलग चुनौतियां खड़ी होती हैं। आर्थिक विकास और सामाजिक विकास साथ-साथ होते हैं। कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, सिंचाई, ऊर्जा संसाधन आदि में सुधार से आर्थिक सुधार के संकेत मिलते हैं और स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पेयजल आदि में सुधार की प्रक्रिया सामाजिक सुधार की दिशा में इंगित करती है। दोनों ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता की वित्तीय स्थिति से संबंधित हैं।

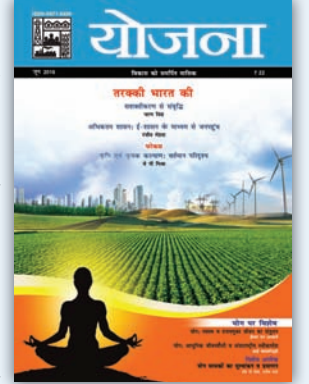
आर्थिक वृद्धि को अधिक समावेशी बनाने के लिए उसके आधार को व्यापक बनाने और वृद्धि की प्रक्रिया से मिलने वाले लाभों को साझा करने की जरूरत हमेशा से महसूस की गई है। समावेशी वृद्धि का अर्थ ऐसी आर्थिक वृद्धि है, जो सुखी बनाने के लिए बुनियादी में सुधार कर मूलभूत जरूरतों को पूरा करे और साथ ही अवसर भी सृजित करे। इसमें समान अवसर प्रदान करना और शिक्षा तथा कौशल विकास के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना शामिल है।

1.2 अरब की विविधता भरी जनसंख्या वाले देश में वृद्धि के स्तरों को समाज के सभी वर्गों तथा देश के सभी भागों तक ले जाना सबसे बड़ी चुनौती है और यहीं सरकार की भूमिका आरंभ होती है। इस प्रकार सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को इन सभी मानदंडों पर विकास के लिए तैयार होना होगा। योजनाकारों एवं नीति निर्माताओं को इस बात का ध्यान रखना होगा कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और प्रति व्यक्ति आय देश की जनता का विकास सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। कुशल मानव संसाधन किसी भी समाज के विकास की पहली इकाई होता है। सभी के लिए, गरीब से गरीब बच्चे और बेहद दुर्गम इलाके में रहने वाले बच्चे के लिए भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कर मानव संसाधन का विकास करना उतना ही जरूरी है, जितना सभी के लिए आजीविका सुनिश्चित करना। अब पर्यावरण के मुद्दों को भी विकास के पैमानों की सूची में जोड़ दिया गया है क्योंकि जलवायु परिवर्तन को किसी राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। सूखा एवं बाढ़ की आपदाएं किसानों की अर्थव्यवस्था के साथ ही सामाजिक ढांचे को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं और सरकार को उनसे प्राथमिकता के साथ निपटना होगा।

सरकार की कई हालिया नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रयास सबसे निचले तबके के आम आदमी तक पहुंचना रहा है। कृषि एवं किसानों के कल्याण के लिए भारी बजटीय आवंटन किया गया है और समाज के अलग-थलग किए गए वर्गों को मुख्यधारा में लाने और उन्हें तेज आर्थिक वृद्धि के लाभ उठाने लायक बनाने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, मुद्रा बैंक, सेतु, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे कई कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। देश में पर्याप्त और टिकाऊ सुरक्षा नेटवर्क तैयार करने की मंशा से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना आरंभ की गई हैं। बुनियादी ढांचा, चाहे मकान हों, सड़क हों, रेलवे हो अथवा ग्रामीण बुनियादी ढांचा हो, सभी प्रत्येक नागरिक के जीवन को करीब से छूता है और इसीलिए वह उस महत्व का हकदार है, जो उसे दिया जा रहा है। आम आदमी तक विकास के लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) जैसे कार्यक्रमों के जरिए ई-प्रशासन पर भी सरकार का जोर रहा है। रोजगारपरकता के लिए महत्वपूर्ण कौशल विकास, उद्यमशीलता के लिए स्टार्ट अप इंडिया एवं स्टैंड अप इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने सबका विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद की है।

विकास के लाभ तभी प्राप्त किए जा सकते हैं, जब नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। पूरा विश्व स्वास्थ्य के लिए योग के लाभों को महसूस कर रहा है और हर वर्ष 21 जून को अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्र के रूप में भारत ने योग को दुनिया के हरेक कोने तक ले जाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है।

भारत निर्भरता और बेहद निर्धनता के उन दिनों से बहुत दूर आ चुका है, जिन दिनों खाद्य का आयात करना पड़ता था, रोजगार की भारी किल्लत थी और कुपोषण तथा रोग हमारे मानव संसाधन को नष्ट कर रहे थे। स्वतंत्रता के छह दशक से भी ज्यादा समय बाद अब भारत ऐसी स्वतंत्र ताकत बन गया है, जिसे गंभीरता से लिया जाता है। अब भारत प्रगति करता राष्ट्र है। □



TARGET **IAS** 2017

KSG

An Institute for IAS Exam...

सामान्य अध्ययन
द्वारा **डॉ. खान**

“विशेषज्ञों से पढ़ने का अतिरिक्त लाभ”

पत्राचार कोर्स (अंग्रेजी एवं हिन्दी)

- सामान्य अध्ययन • भूगोल • इतिहास
- लोक प्रशासन • समाजशास्त्र • मनोविज्ञान

प्रतिदिन
टेस्ट

नया बैच
प्रारंभ
17 जून
2016

2017

फाउंडेशन
कोर्स
पंजीकरण प्रारंभ

डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम (डीएलपी)
घर पर रहते हुए क्लासरूम अध्ययन का लाभ उठायें;
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।

Most Comprehensive Coverage of Syllabus with POD Technique

“We are a dedicated team of experts and only those who are willing to work hard should join us.”

Special Focus on Answer Writing Skill Development

NORTH DELHI : 17th June

2521, Hudson Line, Vijay Nagar Chowk,
GTB Nagar Metro Station, Delhi - 09
Ph: 011-4555 2607/8 M: 09717 380 832

CENTRAL DELHI : 17th June

1/1-A, 2nd Floor, Old Rajinder Ngr. Mkt.
Above Syndicate Bank, Delhi - 60
Ph: 011-4517 0303, (M) 09560 862 483

JAIPUR : 24th June

403-404, Apex Tower, Lal Kothi, Tonk
Road Jaipur-302015 Ph: 0141-4052441,
0141-2743441 M: 08290 800 441

BHOPAL : 4th July

Plot No. 43, R.R. Arcade, IInd Floor
(S-1, S-3), Zone II, M.P. Ngr, Bhopal-11
Ph: 0755-4077 441 M: 07509 975 361

PATNA : 9th July

Above Toyota Showroom, Exhibition
Road, Near Gandhi Maidan, Patna-1
Ph: 0612-3223478, M: 09386 337 412

DIBRUGARH: August, 16

Centre for Management Studies
(CMS), Dibrugarh University
Dibrugarh, Assam - 786004
(M) 7086708270

Send us email: drkhan@ksgindia.com, You can also download Registration Form from Website : www.ksgindia.com

सशक्तीकरण से संवृद्धि

चरण सिंह



भारत की गिनती दुनिया में सबसे तेजी से विकास कर रहे देशों में होती है। कोई भी विकास तब तक अधूरा है जब तक समाज के हर वर्ग तक उसका लाभांश पहुंच न जाए। उसी को ध्यान में रखकर समाज के हर वर्ग के वित्तीय समावेशन के लिए अनेकानेक कदम उठा रही है। कृषक, छात्र, उद्यमी, कारोबारी आदि सभी को एक समान वित्तीय मंच पर लाने का यह प्रयास अभी शुरुआत पर है परंतु संकेत अच्छे दिख रहे हैं

मई 2014 के बाद से केंद्र सरकार देश को सबल बनाने और विकास दर को 9 प्रतिशत से अधिक करने का प्रयास कर रही है। इसके बाद सरकार ने अनेक घोषणाएं कीं जिनके केंद्र में विकासोन्मुखी नीतियों के माध्यम से विकास की उच्च दर प्राप्त करना था। लगभग आठ शताब्दियों तक विदेशी शासन के अंतर्गत भारत ने संसाधनों के अभाव और आर्थिक विकास की निम्न दर (प्रति व्यक्ति) जैसी समस्याओं का सामना किया है। 1951 में देश की 53 प्रतिशत आबादी (20 करोड़ लोग) गरीबी रेखा से नीचे रहने को विवश थे। भारत एक निम्न आबादी वाला देश माना जाता था। आजादी के बाद के दौर में मिश्रित अर्थव्यवस्था स्वीकार की गई जहां समाजवादी अवधारणा प्रबल थी। अनेक प्रकार की योजनाओं और नीतिगत उपायों के बाद, जिनमें से कुछ गंभीर संकट के कारण स्वीकृत किए गए थे, भारत बीसवीं सदी के प्रारंभ में एक महत्वपूर्ण और उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। तत्पश्चात् 2015 के बाद से भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती विकास अर्थव्यवस्था बना है। यहां संशोधित और उच्च मानकों के बावजूद गरीबी का स्तर कम हुआ है। अब देश की 30 प्रतिशत आबादी निर्धन है। अगले 5 वर्षों में देश की वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत से भी अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

वैसे भारत के विकास की कहानी बहुत रोचक है और आर्थिक इतिहास अप्रत्याशित रहा है। एक समय वह भी था जब देश के विकास में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कम थी और सेवा क्षेत्र की अधिक। दूसरी तरफ उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 25 प्रतिशत के

साथ स्थिर बनी हुई थी। विकास की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण था कि औद्योगिक आधार मजबूत किया जाए। इसलिए प्रधानमंत्री ने मई, 2014 में पद ग्रहण करने के तत्काल बाद *मेक इन इंडिया* अभियान का शुभारंभ किया।

विकास दर हासिल करने और औद्योगिक आधार सुनिश्चित करने के लिए अन्य कारकों के अतिरिक्त वित्त की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। विकास के प्रारंभिक चरणों में बैंकिंग प्रणाली उल्लेखनीय भूमिका निभाती है इसलिए न केवल बैंकिंग संस्थाओं का एक नेटवर्क स्थापित किया गया बल्कि यह सुनिश्चित भी किया गया कि बैंकिंग प्रणाली की पैठ बने और उन लोगों को वित्तीय संसाधन आसानी से उपलब्ध हों जिन्हें उनकी जरूरत है। फिर वित्तीय संसाधनों के अतिरिक्त एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है जिसमें कारोबार करना सहज हो और जहां जरूरत हो, वहां हैंड होल्डिंग भी उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री की जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत बैंक खातों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद सरकार ने क्रमिक ढंग से मुद्रा बैंक, स्टार्ट अप और स्टैंड अप, अटल नवाचार मिशन जैसी योजनाओं की घोषणा की।

यह समझना भी जरूरी है कि हालांकि भारत दुनिया में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है और यहां की जनसंख्या में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी उनका पूरी तरह से दोहन अभी नहीं किया गया है। भारत को अगले एक दशक में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के 11 करोड़ अवसर पैदा करने की जरूरत है क्योंकि देश की लगभग दो तिहाई जनसंख्या तब तक श्रमशील आयु वर्ग में

लेखक आईआईएम बंगलुरु में इकोनॉमिक्स के आरबीआई चेर प्रोफेसर हैं। इससे पहले वाशिंगटन स्थित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में वरिष्ठ अर्थशास्त्री के तौर पर कार्य कर चुके हैं। ईमेल: charansingh60@gmail.com

पहुंच जाएगी। भारत की श्रमशक्ति 2022 तक एक अरब तक हो जाएगी। इसलिए बेरोजगारी के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की सामाजिक अशांति से बचने के लिए यह जरूरी है कि लोगों के लिए रोजगार सृजित किए जाएं। आजादी के बाद के नियोजन के प्रारंभिक वर्षों में सरकार मुख्य रूप से बढ़ती श्रम शक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन बाद के वर्षों में निजी क्षेत्र ने भी योगदान देना प्रारंभ किया। फिर भी 2012 तक देश की 90 प्रतिशत श्रमशक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत थी। भविष्य में सालाना लगभग 1.11 करोड़ नौकरियां देने के लिए रोजगार सृजन करने वालों और उद्यमियों की भी जरूरत होगी। सिर्फ रोजगार तलाश करने वालों से काम नहीं चलेगा।

बैंकों की भूमिका

स्थिर विकास सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग में मजबूत वित्तीय प्रणाली जरूरी है। जिससे उत्पादक निवेश के साथ बचतकर्ताओं से निवेशकों तक संसाधनों का कारगर आवंटन प्रभावकारी हो। बैंक दरअसल एक एसेट ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं जहां एक जमाकर्ता संसाधनों को बैंक में जमा करता है और बैंक बदले में बाजार को उधार देता है। बैंक अर्थव्यवस्था में गरीबी कम करने का काम भी करते हैं। विकास को सहज बनाते हैं और वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करते हैं। इस प्रकार की वित्तीय प्रणाली से आय असमानता कम होती है क्योंकि इसके तहत पूंजी का प्रवाह उन उद्यमियों तक होता है जिनके पास धन का अभाव होता है।

बैंकिंग की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जुलाई, 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सरकार को यह आशंका थी कि देश की बैंकिंग परिसंपत्तियों पर कुछ व्यावसायिक घरानों का नियंत्रण हो सकता है। साथ ही बैंकों के माध्यम से सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक विकास हासिल करना था। इसलिए सरकार ने पहले 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों और फिर 1980 में 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसके बाद से भारत की बैंकिंग प्रणाली में रचनात्मक परिवर्तन आया। सरकार कृषि क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्यमों को कारोबार के

लिए ऋण उपलब्ध कराने लगी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा समाज के वंचित समूहों को बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराई गईं। 2011 की जनगणना से स्पष्ट होता है कि देश में 24.7 करोड़ परिवारों में से केवल 14.5 करोड़ परिवारों (58.7 प्रतिशत) की पहुंच बैंकिंग सेवाओं तक है। ग्रामीण क्षेत्रों में 16.9 करोड़ परिवारों में से केवल 8.1 करोड़ परिवार (54.5 प्रतिशत) ही बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा पाते हैं।

अगस्त 2014 में सरकार ने पीएमजेडीवाई का शुभारंभ किया जिसका उद्देश्य वित्तीय सेवाओं जैसे बैंकिंग और जमा खाता, प्रेषण, ऋण, बीमा और किराये की तरिके से पेंशन तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित हो। पीएमजेडीवाई के तहत 27 अप्रैल, 2016 तक 21.7 करोड़

बैंकिंग की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जुलाई, 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सरकार को यह आशंका थी कि देश की बैंकिंग परिसंपत्तियों पर कुछ व्यावसायिक घरानों का नियंत्रण हो सकता है। साथ ही बैंकों के माध्यम से सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक विकास हासिल करना था। इसलिए सरकार ने पहले 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों और फिर 1980 में 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया।

खाते खोले जा चुके हैं जोकि 31 मार्च, 2014 तक सभी वाणिज्यिक बैंकों में 122 करोड़ मौजूदा खातों की तुलना में एक लंबी छलांग कही जा सकती है। यह भी उल्लेखनीय है कि 17.9 करोड़ खातों को रुपये कार्ड जारी किए गए हैं, जबकि 9.7 करोड़ खाते आधार से जोड़े गए हैं और इनमें 83.6 प्रतिशत परिचालित भी हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20.12 करोड़ खाते हैं जिनमें से 9.8 करोड़ खाते ग्रामीण इलाकों में हैं। सबसे अधिक खाते उत्तर प्रदेश (3.3 करोड़) में खोले गए हैं। इसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल का दूसरा स्थान है। इनमें से प्रत्येक राज्य में 2 करोड़ खाते खोले गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पहल के बाद 95 प्रतिशत से अधिक परिवारों की पहुंच बैंकिंग सुविधाओं तक हुई है।

पीएमजेडीवाई को जैम ट्रिनिटी यानी अर्थात जन धन योजना-आधार-मोबाइल नंबर में भी शामिल किया गया है जिसके केंद्र में एक लक्षित तरीके से गरीब परिवारों को सहायता प्रदान करना है। जाम के तहत तकनीकी विकास और प्रक्रियाओं के मानकीकरण के जरिए बैंक शाखा तक बिना जाए भी मोबाइल फोन की मदद से बैंकिंग सेवा प्राप्त की जा सकती है। यहां तक कि ऋण भी हासिल किया जा सकता है।

मुद्रा बैंक और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

8 अप्रैल, 2015 को भारत सरकार ने सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा) बैंक की शुरुआत की जिसके केंद्र में छोटे उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराना है। देश में लगभग छह करोड़ उद्यमी मौजूद हैं जोकि व्यक्तिगत उद्यमी हैं और छोटी विनिर्माण इकाई चला रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं या सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इनमें से केवल 4 प्रतिशत को संस्थागत वित्त प्राप्त होता है। 10 लाख रुपये तक की वित्तीय जरूरतों वाली सूक्ष्म इकाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुद्रा बैंक इन इकाइयों के लिए नियामक और पुनर्वित्त संस्था के रूप में कार्य करेगा। साथ ही उन्हें विकसित होने में सहायता प्रदान करेगा। मुद्रा बैंक नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त ग्राहक संरक्षण सिद्धांतों को लागू करेगा जिससे लघु स्तर के उद्यम धोखा न खाएं और देश में प्रचलित मानक दरों से अधिक भुगतान न करें।

9 मई, 2015 को केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी तीन योजनाओं की शुरुआत की। अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना नामक इन योजनाओं को बैंकिंग खातों के माध्यम से संचालित किया जाता है। इन योजनाओं से बैंकिंग उद्योग में कारोबार बढ़ेगा और वित्तीय समावेशन वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक बनेगा।

स्टैंड अप और स्टार्ट अप

प्रधानमंत्री ने इस वर्ष अप्रैल में समाज के विशेष रूप से वंचित वर्गों और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए स्टैंड अप कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय

बजट में सरकार ने देश में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने और सशक्त करने के लिए कई उपाय किए जैसे संसाधनों का आवंटन, कौशल कार्यक्रमों का प्रारंभ, कर रियायतें प्रदान करना और कारोबार करना सुविधाजनक बनाना। बजट घोषणाओं और तत्पश्चात प्रारंभ की गई योजनाओं का उद्देश्य जनवरी में शुरू किए गए स्टार्ट अप को मजबूती प्रदान करना है, जिससे देश में रोजगार सृजन की गति मिले।

चुनौतियां

सरकार के प्रयासों के परिणाम नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी अनेक चुनौतियां हैं। वित्त तक सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करते हुए उच्च विकास दर हासिल करने हेतु इन चुनौतियों से निपटना भी जरूरी है।

ब्याज दर का मुद्दा

यह समझना जरूरी है कि हालांकि साहूकार मोटा ब्याज वसूलते हैं लेकिन फिर भी उधार लेने वाले वाणिज्यिक बैंकों की अनदेखी करते हुए उन्हीं के पास जाते हैं, भले ही बैंक उनके कितने ही पास क्यों न हो। इसलिए इस बात पर अध्ययन किया जाना चाहिए कि अधिक ब्याज लेने के बावजूद साहूकारों का धंधा फलता-फूलता कैसे है। इसका मतलब यह भी है कि उधार लेने के फैसले को ब्याज दरें प्रभावित नहीं करती। जैसा कि साहित्यिक प्रमाण बताते हैं कि चाणक्य की ब्याज दर संरचना जोखिम भरी थी और ब्याज की दर उधारकर्ता के कारोबार में शामिल जोखिम के साथ बढ़ती थी। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में सामान्य अग्रिम के लिए प्रति वर्ष 15 प्रतिशत का ब्याज लिया जाता था लेकिन व्यापारियों को दिए गए उधार का ब्याज 60 प्रतिशत होता था। अगर माल को जंगल से ले जाया जाता था तो व्यापारियों को 120 प्रतिशत ब्याज देना होता था। जबकि आयात-निर्यात करने वाले व्यापारियों को सालाना 240 प्रतिशत ब्याज चुकाना पड़ता था।

वित्तीय समावेश

पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए नए खातों के परिचालन को सुधारने और लेन-देन बढ़ाने हेतु आत्मविश्वास बढ़ाने तथा बैंकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं जिससे माहौल में भी सुधार हो। निम्न आय या परिसंपत्ति की होल्डिंग, वित्तीय

उत्पादों के संबंध में जागरूकता की कमी, लेन-देन की उच्च लागत, असुविधाजनक उत्पाद जिनका वहन नहीं किया जा सकता या जो लचीले नहीं हैं, जोकि ग्रामीण और बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों के अनुसार नहीं हैं, जैसे कारक वित्तीय व्यवस्था की पहुंच को बढ़ाने में बाधक होते हैं।

बैंकिंग सुविधा को ग्रामीण और वंचित लोगों तक पहुंचाने के लिए अधिक एटीएम लगाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए साहूकार कम से कम दूरी पर होते हैं लेकिन बैंकों तक पहुंचने में समय लगता है। देश में 6 लाख गांवों में सिर्फ 50,000 गांवों में ही किसी बैंक की शाखा है।

अगस्त 2014 में सरकार ने पीएमजेडीवाई का शुभारंभ किया जिसका उद्देश्य वित्तीय सेवाओं जैसे बैंकिंग और जमा खाता, प्रेषण, ऋण, बीमा और किराये की तरिके से पेंशन तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित हो। पीएमजेडीवाई के तहत 27 अप्रैल, 2016 तक 21.7 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं जोकि 31 मार्च, 2014 तक सभी वाणिज्यिक बैंकों में 122 करोड़ मौजूदा खातों की तुलना में एक लंबी छलांग कही जा सकती है।

मुद्रा बैंक

सूक्ष्म उद्यमियों को ऋण देने के लिए, विशेषकर उन गतिविधियों के लिए जो मुद्रा बैंक के तहत आती हैं, वाणिज्यिक बैंकों को अपनी सोच में बदलाव करने की जरूरत होगी। इसके लिए यह जरूरी है कि बैंक सूक्ष्म इकाइयों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनें और इस क्षेत्र को ऋण देने हेतु अनुकूल माहौल बनाया जाए।

स्टैंड अप और स्टार्ट अप

इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए जिसमें उद्यमियों का सृजन हो। भारत को अब उद्यमशीलता के लिए विश्व स्तरीय संस्थानों और पाठ्यक्रमों पर विचार करने की जरूरत है: संभवतः आईआईटी, आईएमएम और कृषि विश्वविद्यालयों की तर्ज पर भारतीय उद्यमशीलता संस्थान की स्थापना करने की

आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा नीति को देश में अधिक विश्वस्तरीय कॉलेजों की स्थापना पर जोर देना चाहिए जो वाणिज्य, विधि और बिजनेस स्टडीज में विशेषज्ञता प्राप्त हों।

देश में रोजगारपरक श्रम की कमी के मुद्दे पर भी तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार के अपने विश्लेषण के अनुसार, विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा कॉलेजों से सालाना ग्रेजुएट होने वाले 120 लाख विद्यार्थियों में से सिर्फ 10 प्रतिशत में श्रमशक्ति में शामिल होने लायक दक्षता होती है।


वैसे परिवार के सदस्य, मित्र और यहां तक कि शिक्षक भी उद्यमशीलता में जोखिम और संदेह को लेकर चिंतित रहते हैं। इसके अलावा, भारतीय मूल्य ऐसे हैं कि इसमें नाकामी के प्रति सहनशीलता न के बराबर है। दूसरी ओर सिलिकॉन वैली में निवेशक ऐसे उद्यमियों की मदद करने के अधिक इच्छुक रहते हैं जो अपने पहले प्रयास में, और यहां तक कि कम से कम दो बार असफल रहे हों। जोखिम झेलने के लिए एक फॉलबैक व्यवस्था जरूरी है इसलिए सरकार को असफल रहने वाले उद्यमियों को किसी किस्म की सामाजिक सुरक्षा या बीमा प्रदान करने पर विचार करना चाहिए।

उद्यमियों की सफलता के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु, सरकारी मंजूरीयों में विलंब नहीं होना चाहिए। 1982 से मौजूदा 110 इनक्यूबेटर्स के साथ, सालाना केवल 500 स्टार्ट अप्स को बढ़ावा दिया गया और तब से केवल 40,000 तकनीकी नौकरियों का सृजन हो पाया है और अंततः उद्यमशीलता को पोषित करने के लिए मेंटरशिप प्रदान की जानी चाहिए। सरकार को कृषि के ही समान, टेलीविजन और रेडियो पर चैनल शुरू करने पर विचार करना चाहिए जिससे अनुभवों को साझा किया जा सके।


निष्कर्ष

भारत एक बड़ी युवा आबादी वाला देश है जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है। यहां के लोगों का लाभ तभी उठाया जा सकता है, जब विकास के लिए पर्याप्त अवसर होंगे। पिछले दो वर्षों में सरकार ने बैंकिंग सुविधाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए न केवल प्रयास किए हैं बल्कि स्वरोजगार और विकास के लिए अनुकूल माहौल भी बनाने का प्रयास किया है। □





40 Centres in 10 States - The 'DHYEYA' Truly All India



विगत 15 वर्षों से सर्वाधिक विश्वसनीय एवं सर्वोत्कृष्ट संस्थान जो सामान्य अध्ययन के 50 से भी अधिक समर्पित एवं अनुभवी विशेषज्ञों का भारत में सबसे बड़ा नेटवर्क

OUR MENTORS

GENERAL STUDIES	HISTORY & CULTURE	GEOGRAPHY	ECONOMY	SCIENCE & TECHNOLOGY	POLITY & GOVERNANCE	INTERNATIONAL RELATIONS
	Vinay Singh Sujeet Singh Vijay Ved Javed Haque Tarique Khan Waris Siddiqui	Sanjeev Sharma Sanjay Singh Apurva Mehrotra Sikander Khan Divyavadan Singh	Vinay Singh S. K. Jha Kumar Amit Zulfiqar Ahmad Kumar Sarvesh	Q. H. Khan Javed Haque Ayaz Khan Ritesh Jaiswal	Vinay Singh Dr. M. Kumar V. K. Tripathi Kumud Ranjan Kumar Sarvesh S. P. Singh Jay Singh Bharat Singh Kumar Vineet	Vinay Singh Ayaz Khan Dr. Jitendra Srivastava Kumar Sarvesh Bharat Singh
	SOCIAL ISSUES & SOCIAL JUSTICE	ECOLOGY, ENVIRONMENT & DISASTER MANAGEMENT	INTERNAL SECURITY	ETHICS, INTEGRITY & APTITUDE	CURRENT AFFAIRS	CSAT
Kumar Amit Sweta Singh	Sanjeev Sharma Sanjay Singh Apurva Mehrotra Sikander Khan Divyavadan Singh	Vinay Singh Ayaz Khan Bharat Singh	Vinay Singh Sanjeev Kumar T. Dwivedi Jay Singh Bharat Singh and Experts From IIPA & DU	Dhyeya Team	Mukesh Kumar Sweta Singh Ather Abbasi Javed Ahmed Prof. Usmani Jay Singh Ahim Rashmi	

वैकल्पिक विषय (हिन्दी माध्यम)

हिन्दी साहित्य - कुमार सर्वेश
समाजशास्त्र - कुमार अमित
लोक प्रशासन - जय सिंह

भूगोल - संजीव शर्मा एवं संजय सिंह
राजनीति विज्ञान - डॉ. जितेन्द्र श्रीवास्तव
इतिहास - सुजीत सिंह, विजय वेद, जावेद हक

समाज कार्य - कुमार अमित
रक्षा अध्ययन - डॉ. जितेन्द्र श्रीवास्तव

Announcement of New Batches for Session 2016-17

हिन्दी माध्यम

उत्तरी दिल्ली (मुखर्जी नगर)	पूर्वी दिल्ली (लक्ष्मी नगर)	इलाहाबाद	लखनऊ
<p>सामान्य अध्ययन</p> <p>PREMIUM BATCH Pre-cum-mains</p> <p>23rd May at 8:00 am</p> <p>TARGET PRELIMS 2016 45 Days Crash Course</p> <p>23rd May at 1:30 pm</p> <p>वैकल्पिक विषय ● हिन्दी साहित्य ● इतिहास ● भूगोल जून 2016 के द्वितीय सप्ताह से बैच प्रारंभ</p>	<p>सामान्य अध्ययन</p> <p>PREMIUM BATCH Pre-cum-mains</p> <p>REGULAR BATCH 1st Week of June at 8:00 am</p> <p>WEEKEND BATCH 21st May at 11:00 am</p>	<p>सामान्य अध्ययन</p> <p>FOUNDATION 27th May at 5:30 pm 3rd June at 8:00 am 29th July at 2:30 pm</p> <p>MAINS BATCH 20th May at 8:00 am</p> <p>PREMIUM BATCH Pre-cum-mains</p> <p>REGULAR BATCH WEEKEND BATCH 27th May at 2:30 pm 21st May at 4:00 pm 29th July at 8:00 am</p> <p>GS UP FOCUSED BATCH 10th June at 5:30 pm</p> <p>वैकल्पिक विषय ● समाजशास्त्र ● इतिहास ● भूगोल ● समाज कार्य ● लोक प्रशासन ● राजनीति विज्ञान ● रक्षा अध्ययन जून 2016 के द्वितीय सप्ताह से बैच प्रारंभ</p>	<p>सामान्य अध्ययन</p> <p>PREMIUM BATCH Pre-cum-mains</p> <p>27th May at 9:00 am & 27th May at 5:30 pm</p> <p>वैकल्पिक विषय ● इतिहास ● भूगोल ● समाजशास्त्र ● समाज कार्य ● रक्षा अध्ययन जून 2016 के द्वितीय सप्ताह से बैच प्रारंभ</p>

COMPREHENSIVE ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES PROGRAM-2016

PHASE - 3rd
22nd May at 12 pm - 2 pm

*Take Admission
Feel the Difference*

FACE-TO-FACE CENTRES	VSAT CENTRES
<ul style="list-style-type: none"> ● NORTH DELHI : A 12-13, Ansal Building, 201, 11nd Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9 Ph.: 011-47354625 / 09540062643 ● EAST DELHI : 1/3 11rd Floor, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi Ph.: 011-43012556 / 09311969232 ● ALLAHABAD : 11nd & 11rd Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Allahabad-211001 Ph.: 0532-2260189 / 08853467068 ● LUCKNOW : A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow (UP) Ph. : 0522-4025825 / 09506256789 	<ul style="list-style-type: none"> ● BIHAR: PATNA - 7549106424, CHATISGARH: BILASPUR - 9424124434, DELHI & NCR: FARIDABAD-9582698964, LAXMI NAGAR-9311969232, HARYANA: SIRSA-9255464644, KURUKSHETRA - 8607221300, JHARKAND: DHANBAD - 9973401444, MADHYA PRADESH: JABALPUR - 9993681988, REWA - 9926207755, SINGRAULI - 9589913433, PUNJAB: AMRITSAR - 737828266, CHANDIGARH - 9872038899, PATIALA - 9041030070, RAJASTHAN: ALWAR - 9024610363, JODHPUR - 9782006311, SIKAR - 9672980807, UTTAR PRADESH: BAHAIRCH - 8874572542, BAREILLY - 7409878310, GORAKHPUR - 9236747474, JHANSI - 8874693999, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7570009004, LUCKNOW (GOMTI NAGAR) - 7570009003, MORADABAD - 9927622221, SAHARANPUR-9568859300, WEST BENGAL: KOLKATA-8335054687

FOR DETAILS VISIT US ON WWW.DHYEYAIAS.COM OR SEND 'DHY' AT 52424 OR CALL ON 9205274741 / 42 / 43

कृषि और किसानों का कल्याण: वर्तमान परिदृश्य

जे पी मिश्र



कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का विशालतम क्षेत्र है। इस क्षेत्र ने वर्ष 2014-15 में समग्र सकल मूल्य वर्धन में 16.1 प्रतिशत (नई श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के मूल्यों पर आधारित) योगदान दिया था। आर्थिक संकेतकों के अतिरिक्त, यह क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा के लिए खाद्य और पोषण तथा रोजगार के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो वह विशाल जनसंख्या और ग्रामीण श्रम शक्ति को उपलब्ध कराता है। इस क्षेत्र में रोजगार से जुड़े श्रम बल के अंश में वर्ष 1993-94 में 64.8 प्रतिशत से लेकर वर्ष 2011-12 में 48.9 प्रतिशत तक की कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद यह विशाल संख्या में लोगों को रोजगार देता है, हालांकि औद्योगिक और सेवा जैसे अन्य क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की तुलना में कृषि क्षेत्र से होने वाली आमदनी बहुत कम है

कि

सानों और कृषि क्षेत्र को अक्सर उत्पादन से संबंधित बदलावों और मूल्य की अस्थिरता जैसी समस्याओं से दो-चार होना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाली मौसम की असामान्यताएं बढ़ रही हैं और मौसम की असामान्य स्थितियों के कारण अक्सर सामान्य संस्थागत सहायता अपर्याप्त और कम पड़ जाती है। भारत में मौसम की ऐसी असामान्य स्थितियां बढ़ रही हैं और इनकी वजह से लाखों किसान परिवारों के कल्याण के लिए मजबूत प्रयास किया जाना बेहद आवश्यक हो गया है। किसानों के कल्याण के मामले पर आगे बढ़ने से पहले कई पहलुओं पर गौर किया जाना आवश्यक है। जब किसानों के कल्याण के उपाय सही दिशा में बढ़ेंगे, तो उनके साथ ही साथ औद्योगिकीय सुधारों और प्रौद्योगिकी के सृजन और उसके हस्तांतरण के उपायों को भी साथ लेकर चलना होगा, ताकि किसानों को ज्यादा आमदनी उपलब्ध कराई जा सके और साथ ही साथ अनाज और अन्य जिनसे भी बढ़ती मांग पूरी की जा सके। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 तक अनाज की अनुमानित मांग 277 मिलियन और तिलहनों की मांग 71 मिलियन तक पहुंच जाएगी। यूं तो अनाज और खाद्यान्न में वृद्धि की मौजूदा स्थिति के साथ इस मांग के पूरा हो जाने की संभावना है, लेकिन दलहन में कुछ कमी और सब्जियों/खाद्य तेलों में बेतहाशा कमी होने का अंदेशा है, जहां घरेलू खपत से जुड़ी करीब 60 प्रतिशत जरूरतें आयात के माध्यम से पूरी होती हैं।

उत्पादकता बढ़ाने, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने और कृषि संबंधी दक्षता व व्यवसायिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए बाजार तथा भूमि से संबंधित आवश्यक सुधारों द्वारा समुचित रूप से समर्थित उपायों से कृषि संबंधी विपदा से निपटने के लिए विकास के सम्मिलित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जोखिम में कमी लाने और विविध गतिविधियों द्वारा जोखिम में कमी और अनुकूलन और आमदनी में वृद्धि के लिए किसानों को सहायता देने सहित पूर्वी राज्यों को वैकल्पिक अनाज के कटोरे के रूप में विकसित करने के लिए संस्थाओं और डिलिवरी सिस्टम्स स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिए जाने की भी आवश्यकता है। कृषक कल्याण सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का आधार रहा है। सरकार ने किसानों की समस्याओं का निराकरण करने और उनके कल्याण के लिए कई नवाचार और नए दृष्टिकोण वाले समाधान प्रारंभ किए हैं। एक ओर जहां इनमें सिंचाई के अंतर्गत अधिक क्षेत्रफल और अच्छी इनपुट की उपलब्धता संबंधी सहायता देना शामिल है, वहीं दूसरी ओर, फसल बीमा, राष्ट्रीय कृषि मंडी और मूल्य स्थिरता जैसे प्रोत्साहनों के जरिए किसानों को फसल नाकाम रहने और मूल्य अस्थिरता के जोखिमों के विपरीत अधिकार सम्पन्न बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। उच्च मूल्य वाली ऑर्गेनिक खेती, परंपरागत खेती और मवेशी तथा मत्स्यपालन सहित खेतीबाड़ी की विविधता सरकार के शीर्ष एजेंडे पर हैं। इसके अलावा, किसानों को नवीनतम प्रौद्योगिकियों और विपणन के

लेखक भारत सरकार के नीति आयोग में सलाहकार (कृषि) हैं। वह कृषि-विज्ञानी हैं और कृषि शोध व विकास में दो दशक से अधिक समय से कार्यरत हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी अग्रणी योजनाओं के साथ काम कर चुके हैं। संप्रति कृषि विकास पर नीति आयोग के कार्यबल से जुड़े हैं तथा लैंड लीजिंग पर विशेषज्ञ समूह के सदस्य समन्वयक भी हैं। ईमेल: mishrajp@gmail.com

अवसरों से अवगत कराने के लिए कृषि के समस्त पहलुओं के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान करने का कार्य एक समर्पित टीवी चैनल डीडी किसान के माध्यम से किया जा रहा है। पिछले दो वर्षों में अनेक चुनौतियों से निपटने और देश के लाखों किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं और कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है:

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

देश में, जहां बुवाई वाले क्षेत्र के 55 प्रतिशत हिस्से में पानी की किल्लत हो, वहां किसानों का कल्याण केवल हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल के माध्यम से ही संभव है। हाल ही में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने इसे सही संभावनाओं के साथ प्रस्तुत किया है, जिसमें जल भंडारण और उसके दक्ष उपयोग में वृद्धि के साथ-साथ सुगमता से किए जाने वाले कार्यों पर ज्यादा बल दिया गया है। पीएमकेएसवाई को मिशन मोड में कार्यान्वित करते हुए 28.5 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के दायरे में लाया जाएगा। वर्ष 2015-16 में त्वरित सिंचाई लाभ योजना (एआईबीपी) और पीएमकेएसवाई-हर खेत को पानी के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में 2510 करोड़ रुपये के पूरक अनुदान सहित पीएमकेएसवाई के लिए 4510 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2016-17 के केंद्रीय बजट में पीएमकेएसवाई के लिए प्राथमिकता निर्धारित की गई है। 80.6 लाख हैक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई के लिए ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत अब तक सुस्त पड़ी 89 सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के काम में तेजी लाई जाएगी। प्रस्तावित धनराशि की आवश्यकता अगले साल 17000 करोड़ रुपये और अगले पांच वर्षों में 86,500 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। 31 मार्च 2017 से पहले इनमें से 23 परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 20000 करोड़ रुपये की शुरुआती राशि के साथ नाबार्ड में एक समर्पित दीर्घकालिक सिंचाई कोष की परिकल्पना की गई है। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, बजटीय सहायता तथा बाजार ऋण के जरिए वर्ष

2016-17 में कुल 12517 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

बहुत से राज्यों ने जल संरक्षण और फसल कटाई के लिए नवाचार अभ्यास प्रारंभ किए हैं। महाराष्ट्र ने जलयुक्त शिवार योजना शुरू की है, जिसमें जलाशय बनवाने और बहाल करने पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के माध्यम से धनराशि व्यवस्था की जाएगी। कर्नाटक सरकार ने सूक्ष्म-सिंचाई पर मिलने वाली केंद्रीय सब्सिडी में और राशि जोड़ते हुए पर इसे बढ़ा दिया है, ताकि इसका शत-प्रतिशत उपयोग ड्रिप और स्पिंकल प्रणालियों में किया जा सके। गुजरात सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई के लिए किसानों की सहायता से जुड़ी अनोखी व्यवस्था को संस्थागत रूप प्रदान किया है। गुजरात हरित क्रांति निगम, केंद्र से धनराशि प्राप्त करता है और उसके बाद शुरुआती तीन वर्षों के रखरखाव के लिए साथ मिलकर सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। राजस्थान ने नहर के कमान क्षेत्रों में डिग्गी-कम-स्पिंकलर व्यवस्था का कार्यान्वयन किया है, जहां नहर का बंद होना और टूटना तथा पानी की कम आपूर्ति होना सामान्य बात है। अन्य राज्यों ने भी जल संरक्षण, जल संचयन और जल के दक्ष उपयोग के लिए बहुत से नवीनतम जल-सकारात्मक और मिश्रित तरीके लागू किए हैं।

प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) के स्थान पर खरीफ मौसम 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन किया गया है। एनएआईएस/एमएनएआईएस में जो प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं, उनमें देशभर में फसलों/क्षेत्रफल के लिए वास्तविक प्रीमियम में किसानों के अंश को तर्कसंगत बनाया गया है और उन्हें घटाकर खरीफ की अनाज, दलहन एवं तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि की 2 प्रतिशत तक, रबी की अनाज, दलहन एवं तिलहन फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत तक और खरीफ एवं रबी सालाना व्यवसायिक/वार्षिक बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत अधिकतम सीमा तक किया जाना शामिल है। वर्ष 2016-17 के लिए 5,500 करोड़ रुपये का परिच्यय उपलब्ध कराया गया है।

राज्यों से इस योजना को खरीफ 2016 के आरंभ में लागू करने का अनुरोध किया गया है। यह योजना उन किसानों को अपार राहत प्रदान करेगी, जिनकी फसलों की पैदावार पर अक्सर प्राकृतिक आपदाओं के खतरे का साया मंडराता रहता है।

सॉइल हेल्थ कार्ड योजना

हरित क्रांति के प्रारंभ के साथ ही, भारत में उर्वरकों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा, लेकिन इससे बेहिसाब यूरिया को प्रमुखता मिली। 1970 के दशक के आरंभ में नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटैश का औसत अनुपात 6:1.9:1 था 1996 में इसका पलड़ा नाइट्रोजन के पक्ष में झुक गया यह अनुपात 10:2.9:1 तक पहुंच गया। उसके उपरांत वर्ष 2012-13 में विपरीत दिशा में मामूली बदलाव आया, लेकिन यह अनुपात 8.2:3.2:1 पर बरकरार है। सामान्य धरणा है कि भारतीय किसान यूरिया का बहुत अधिक उपयोग करते हैं लेकिन उपरोक्त तथ्य दर्शाते हैं कि यह भी बहुत एकांगी दृष्टिकोण है। मृदा और फसल के प्रकार तथा सिंचित बनाम वर्षा सिंचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है। किसानों को उनके खेत के पोषण के स्तर की जानकारी देने के लिए अब सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कार्यान्वित की जा रही है, ताकि वह उर्वरकों के उपयोग के बारे में ज्यादा समझदारी से निर्णय ले सकें। इस योजना के अंतर्गत मार्च 2017 तक समस्त 14 करोड़ खेतों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेशनल प्रॉजेक्ट ऑन सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (मृदा स्वास्थ्य एवं उत्पादकता से संबंधित राष्ट्रीय परियोजना) के लिए 368 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा अगले तीन वर्षों के दौरान उर्वरक बनाने वाली कंपनियों के मृदा और बीज परीक्षण सुविधाओं सहित 2000 मॉडल रिटेल आउटलेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

पूर्वोत्तर भारत में परंपरागत कृषि विकास योजना और ऑर्गेनिक खेती

वर्षा सिंचित क्षेत्रों जो देश की कृषि भूमि का लगभग 55 प्रतिशत हैं, में फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार ने दो महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की हैं। पहली,

‘परंपरागत कृषि विकास योजना’, जो अगले तीन वर्षों के दौरान पांच लाख हैक्टेयर भूमि को ऑर्गेनिक खेती के दायरे में लाएगी। दूसरी, “पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऑर्गेनिक मूल्य श्रृंखला विकास” (ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन) नामक मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) पर आधारित ऑर्गेनिक खेती योजना सरकार ने शुरू की है। इसमें मूल्य वर्धन पर

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) के स्थान पर खरीफ मौसम 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन किया गया है।

जोर दिया गया है, ताकि इन भागों में उगने वाले ऑर्गेनिक उत्पादों को घरेलू और विदेशी बाजार उपलब्ध हो सकें। इन योजनाओं के लिए कुल 412 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि मंडी (एनएएम)

कृषि उपज विपणन प्रणालियों को लेवी और मंडी करों की बहुत अधिक असंगतियों और विविधताओं का सामना करना पड़ता है। ये न तो पारदर्शी हैं और न ही सभी राज्यों में एक समान हैं और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य पाने में प्रमुख बाधा हैं। यहां तक कि राज्यों के भीतर भी कृषि संबंधी जिंसों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने पर गंभीर प्रतिबंध हैं। कर्नाटक द्वारा एक मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें राज्य सरकार की एजेंसी और एनसीडीईएक्स स्पॉट एक्सचेंज के संयुक्त उद्यम के साथ कई मंडियों को एकल लाइसेंसिंग सिस्टम में एक साथ जोड़ा गया है, जो स्वाचालित या ऑटोमेटिड नीलामी और नीलामी के बाद की सुविधाओं की पेशकश करता है। इस मॉडल को आधार के रूप में ग्रहण करते हुए, सरकार ने 200.00 करोड़ रुपये के बजट के साथ वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 के दौरान कार्यान्वयन के लिए हाल ही में एग्री-टैक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एटीआईएफ) के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि मंडी (एनएएम) नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। यह योजना कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के

अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन स्माल फार्मर्स एग्री-बिज़नेस कंसोर्टियम (एसएफएसी) के जरिए एनएएम के कार्यान्वयन की परिकल्पना करती है। एनएएम अखिल भारतीय इलैक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल के लिए संभावनाएं उपलब्ध कराती है, जो कृषि जिंसों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय मंडी बनाने के लिए चुनिंदा कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) के मंडी स्थलों का नेटवर्क तैयार करेगा। देश भर में राज्यों द्वारा अपने विपणन कानूनों में (1) राज्य भर में एकल लाइसेंस वैध बनाने, (2) एक ही स्थान पर बाजार शुल्क की वसूली और (3) मूल्य का पता लगाने के साधन के रूप में, इलैक्ट्रॉनिक नीलामी के प्रावधान से संबंधित पूर्व में किए गए सुधारों के आधार पर चुनिंदा 585 नियंत्रित थोक मंडियों में ई-प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा।

मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ)

मूल्य अस्थिरता एक प्रमुख आघात है, जिसका सामाना किसानों को खेती-बाड़ी में करना पड़ता है। अक्सर यह इतना कम होता है कि उत्पाद की बिक्री के सीजन में कभी भी लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता, जबकि खरीद के समय यह इतना महंगा होता है खरीदने की सामान्य क्षमता से बाहर हो जाता है। पीएसएफ की स्थापना खराब हो जाने वाली कृषि और बागवानी से संबंधित वस्तुओं की खरीद और वितरण के लिए की गई है। इस कोष का लक्ष्य कृषि और बागवानी से संबंधित खराब हो जाने वाली वस्तुओं की खरीद और वितरण तथा किसानों साथ ही साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कार्यशील पूंजी और अन्य लागत उपलब्ध कराना है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

कृषि क्षेत्र में मवेशी, सकल मूल्य के 25 प्रतिशत का योगदान देते हैं और लगभग 21 मिलियन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। यह कृषि में तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से है और यह क्षेत्र किसान को किसी भी प्रकार की विपदा से उबरने की ताकत और अतिरिक्त आमदनी उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन वर्ष 2014-15 में स्वदेशी प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रारंभ किया गया था। यह स्वदेशी प्रजातियों

के विकास के लिए मिशन एकीकृत मवेशी विकास केंद्रों, गोकुल ग्रामों की स्थापना की भी परिकल्पना करता है। इस मिशन के लिए वर्ष 2013-14 से वर्ष 2014-15 तक का परिव्यय 500 करोड़ रुपए था। इसके अलावा वर्ष 2015-16 के लिए स्वदेशी प्रजातियों के विकास के लिए 50.00 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई।

राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र

स्वदेशी प्रजातियों के विकास, रक्षण और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। स्वदेशी प्रजातियों को समग्र और वैज्ञानिक ढंग से विकास और रक्षण करने के लिए एक केंद्र उत्तर और दूसरा दक्षिण भारत में उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित किए जा रहे हैं। स्वदेशी गोजातीय प्रजातियों (39 गाय-बैल और 13 भैंस), मिथुन और याक का रक्षण और विकास उनकी उत्पादकता बढ़ाने और उनके जेनेटिक गुणों को उन्नत बनाने के लिए किया जाएगा। केंद्र, स्वदेशी जीवाणु-रोगाणु (जर्म-प्लाज्म) का संग्रह होने के साथ-साथ देश में प्रमाणित जीवाणु-रोगाणु स्रोत भी होगा। किसानों, ब्रीडरों और प्रजनन संगठनों को सर्वोकृष्ट प्रमाणित जीवाणु-रोगाणु

सरकार ने 200.00 करोड़ रुपये के बजट के साथ वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 के दौरान कार्यान्वयन के लिए हाल ही में एग्री-टैक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एटीआईएफ) के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि मंडी (एनएएम) नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। यह योजना कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन स्माल फार्मर्स एग्री-बिज़नेस कंसोर्टियम (एसएफएसी) के जरिए एनएएम के कार्यान्वयन की परिकल्पना करती है।

–स्वदेशी प्रजातियों के रखरखाव के लिए बैलों के रूप में कृत्रिम इन्सेमिनेशन और प्राकृतिक सेवा, बछिया, नर और मादा बछड़े, सीमन और भ्रूण उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें से प्रत्येक, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र हेतु क्रमशः मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश को 25.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(जारी ... पृष्ठ 20 पर)

सामान्य अध्ययन

अशोक सर के नेतृत्व में भारत के सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक एक मंच पर
30 वर्षों से भी अधिक समय से सिविल सेवा के
अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन का अनुभव



श्री अशोक सिंह

फाउंडेशन कोर्स

प्रत्येक माह नया बैच प्रारंभ

ICS की विशेषताएं

- ★ वरिष्ठ सिविल सेवकों और प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा नियमित अतिथि व्याख्यान
- ★ साप्ताहिक टेस्ट श्रृंखला
- ★ अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन एकाउंट
- ★ यूपीएससी के अद्यतन पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज

ICS
empowering nation
Institute for Civil Services

870, 1st floor, opposite Batra Cinema, Mukherjee Nagar, Delhi-09

☎ 011-45094922, 8750908822, 77 | www.icsias.com

अधिकतम शासन: ई-शासन के माध्यम से जनपहुंच

रंजीत मेहता



भारत में ई-गवर्नेंस की शुरुआत रक्षा सेवाओं, आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीय जनगणना, चुनाव, कर संग्रह, आदि के लिए कम्प्यूटरीकरण पर जोर के साथ 1960 के दशक के अंत में और 1970 के दशक के आरंभ में हुई। 1990 के दशक की शुरुआत में यह साकार होती दिखी लेकिन इसकी व्यापकता हाल के वर्षों में, खासकर, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत के बाद बढ़ी है और एक-एक नागरिक तक इसे पहुंचाने का प्रयास सफल होता दिख रहा है

ई गवर्नेंस, सरकार के भीतर, सरकार और राष्ट्रीय, राज्य, नगर निगम और स्थानीय स्तर की सरकारी एजेंसियों, नागरिक व व्यवसायों के बीच, दक्षता, प्रभावशीलता, पारदर्शिता और सूचना और व्यवहार की जवाबदेही के आदान-प्रदान में बदलाव के लिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। इसका उद्देश्य नागरिकों को सूचना तक पहुंच और उसके उपयोग के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना भी है।

ई-सरकार का उद्भव वेब जगत की सबसे मुख्य घटनाओं में से एक रहा है। चूंकि इंटरनेट ने डिजिटल समुदायों को विकसित होने और यह सोचने में कि वे वास्तव में देश (और विश्व) के आसपास के व्यक्तियों से जुड़ने में समर्थ हो रहे हैं, सहायता की है, इसने राष्ट्रीय सरकारों के लिए कई चुनौतियां और अवसर प्रस्तुत किए हैं। लोकतांत्रिक राज्यों में सरकारें मुख्य रूप से एक प्रतिनिधि तंत्र होती हैं जिसके तहत चयनित कुछ बहस होती हैं और राष्ट्र राज्य के नागरिकों की ओर से उनके लिए विधान अधिनियमित किए जाते हैं। इसके विभिन्न पहलू हैं, जो ई-गवर्नेंस के संदर्भ में महत्व रखते हैं।

सरकारों द्वारा आईटी को वृहत् रूप से अपनाने का वैश्विक रुझान वर्ल्ड वाइड वेब के आगमन के साथ नब्बे के दशक में उत्पन्न हुआ। तब से प्रौद्योगिकी के साथ ही ई-गवर्नेंस की पहलों ने एक लंबा सफर तय किया है। इंटरनेट और मोबाइल कनेक्शन में बढ़ोतरी के साथ नागरिक व्यापक तरीके से संपर्क साधने की अपनी नई विधा का दोहन करने की कला सीख रहे हैं। वे सरकार और कॉर्पोरेट जगत से

अधिक से अधिक सूचना और सेवा ऑनलाइन प्राप्त करने के प्रति उत्सुक हो रहे हैं। उनके स्थानीय तंत्र, व्यावसायिक और निजी जीवन में भी इसका दखल बढ़ रहा है, इस प्रकार पर्याप्त सबूत दर्शाते हैं कि ई-नागरिकता अपना प्रभाव जमा रही है।

भारत में ई-गवर्नेंस की शुरुआत रक्षा सेवाओं, आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीय जनगणना, चुनाव, कर संग्रह, आदि के लिए कम्प्यूटरीकरण पर जोर के साथ 60 के दशक के अंत में और 70 के दशक के आरंभ में हुई। हालांकि, 90 के दशक के आरंभ से, ई-गवर्नेंस ने एक व्यापक आयाम धारण किया। ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बनाने की नीति पर जोर देने के लिए और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) तथा निजी क्षेत्र से अधिक से अधिक आदानों को प्राप्त करने हेतु व्यापक क्षेत्रीय अनुप्रयोगों के लिए इसकी जोरदार आवश्यकता महसूस हुई। शुरुआत में जहां जोर स्वचालन और कम्प्यूटरीकरण पर था, बाद में संपर्क, नेटवर्किंग, जानकारी प्राप्त करने और सेवाओं के वितरण के लिए प्रणाली स्थापित करने, को भी इसमें तत्काल शामिल कर लिया गया। मई 2006 में राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) के कार्यान्वयन का उद्देश्य आम आदमी के लिए सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाने की दृष्टि से लोगों के अपने क्षेत्र में ही वहनीय दर पर संयुक्त सेवा वितरण दुकानों के जरिए सरकारी सेवा की दक्षता, पारदर्शिता और इस तरह की सेवाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना था।

एनईजीपी में वर्तमान में 27 मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) और 8 संपूरक

लेखक नयी दिल्ली स्थित पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के निदेशक हैं। साथ ही भारत सरकार की विभिन्न समितियों के सदस्य भी हैं। छह पुस्तकें और दर्जनों शोध-पत्र लिख चुके हैं। पत्र-पत्रिकाओं में नियमित लेखन। ईमेल: ranjeetmehta@gmail.com

घटकों को शामिल किया गया है, जिन्हें केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर की सरकारों के स्तर में लागू किया जाना है। इनके तहत केंद्रीय स्तर पर आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क और पासपोर्ट, राज्य स्तर पर भू-अभिलेख, कृषि और ई-जिला तथा स्थानीय स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं जैसी परियोजनाओं को शामिल किया गया है।

ऐसे उपभोक्ताओं के लिए जिनके पास आधार कार्ड नहीं था, एलपीजी सब्सिडी का लाभ लेना मुश्किल था। अब, जो उपभोक्ता इस योजना में शामिल होना चाहते हैं उन्हें या तो अपने बैंक खाते के साथ और एलपीजी उपभोक्ता खाते में अपना आधार संख्या जुड़वाना होगा या जिनके पास आधार संख्या नहीं है, वे अपने 17 अंकों की एलपीजी पहचान को सीधे अपने बैंक खाते से जोड़ना होगा।

सरकार में आईसीटी सेवाओं के प्रभावी उपयोग से मौजूदा क्षमता को बहुत बढ़ाया गया, संचार लागत में कमी आई और विभिन्न विभागों के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है। इसने नागरिकों को ठोस लाभ के लिए आसान पहुंच प्रदान किया है, फिर चाहे वह ऑनलाइन फार्म भरने, बिल प्रदान और भुगतान करने जैसे साधारण अनुप्रयोग हों या फिर दूरस्थ शिक्षा और दूर-चिकित्सा जैसे जटिल अनुप्रयोग हों। हाल ही में ई-गवर्नेंस में सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं:

पहल

पहल डीबीटीएल महत्वाकांक्षी योजना, रसोई गैस पर नकद सब्सिडी देने के उद्देश्य से पिछली सरकार द्वारा 1 जून, 2013 को शुरू की गई थी और इसमें 291 जिलों को कवर किया गया। वर्तमान सरकार ने व्यापक रूप से पहल योजना की जांच की और उपभोक्ताओं द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की समीक्षा करने के बाद इस योजना में सुधार किया गया और इसे फिर से 15 नवंबर, 2014 को शुरू किया। पहले चरण में इसके तहत 54 जिलों के 2.5 करोड़ परिवारों को कवर किया गया और देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए 1 जनवरी, 2015 को इस संशोधित योजना का दूसरा चरण शुरू हुआ। पिछली

योजना में एलपीजी सब्सिडी प्राप्त करने वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए आधार संख्या के लिए अनिवार्य था।

बहरहाल, ऐसे उपभोक्ताओं के लिए जिनके पास आधार कार्ड नहीं था, एलपीजी सब्सिडी का लाभ लेना मुश्किल था। अब, जो उपभोक्ता इस योजना में शामिल होना चाहते हैं उन्हें या तो अपने बैंक खाते के साथ और एलपीजी उपभोक्ता खाते में अपना आधार संख्या जुड़वाना होगा या जिनके पास आधार संख्या नहीं है, वे अपने 17 अंकों की एलपीजी पहचान को सीधे अपने बैंक खाते से जोड़ना होगा। एक बार इस योजना से उपभोक्ता के जुड़ जाने के बाद, उन्हें बाजार मूल्य पर सिलेंडर मिल जाएगा और उनके बैंक खाते में सीधे एलपीजी सब्सिडी पहुंच जाएगी। पहली बार इस योजना से जुड़ने वाले उपभोक्ता के खाते में 568 रुपये की राशि का अग्रिम में भुगतान किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि जब उपभोक्ता पहली बार सिलेंडर की बुकिंग करेगा, तब बाजार मूल्य पर सिलेंडर का भुगतान करने के लिए उसके पास अतिरिक्त पैसे होंगे। यह राशि प्रत्येक सिलेंडर पर किए जाने वाले सब्सिडी भुगतान के अतिरिक्त है।

योजना के तहत उपभोक्ताओं को उनकी स्थिति के बारे में सूचित रखने के लिए, उन्हें इस योजना में हर स्तर पर एसएमएस भेजा जाता है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सभी एलपीजी उपभोक्ताओं से यह आग्रह किया जाता है कि यदि उन्होंने अपने वितरक के पास अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं कराया है, तो यथाशीघ्र ऐसा करें। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि केवल कैश मेमो के साथ ही सिलेंडर प्राप्त करें ताकि अपनी सब्सिडी स्थानांतरण के संबंध में आश्वस्त हो सकें।

योजना के तहत देश के 676 जिलों में 15.3 करोड़ उपभोक्ताओं से ज्यादा को कवर किया जाएगा। वर्तमान में 6.5 करोड़ उपभोक्ताओं अर्थात् 43 प्रतिशत ने पहले से ही योजना में शामिल हो चुके हैं और अपने बैंक खाते में सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं।

डीबीटीएल को यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि लाभ वास्तविक घरेलू ग्राहक तक सीधे पहुंचे और कहीं बंटे नहीं। इस प्रक्रिया के माध्यम से जनता के पैसे

को बचाया जाएगा। सभी एलपीजी ग्राहकों से तुरंत ऊपर बताए गए योजना में शामिल होने का अनुरोध किया जा रहा है।

15 नवंबर, 2014 को इस योजना के शुभारंभ के बाद से 30 दिसंबर, 2014 तक 624 करोड़ रुपये की राशि 20 लाख से ज्यादा एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए स्थानांतरित कर दी गई। इस योजना में अगर कोई सब्सिडी नहीं चाहता है तो वह इसे स्वेच्छा से छोड़ सकता है। भारत सरकार ने मार्च 2015 में *गिव इट अप* अभियान शुरू किया था, अप्रैल 2016 तक लगभग एक करोड़ लोगों ने अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी, इनमें मध्यम वर्ग और सेवानिवृत्त लोग भी शामिल हैं।

डिजिटल इंडिया

डिजिटल इंडिया पहल, सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड और मोबाइल कनेक्टिविटी पर केंद्रित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में हो रही देरी को दूर करने के लिए एक पुनर्प्रयास है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), रेलटेल और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के माध्यम से प्रत्यक्ष खर्च सीमित हो जाएगा, लेकिन ग्रामीण भारत में बसने वाली 68 प्रतिशत आबादी में से ज्यादातर के ऑनलाइन हो जाने से अप्रत्यक्ष मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

डिजिटल इंडिया, एकल कार्यक्रम के तहत विभिन्न पहलों को समेटे हुए है, जिसमें प्रत्येक का लक्ष्य भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार करना और पूरी सरकार के संकेंद्रित और समन्वित प्रयास से नागरिकों के लिए सुशासन लाना है।

डिजिटल भारत कार्यक्रम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं, उत्पादों, विनिर्माण और रोजगार के अवसरों आदि के क्षेत्रों में समावेशी विकास पर लक्षित है। यह तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है-

- प्रत्येक नागरिक की उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसरचना
- मांग पर शासन और सेवाएं
- नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण

उपरोक्त लक्ष्यों के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ब्रॉडबैंड राजमार्ग, सार्वभौमिक

मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट जन पहुंच कार्यक्रम, ई-शासन: प्रौद्योगिकी की मदद से सरकार में सुधार लाना, ई क्रांति - सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण: कुल शून्य आयात, नौकरियां और शीघ्र उपज कार्यक्रमों के लिए

एक बार जब छोटे व्यवसायों को आईएसपी लाइसेंस मिलना शुरू हो जाए, यह आगे की प्रक्रिया को तीव्र कर देगा। उस स्तर को पाने में दो वर्ष का समय लग सकता है। एक आईएसपी, डिजिटल अवसंरचनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की तर्ज पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है।

आईटी प्रदान करने पर लक्षित है। डिजिटल इंडिया, एकल कार्यक्रम के तहत विभिन्न पहलों को समेटे हुए हैं, जिसमें प्रत्येक का लक्ष्य भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए तैयार करना और पूरी सरकार के संकेंद्रित और समन्वित प्रयास से नागरिकों के लिए सुशासन लाना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (डीईआईटीवाई) विभाग द्वारा विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के सहयोग से इस कार्यक्रम की परिकल्पना और समन्वित किया गया है। डिजिटल इंडिया पर निगरानी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, सभी मौजूदा और चल रही और ई-शासन पहलों का डिजिटल इंडिया के सिद्धांतों के साथ तालमेल करने के लिए पुनर्लान किया गया है।

डिजिटल इंडिया कई अवयवों से बना है, लेकिन सबसे बड़ा अवयव अंतिम मील तक कनेक्टिविटी है। जहां, सरकार सभी ग्राम पंचायतों और संयुक्त सेवा केंद्रों को फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से जोड़ने पर विचार कर रही है, जिसकी उन्हें जरूरत है।

सरकार ने नामित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी लाने के उद्देश्य से फाइबर ऑप्टिक्स बिछाने के लिए नियुक्त किया है। बहरहाल, इसका व्यापारिक हिस्सा अभी अस्पष्ट है। सरकार अब ऐसे उद्यमियों की तलाश में है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम मील तक कनेक्टिविटी पहुंचाने के लक्ष्य को पाने के लिए आईएसपी (इंटरनेट

सेवा प्रदाता) की स्थापना कर सके। एक बार जब छोटे व्यवसायों को आईएसपी लाइसेंस मिलना शुरू हो जाए, यह आगे की प्रक्रिया को तीव्र कर देगा। उस स्तर को पाने में दो वर्ष का समय लग सकता है। एक आईएसपी, डिजिटल अवसंरचनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की तर्ज पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है।

इस बीच, डिजिटल इंडिया पहल और भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से उत्साहित निजी क्षेत्र भारतीय कंपनियों द्वारा तकनीक खर्च के संबंध में आशान्वित है। भारत की प्रौद्योगिकी खरीद, जिसमें कंप्यूटर और परिधीय उपकरण, संचार उपकरण सॉफ्टवेयर, तकनीकी परामर्श सेवाएं, तकनीक आउटसोर्सिंग और हार्डवेयर रखरखाव शामिल हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 और 2017 में 12 प्रतिशत की दर से विकसित होगा।

प्रौद्योगिकी व्यय 2015 में 2.08 खरब रुपये से 2016 में 2.32 खरब रुपये और 2017 में 2.59 खरब रुपये तक पहुंच जाएगा। इस खर्च का एक तिहाई भाग हार्डवेयर पर खर्च होगा जो भारतीय कंपनियों के लिए खर्च का सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है। हालांकि, संचार उपकरण खर्च बाकी की तुलना में बहुत धीरे-धीरे बढ़ेगा क्योंकि बाजार परिपक्व होने के साथ ही कीमतों में गिरावट जारी है। डिजिटल इंडिया को आकर्षण मिलने और टेलीकॉम कंपनियों द्वारा 4जी जैसे नए और बेहतर संचार नेटवर्क लांच करने से भी यही होगा।

2014-15 में केंद्र सरकार ने शुरूआती दौर में फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से 100,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने की योजना बनाई, जिसे बाद में घटाकर 50,000 कर दिया गया। मार्च 2015 तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग केवल 20,000 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के तहत कवर किया गया था, जिसका बाद में नाम बदलकर भारतनेट कर दिया गया।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर, 2015 तक 32,272 ग्राम पंचायतों को 76,624 किमी फाइबर के साथ कवर किया गया था। भारतनेट परियोजना, सभी ग्रामीण घरों और संस्थानों के लिए 2 एमबीपीएस से 20 एमबीपीएस तक की सस्ती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की दिशा में वर्ष

2017 तक एक उत्कृष्ट नेटवर्क स्थापित करने पर लक्षित है।

डिजिटल इंडिया: प्रमुख परियोजनाएं

विभिन्न परियोजनाओं/उत्पादों को पहले से ही शुरू किया गया है या जो कुछ शुरू किए जाएंगे, निम्नलिखित हैं:

1. डिजिटल लॉकर प्रणाली: इसका उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करना और एजेंसियों के बीच ई-दस्तावेजों के आदान-प्रदान करने के लिए सक्षम प्रणाली स्थापित करना है। ई दस्तावेजों के आदान-प्रदान, पंजीकृत खजाने के माध्यम से किया जाएगा जिससे ऑनलाइन दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित हो सके।
2. शासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए MyGov.in को एक मंच के रूप में शुरू किया गया है। इसके लिए 'चर्चा (डिस्कस)', 'करना (डू)' और 'प्रसार (डिससेमिनेट)' का 3डी का रास्ता चुना गया है। उपयोगकर्ताओं के लिए मोबाइल पर इन सुविधाओं को MyGov मोबाइल ऐप के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा।
3. स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम): मोबाइल ऐप को स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आम लोगों और सरकारी संगठनों द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

दिसंबर, 2015 तक 32,272 ग्राम पंचायतों को 76,624 किमी फाइबर के साथ कवर किया गया। भारतनेट परियोजना, सभी ग्रामीण घरों और संस्थानों के लिए 2 एमबीपीएस से 20 एमबीपीएस तक की सस्ती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की दिशा में वर्ष 2017 तक एक स्केलेबल नेटवर्क स्थापित करने पर लक्षित है।

4. ई हस्ताक्षर फ्रेमवर्क के जरिए नागरिकों को आधार प्रमाणीकरण का उपयोग कर ऑनलाइन डिजिटल रूप में किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की अनुमति होगी।
5. ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (ओआरएस) को ई हॉस्पिटल एप्लिकेशन के तहत शुरू किया गया है। यह एप्लिकेशन ऑनलाइन

पंजीकरण, शुल्क का भुगतान और मिलने का समय, ऑनलाइन नैदानिक (क्लीनिकल) रिपोर्ट, रक्त उपलब्धता की ऑनलाइन पूछताछ आदि के रूप में महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है।

6. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल लाभार्थी तक भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने सभी छात्रवृत्तियों को प्रदान करने के लिए एकल खिड़की समाधान प्रदान करता है। यहां छात्र के आवेदन करने के साथ ही उसका सत्यापन, मंजूरी और लाभार्थी को भुगतान करने की सुविधा मौजूद है।
7. डीईआईटीवाई ने देश में बड़े पैमाने पर रिकॉर्डों के डिजिटलीकरण के लिए डिजिटाइज्ड इंडिया प्लेटफॉर्म (डीआईपी) नाम से एक पहल की शुरुआत की है। इससे नागरिकों को सेवाओं की कुशल वितरण की सुविधा उपलब्ध होगी।
8. भारत सरकार ने भारत नेट नाम की एक पहल शुरू की है, यह देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने का एक उच्च गति डिजिटल राजमार्ग है। ऑप्टिकल फाइबर के जरिए ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली यह दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना होगी।
9. बीएसएनएल ने 30 साल पुरानी व्यवस्था को बदलने के लिए अगली पीढ़ी के नेटवर्क (एनजीएन) शुरू की है, यह आवाज, डेटा, मल्टीमीडिया /वीडियो और अन्य प्रकार के पैकेट स्वीच संचार सेवाओं जैसे सभी प्रकार की सेवाओं के प्रबंधन के लिए एक आईपी आधारित प्रौद्योगिकी है।
10. बीएसएनएल ने देश भर में बड़े पैमाने पर वाई-फाई हॉटस्पॉट बनाने की शुरुआत की है। उपयोगकर्ता अपने मोबाइल उपकरणों के माध्यम से बीएसएनएल वाई-फाई नेटवर्क से जुड़ सकते हैं।



11. इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिक सेवाएं देने और नागरिक और अधिकारियों के बीच संवाद में सुधार के लिए एक सार्वभौमिक पहुंच की अत्यंत आवश्यकता है। सरकार को भी इसका एहसास है, यह ब्रॉडबैंड राजमार्ग को डिजिटल इंडिया के स्तंभों में शामिल करने से परिलक्षित होता है। जहां कनेक्टिविटी एक कसौटी है, वहीं नागरिकों के लिए सेवाओं की आपूर्ति की सुविधा के लिए प्रौद्योगिकियों को सक्षम करना और उपलब्ध कराना दूसरे मानदंड हैं।

नीतिगत पहल

ई-क्रांति फ्रेमवर्क, भारत सरकार के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अपनाने की नीति, ई-गवर्नेंस सिस्टम में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अपनाने के लिए फ्रेमवर्क, भारत सरकार के लिए ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के लिए नीति, भारत सरकार की ई-मेल नीति, भारत सरकार के आईटी संसाधनों के उपयोग पर नीति, सरकारी अनुप्रयोगों के स्रोत कोड को खोलकर सहयोगात्मक अनुप्रयोग विकास की नीति, क्लाउड रेडी अनुप्रयोगों के लिए दिशानिर्देश का विकास और पुनर्गठन जैसे नीतिगत पहलों को (डीईआईटीवाई के

द्वारा) भी ई-शासन के क्षेत्रों में शुरू किया गया है।

- बीपीओ नीति को विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य राज्यों के छोटे/मुफ़रिसल शहरों में बीपीओ केंद्रों को स्थापित करने के लिए अनुमोदित किया गया है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स विकास कोष (ईडीएफ) नीति नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और उत्पाद विकास को बढ़ावा देने के लिए और वेंचर फंड का एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए देश के भीतर आईपी का एक संसाधन पूल तैयार करने पर लक्षित है।
- लचीले इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीफलेक्सई) भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य लचीले इलेक्ट्रॉनिक्स के उभरते क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है।
- इंटरनेट पर उत्कृष्टता केंद्र (आईओटी) पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई), अरनेट और नैसकॉम की एक संयुक्त पहल है।

ई-गवर्नेंस सुधार, भारत की गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में सुधार के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में काम करने में सक्षम है। हम मानते हैं कि इस तरह के हस्तक्षेप से गरीबों को स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने में मदद मिल सकती है।

अब यह निर्धारित करना है कि भारत के सबसे गरीब लोगों के लाभों के प्रभावों को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए इस मंच का लाभ उठाया जाए। डीबीटी के गुण और दोष आशाओं और मान्यताओं का मिश्रण हैं, लेकिन डीबीटी अच्छे के लिए है और निश्चित रूप से इससे सभी हितधारकों यानि सरकार, लाभार्थियों और निजी संस्थानों को फायदा होगा। यह प्रत्येक लाभार्थी को उनका हिस्सा समय पर प्रदान कर, आर्थिक समानता के अधिकार को वास्तविकता प्रदान करेगा। □

(पृष्ठ 15 से जारी ...)

नीली क्रांति

मत्स्य क्षेत्र विकास और मछुआरा समुदाय के कल्याण की अपार संभावनाओं को देखते हुए नीली क्रांति के तहत मत्स्य क्षेत्र विकास की एकीकृत योजना प्रारंभ की गई है। नीली क्रांति के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए मत्स्य से संबंधित विविध योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अगले पांच वर्ष के लिए

3000 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

बजटीय सहायता

इन सभी गतिविधियों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने वर्ष 2016-17 के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता का प्रावधान किया है। वर्ष 2016-17 के लिए कृषि मंत्रालय हेतु 35984 करोड़ रुपये की विशाल बजटीय

सहायता निर्धारित की गई है। इसके अलावा वर्ष 2016-17 के लिए किसानों के वास्ते 9 लाख करोड़ रुपये की ऋण सहायता की भी परिकल्पना की गई है। सबसे बढ़कर, ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण विद्युतीकरण और सामाजिक क्षेत्र के अन्य प्रयासों में निवेश से गांवों के कायाकल्प में मदद मिलेगी। ये सभी उपाय किसानों के कल्याण में सहायक होंगे और ग्रामीण भारत में दीर्घकालिक समृद्धि लाएंगे। □

समावेशी विकास और दूरगामी परिणाम का राजनय

अचल मल्होत्रा



भारत समावेशी विकास के लिए परस्पर प्रयासरत है। इस प्रयास को मजबूती देने के लिए भारत अपने पड़ोसी देशों एवं शेष विश्व से लगातार संबंध बेहतर करने के प्रयास कर रहा है। भारत की कूटनीति का ही प्रयास है कि उसे बहुपक्षीय सहयोग मिल रहा है। कुल मिलाकर राजनय इस रवैये के साथ आगे बढ़ रहा है कि समावेशी विकास के भारत के एजेंडे के साथ अन्य देश भी तालमेल कर सकें

मई 2014 में कार्यभार ग्रहण करने के बाद नई सरकार ने लंबी अवधि के नजरिए के साथ अभिनव पहल की एक श्रृंखला की घोषणा की। सरकार के अनेक कार्यक्रम जैसे *मेक इन इंडिया*, *स्किल भारत*, *स्मार्ट सिटी*, *बुनियादी ढांचे का विकास*, *डिजिटल भारत*, *स्वच्छ भारत* आदि प्रथम दृष्टया घरेलू एजेंडे का हिस्सा नजर आए लेकिन इन कार्यक्रमों की सफलता के लिए बाहरी आदानों जैसे विदेशी भागीदार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता थी। भारत की कूटनीति ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बहुत कम समय में सभी आवश्यकताओं को पूरा किया गया। अब भारत की विदेश नीति क्रियाशील एवं व्यावहारिक है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कूटनीति का समिश्रण है। यह विकास केंद्रित है। इसके केंद्र में ऐसे बाहरी वातावरण का सृजन करना है जोकि देश के समावेशी आंतरिक विकास के अनुकूल हो। यहां मंतव्य घरेलू एजेंडे की प्राथमिकताओं के साथ कूटनीतिक पहल को भी संश्लिष्ट करना है। इसके अतिरिक्त इन प्रयासों का लक्ष्य यह है कि विभिन्न देशों के बीच बढ़ते अविश्वास को दूर किया जाए, खासकर पड़ोसी देशों के साथ और विश्व भर में परस्पर सहयोग कायम करने हेतु मित्रता और समझदारी विकसित की जाए, साथ ही एक प्रभावशाली देश के रूप में विश्व स्तर पर भारत की मौजूदगी और दृश्यता बढ़ाई जाए।

भारत के दीर्घकालीन दृष्टिकोण पर अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों की सहमति हासिल करने के लिए हमारी राजनीतिक-आर्थिक कूटनीतिक पहल को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। यहां हम जिन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, वे केवल सकारात्मक परिणामों का संकेत हैं:

देश में समावेशी विकास हेतु कूटनीति बुनियादी ढांचा और वित्त

गत वर्ष अगस्त में प्रधानमंत्री की दुबई यात्रा के दौरान संयुक्त अरब अमीरात ने भारत बुनियादी ढांचा निवेश कोष की घोषणा की गई थी। इस कोष ने भारत में बुनियादी ढांचे के त्वरित विस्तार हेतु भारत की योजनाओं में निवेश को समर्थन देने के लिए 75 बिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन और भारत ने देश के राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा निवेश कोष के तहत एक साझेदारी कोष का गठन किया है। ऐसी संभावना है कि भारतीय रेल और विशेष रूप से सड़कों को विदेशी सहयोग और सहायता का लाभ मिलेगा। जापान पूर्वोत्तर में सड़कों की कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए ऋण उपलब्ध कराने को तैयार है। भारत और जापान के बीच उच्च गति की बुलेट ट्रेन के निर्माण पर सहमति बनी है। बुलेट ट्रेन शुरू होने के बाद मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा केवल दो घंटे में तय की जा सकेगी, जिसमें अभी सात घंटे लगते हैं। जापान चेन्नई और अहमदाबाद मेट्रो परियोजनाओं के लिए 100 बिलियन येन का ओडीए ऋण भी देगा। वहीं फ्रांस दूसरे चरण की बंगलुरु और

लेखक अर्मेनिया और जॉर्जिया में भारत की राजदूत पद पर कार्यरत थे। संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठन विएना में भारत के स्थायी सहायक प्रतिनिधि रहे। नयी दिल्ली में पड़ोसी देशों के साथ संबंध विभाग के प्रभारी निदेशक हैं। आजकल विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर फ्रीलांसर के तौर पर विश्लेषण करते हैं। साथ ही भारतीय विश्वविद्यालयों में भारत की विदेश नीति पर व्याख्यान भी करते हैं। ईमेल: achal_malhotra@hotmail.com

कोच्चि मेट्रो परियोजनाओं और नागपुर में मेट्रो परियोजना को वित्त पोषित करेगा। बंगलुरु और नागपुर में मेट्रो परियोजनाओं के लिए जर्मनी भी प्रति परियोजना 500 मिलियन यूरो का ऋण भारत को प्रदान करेगा। भारत और चीन ने रेलवे क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति

वर्ष 2015 में एफडीआई में पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जोकि महत्वाकांक्षी योजनाओं को साकार करने के लिए अति आवश्यक है। इससे उन कूटनीतिक अभियानों की सफलता प्रदर्शित होती है जिनकी शुरुआत यह सोचकर की गई थी कि इनसे विश्व स्तर पर भारत की उभरती अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ेगा।

जताई है। प्रस्तावित परियोजनाओं में मौजूदा चेन्नई-बंगलुरु-मैसूर क्षेत्र पर गति को बढ़ाना शामिल हैं। फ्रेंच कंपनी आल्सटॉम बिहार के मधेपुरा में 3.2 बिलियन यूरो के निवेश के साथ इलैक्ट्रिक इंजन संयंत्र का निर्माण करेगी। भारत में रेलवे के बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित करने के लिए लंदन में पहले रुपी डिनोमिनेटेड बांड की शुरुआत का कार्य प्रगति पर है।

मेक इन इंडिया

भारत के विदेशी अभियानों पर प्रभावशाली प्रतिक्रिया मिली है। रूस ने भारत में केए 226 हेलीकॉप्टरों के संयुक्त निर्माण पर सहमति जताई है। इसके अतिरिक्त मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के स्थानीयकरण पर सहयोग देने पर भी रजामंदी जताई है। रूस के रोसएटम और भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग ने स्थानीयकरण के लिए कार्रवाई कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है। एल एंड टी और फ्रेंच अरेवा ने जैतपुर परमाणु बिजली परियोजना का स्वदेशीकरण बढ़ाने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा पर सहमति जताई है। एयरबस और टाटा भारत में सी 295 हेलीकॉप्टरों के संयुक्त निर्माण का कार्य करेंगे। एयरबस ने भी हेलीकॉप्टर निर्माण हेतु महिंद्रा के साथ एक प्रारंभिक समझौता किया है। बोइंग एचएच 64 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए एयरो संरचनाओं का निर्माण करेगा। 12 बिलियन डॉलर मूल्य

की जापान-भारत मेक इन इंडिया विशेष वित्त सुविधा की शुरुआत की गई है। वहीं, मारुति जापान में निर्यात के लिए कारों का निर्माण करेगी।

विदेशी निवेश

वर्ष 2015 में एफडीआई में पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जोकि महत्वाकांक्षी योजनाओं को साकार करने के लिए अति आवश्यक है। इससे उन कूटनीतिक अभियानों की सफलता प्रदर्शित होती है जिनकी शुरुआत यह सोचकर की गई थी कि इनसे विश्व स्तर पर भारत की उभरती अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ेगा। भारतीय और चीनी कंपनियों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञानों का कुल मूल्य 22 बिलियन डॉलर मूल्यांकित किया गया है। भारत और ब्रिटेन की निजी कंपनियों के बीच 9.2 बिलियन ब्रिटिश पाउंड के सौदे किए गए हैं जिसमें वोडाफोन का 1.3 बिलियन ब्रिटिश पाउंड का सौदा भी शामिल है। जापान ने अगले पांच वर्षों में भारत में बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं और स्मार्ट शहरों के निर्माण के लिए 35 बिलियन डॉलर के निवेश का वादा किया है। दक्षिण कोरिया ने 10 बिलियन डॉलर का वादा किया है (1 बिलियन डॉलर आर्थिक विकास सहयोग निधि के रूप में और 9 बिलियन डॉलर प्राथमिक क्षेत्रों जैसे रेलवे, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन हेतु निर्यात ऋण के रूप में) जर्मनी की ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की दिग्गज कंपनी बॉश ने भारत में तीन नए विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना की घोषणा की है और 100 बिलियन ब्रिटिश पाउंड के निवेश की बात की है।

स्मार्ट सिटी

भारत में स्मार्ट शहरों के विकास में सहायता करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय भागीदार सामने आए हैं: अमेरिका ने विशाखापत्तनम, अहमदाबाद, इलाहाबाद को विकसित करने के लिए सहमति जताई है। फ्रांस ने चंडीगढ़, नागपुर, पुहुचेरी पर विशेष जोर देते हुए स्मार्ट सिटी परियोजना में 2 बिलियन यूरो से अधिक का निवेश करने को तैयार है।

डिजिटल इंडिया और स्मिल इंडिया

माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बहुराष्ट्रीय

कंपनियों डिजिटल इंडिया के कार्यावयन की दिशा में योगदान देने पर सहमत हैं। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, सिंगापुर और मलेशिया आदि देशों ने कौशल भारत कार्यक्रम के कार्यावयन में भारत की सहायता करने पर रजामंदी दिखाई है।

स्वच्छ गंगा

जापान और जर्मनी ने गंगा नदी के कायाकल्प के लिए वित्तीय सहायता, विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी की पेशकश की है।

ऊर्जा सुरक्षा

इस क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा हेतु भागीदारी पर कूटनीतिक पहल की जा रही है। पिछले वर्ष दिसंबर में पेरिस जलवायु परिवर्तन शिखर वार्ता के मौके पर भारत की पहल पर 100 से अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई थी। यह इस दिशा में यह कदम मील का पत्थर था। इसके लिए भारत ने सचिवालय के लिए जमीन आवंटित की है (गुडगांव, एनसीआर दिल्ली में) और सचिवालय के निर्माण हेतु 30 मिलियन डॉलर का योगदान करने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत में परमाणु संयंत्रों की स्थापना और हमारे ऊर्जा मिश्रण में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विदेश से प्राकृतिक यूरेनियम की खरीद हेतु असेन्य परमाणु सहयोग के लिए समझौता किया जा रहा है।

भूटान और बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। भूमि सीमा समझौते के अनुसमर्थन से न केवल भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की सीमा पर सहमति बनी, बल्कि इससे सीमा प्रबंधन सहज हुआ विशेष रूप से अवैध प्रवास, मानव तस्करी, स्मगलिंग आदि की जांच करना आसान हुआ। अब 161 एन्क्लेव में रहने वाले पचास हजार राज्यविहीन व्यक्तियों की वैध राष्ट्रीय पहचान है।

विश्वास बहाली के लिए कूटनीति

पी 5 के अतिरिक्त विश्व के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र- दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, खाड़ी, अफ्रीका, एशिया प्रशांत - भारत की

विश्वव्यापी कूटनीतिक पहुंच के गंतव्य हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र के विचार-विमर्श में भाग लेने के अतिरिक्त महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूहों जैसे आसियान, ईएएस, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जी-20, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन में भी सक्रिय है।

दिल्ली घोषणापत्र 2015 पर सहमति बनी जिसमें भारत-अफ्रीका के बीच सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए 10 बिलियन डॉलर के ऋण, 600 मिलियन डॉलर के अनुदान सहयोग तथा अगले पांच वर्षों के लिए 50000 छात्रवृत्तियों की घोषणा की है। इन प्रयासों से अफ्रीका में भारत की मौजूदगी बढ़ेगी, साथ ही भारत के साथ सद्भावना उत्पन्न होगी और अफ्रीका में चीन की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करना संभव होगा।

नए प्रधानमंत्री के आधिकारिक तौर पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले भी हम अपने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देते रहे हैं। मई 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के राष्ट्र और सरकार प्रमुखों की उपस्थिति से यह बात रेखांकित हुई कि भारत की नई राजनीतिक व्यवस्था अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाना चाहती है। इस अवसर ने शुरुआती संबंधों को पुष्ट किया और इसके बाद क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की तर्ज पर यात्राओं और बैठकों का आदान-प्रदान शुरू हुआ। साथ ही पाकिस्तान से दोबारा बातचीत शुरू हुई। कुल मिलाकर भारत द्वारा की गई इस पहल के परिणाम संतोषजनक रहे। भूटान और बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। भूमि सीमा समझौते के अनुसमर्थन से न केवल भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की सीमा पर सहमति बनी, बल्कि इससे सीमा प्रबंधन सहज हुआ विशेष रूप से अवैध प्रवास, मानव तस्करी, स्मगलिंग आदि की जांच करना आसान हुआ। अब 161 एन्क्लेव में रहने वाले पचास हजार राज्यविहीन व्यक्तियों की वैध राष्ट्रीय पहचान है। नेपाल के साथ हमारा विश्वास बढ़ा है। श्रीलंका और मालदीव के साथ भी भारत के संबंध फिर से कायम हुए हैं। अफगानिस्तान के

साथ रणनीतिक साझेदारी को नया जीवन मिला है लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत द्वारा लचीलापन दिखाने के बावजूद भारत-पाकिस्तान संबंधों में अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। फिर भी रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। उम्मीद की एक गली नजर आ रही है जिससे भविष्य में आगे बढ़ने की आशा की जा सकती है।

पी 5

अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्राओं ने पी 5 देशों के साथ संबंधों में नवशक्ति का संचार किया और इन देशों के साथ बहुपक्षीय सहयोग को गति प्रदान की। दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री की मॉस्को यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण थी। यह धारणा बन रही थी कि मई 2014 में नई सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद भारत धीरे-धीरे पश्चिम के करीब आने के प्रयास में अपने पुराने मित्र रूस से दूर हो रहा है। इस यात्रा से न सिर्फ रूस से संबंधित चिंता का निवारण हुआ, बल्कि आपसी विश्वास और भरोसा भी बहाल हुआ। साथ ही, एक ध्रुवीय विश्व में मौजूद रहते हुए एक दूसरे की मजबूरियों को समझने का प्रयास किया गया।

एक्ट ईस्ट नीति

नब्बे के दशक में प्रतिपादित लुक ईस्ट नीति ने एक्ट ईस्ट नीति का रूप अख्तियार किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत आसियान देशों के साथ अपने संबंधों, विशेष रूप से आर्थिक संबंधों पर ठोस पहल करने पर जोर दे रहा है। इसके अतिरिक्त भारत ने आसियान-भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास निधि के लिए 5 मिलियन डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है, जोकि इससे पहले 1 मिलियन डॉलर थी।

द्वीप देश

समुद्री सुरक्षा और नील/महासागर अर्थव्यवस्था के लिहाज से मालदीव, श्रीलंका, मॉरीशस, सेशल्स जैसे देशों में कूटनीतिक पहल करना महत्वपूर्ण है। यह चीन के बढ़ते प्रभाव से मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक उपाय भी कहा जा सकता है।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा और बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों की मौजूदगी के कारण खाड़ी

और पश्चिम एशिया/मध्य पूर्व भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त आईएसआईएस जैसी कट्टरपंथी और हिंसक ताकतों के उभरने के कारण हमारी सुरक्षा को भी खतरा है। अगस्त 2015 में संयुक्त अरब अमीरात और इस वर्ष अप्रैल में सऊदी अरब में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान इन विषयों पर चर्चा की गई। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली और एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी विकसित हुई। सऊदी अरब की यात्रा से रणनीतिक भागीदारी को मजबूती मिली। इस यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग, आतंकवाद का मुकाबला करने और सुरक्षा के लिए सहयोग पर जोर दिया गया जिसमें खाड़ी और हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा शामिल हैं, विशेष रूप से आतंकवादियों द्वारा साइबर स्पेस के दुरुपयोग को रोकना। इसके अतिरिक्त आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को धन मुहैया कराने से संबंधित खुफिया जानकारी साझा करने पर भी सहमति बनी है।

अफ्रीकी देश

भारत-अफ्रीका फोरम (अक्टूबर, 2015) के दौरान पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप के 41 देशों के राष्ट्र और सरकार प्रमुख दिल्ली पहुंचे। इस फोरम ने अतीत को प्रतिबिंबित करने, सदियों पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करने तथा एक गतिशील एवं परिवर्तनशील कार्यसूची को सबके सम्मुख रखने का एक सुअवसर

विश्वव्यापी परमाणु निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं जैसे मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर), परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी), ऑस्ट्रेलिया समूह और वेसनर एग्रीमेंट में भारत की सदस्यता को पहले से अधिक समर्थन मिला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए भी समर्थन बढ़ा है।

प्रदान किया जिससे आने वाले वर्षों में भारत और अफ्रीका के करीब आने की उम्मीद की जा सकती है। इस दौरान दिल्ली घोषणापत्र 2015 पर सहमति बनी जिसमें भारत-अफ्रीका के बीच सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए 10

बिलियन डॉलर के ऋण, 600 मिलियन डॉलर के अनुदान सहयोग तथा अगले पांच वर्षों के लिए 50000 छात्रवृत्तियों की घोषणा की है। इन प्रयासों से अफ्रीका में भारत की मौजूदगी बढ़ेगी, साथ ही भारत के साथ सद्भावना उत्पन्न होगी और अफ्रीका में चीन की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करना संभव होगा।

बहुपक्षीय मंच

संयुक्त राष्ट्र, जी -20, आसियान, ईएएस, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन सहित प्रमुख बहुपक्षीय मंचों में भारत की बढ़ती सक्रियता ने देश का अंतर्राष्ट्रीय कद बढ़ाया है। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, विश्वव्यापी प्रशासनिक ढांचे में सुधार, जलवायु परिवर्तन, समुद्री डकैती, साइबर सुरक्षा, विश्वव्यापी व्यापार वार्ता जैसे मुद्दों पर भारत के अभियानों से अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण बदला है और विश्वव्यापी कार्यसूची का रूपांतरण हुआ है। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में भारत पर्यवेक्षक की बजाए पूर्ण सदस्य बन गया है। यह स्पष्ट है कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है जोकि ओपेक में भारत की सदस्यता को मिले समर्थन में सकारात्मक रूप से नजर आता है। विश्वव्यापी परमाणु निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं जैसे मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर), परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी), ऑस्ट्रेलिया समूह और वेसनर एग्रीमेंट में भारत की सदस्यता को पहले से समर्थन बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए भी समर्थन बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन को जल्द मंजूरी देने को भी रजामंदी मिल रही है, जिसे भारत ने प्रस्तावित किया था।

सीओपी 21 के अंतिम दस्तावेज में भारत के योगदान की विश्व स्तर पर सराहना की जा रही है। इस दस्तावेज में जलवायु के साथ न्याय की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। भारत ने इसमें जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सामान्य किंतु भिन्न जिम्मेदारी जैसे सिद्धांत रखे हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष जुलाई में रूस के उफा शहर में 7 वीं ब्रिक्स शिखर वार्ता में दस कदम या 10 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तावित किया था, जिसमें व्यापार मेलों, खेल, फिल्म महोत्सवों, कृषि, ऑडिट जैसे क्षेत्रों में अंतर क्षेत्रीय सहयोग की बात की गई थी। 7 वीं ब्रिक्स शिखर वार्ता में भारत समर्थित प्रस्तावों, जैसे 100 बिलियन डॉलर मूल्य के नए विकास बैंक और 100 बिलियन डॉलर मूल्य के मुद्रा रिजर्व पूल को औपचारिक रूप दिया गया।

कनेक्टिविटी

उपक्षेत्रीय और क्षेत्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कूटनीतिक पहल की गई जिसमें चटगांव और मोंगला बंदरगाहों के प्रयोग के लिए बांग्लादेश के साथ संधि, कोलकाता-ढाका-अगरतला बस सेवा की शुरुआत, भारत, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के बीच मोटर वाहन संधि शामिल है। भारत ने ऐसी परियोजनाओं के लिए 1 अरब डॉलर मूल्य के ऋण के लिए प्रतिबद्धता जताई है जिनसे भारत और आसियान देशों के बीच भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिले। भारत द्वारा

(जारी ... पृष्ठ 32 पर)

www.afeias.com

IAS की Free तैयारी

IAS की परीक्षा के निःशुल्क मार्गदर्शन के लिए डॉ. विजय अग्रवाल की वेबसाइट

इस पर आपको मिलेगा -

- प्रतिदिन ऑडियो लेक्चर
- अखबारों पर समीक्षात्मक चर्चा
- परीक्षा सम्बन्धी लेख
- आकाशवाणी के समाचार
- वीडियो
- नॉलेज सेंटर
- अखबारों की महत्वपूर्ण कतरनें
- फ्री मॉक-टेस्ट।

सुनिए डॉ. विजय अग्रवाल का
लेक्चर रोजाना

लॉग ऑन करें- www.afeias.com

डॉ. विजय अग्रवाल
की पुस्तक

‘आप IAS
कैसे बनेंगे’

आप
IAS
कैसे
बनेंगे

डॉ. विजय अग्रवाल

₹195/-

यह किताब IAS की तैयारी करने वालों के लिए एक
‘चलता-फिरता कोचिंग संस्थान’ है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं के यहाँ उपलब्ध

YH-29/2016

सरकार, सुशासन और सामाजिक न्याय

स्वदेश सिंह



शासन की सफलता आखिरी व्यक्ति तक नीतियों की सफल पहुंच सुनिश्चित करने में है। प्रक्रिया और वितरण शासन के दो अहम पहलू हैं। इन दोनों पहलुओं में सफलता सुनिश्चित होने पर ही किसी योजना को पूर्णतः सफल माना जा सकता है। यह सुखद संकेत है कि हाल के वर्षों में इन दोनों पहलुओं पर सुधार दिख रहा है और अंततः इसका सकारात्मक परिणाम योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी दिख रहा है जो सरकार का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए काफी है

(इस आलेख के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में ये बताने की कोशिश की गई है कि केंद्र सरकार सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कैसे वितरणीय न्याय और प्रक्रियात्मक न्याय को बराबर महत्व दे रही है। दूसरे हिस्से में केंद्र सरकार द्वारा समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों की चर्चा की गई है।)

मूल्यों और संसाधनों का आधिकारिक तौर पर निर्धारण ही राजनीति है। लंबे समय तक सही तरीके से ऐसा करते रहने से समाज में न्याय स्थापित होता है और राजनीति सामाजिक बदलाव का बड़ा माध्यम बनती है। जहां तक न्याय की बात है तो उसकी एक परिभाषा होती है जो बराबर हैं उन्हें बराबरी का हक देना और जो असमान हैं उन्हें अधिक महत्व देना। अगर राजनीति और न्याय की दोनों परिभाषाओं को एक साथ देखें तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में कठिनाई नहीं होगी।

मूल्यों और संसाधनों का न्यायसंगत तरीके से आधिकारिक रूप से निर्धारण ही राजनीति का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए जिससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा और राजनीति एक बड़े सामाजिक बदलाव की साक्षी बनेगी। न्याय सुनिश्चित करते समय दो स्तर पर ध्यान देना चाहिए। एक तो वितरण के स्तर पर और दूसरा क्रियान्वयन के स्तर पर। हम यहां न्याय के दो प्रकार पर चर्चा करेंगे- वितरणीय न्याय और प्रक्रियात्मक न्याय।

मौजूदा शासन और प्रक्रियात्मक न्याय

वितरणीय न्याय के तहत जनता के लिए संसाधन, योजना और कार्यक्रमों का सरकार

द्वारा निर्धारण किया जाता है। अधिकतर सरकारें अपने काम को यहीं तक सीमित मानती हैं। वो इस पर चिंता नहीं करती कि योजना या संसाधन नीचे तक या जरूरतमंद कैसे पहुंचेंगे। इसीलिए हमें योजनाओं के धरातल पर आने पर कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई स्तर पर संसाधनों का रिसाव (लीकेज) देखने को मिलता है। इस रिसाव का सबसे अधिक नुकसान पंक्ति के अंतिम में खड़े व्यक्ति को होता है क्योंकि वहां पहुंचते-पहुंचते संसाधन खत्म होने लगते हैं। जो गरीब और वंचित है वो हमेशा ही गरीब रह जाता है। इसलिए जरूरी है कि वितरणीय न्याय के साथ-साथ प्रक्रियात्मक न्याय भी सुनिश्चित किया जाए। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने योजनाओं के निर्माण के समय से ही जनभागीदारी का पूरा ख्याल रखते हुए योजनाओं को ऐसे निर्मित किया है जिससे अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। योजना के क्रियान्वयन में कई स्तर पर प्रक्रियात्मक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। अगर क्रियान्वयन के स्तर पर न्याय सुनिश्चित नहीं होगा तो वितरणीय न्याय का कोई लाभ नहीं होगा और सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित नहीं हो पाएगा।

वितरणीय न्याय (मूल्यों-संसाधनों का निर्धारण) के साथ-साथ केंद्र सरकार ने प्रक्रियात्मक न्याय (मूल्यों-संसाधनों का वितरण) के माध्यम से निचले स्तर के लोगों तक सुशासन पहुंचाने की सफल कोशिश की है जो विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं में

लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में राजनीतिशास्त्र के प्राध्यापक हैं। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और आईआईएमसी, नई दिल्ली से पढ़ाई पूरी करने के बाद मीडिया में काम किया है। इस आलेख के लिए पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली के महानिदेशक विनय सहस्रबुद्धे के मार्गदर्शन और शोधार्थियों से मिले सहयोग के लिए लेखक आभार व्यक्त कर रहे हैं। ईमेल: swadesh171@gmail.com

परिलक्षित होता है। जब योजनाएं बनीं तभी इस पर भी चिंता की गई कि वो आम आदमी तक कैसे पहुंचेगी। यहां पांच उदाहरणों के माध्यमों से समझने की कोशिश की गई है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम साबित हुई है। इस योजना का उद्देश्य ही उन लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना था जो लंबे समय से छूटे हुए थे। इसे तय करने के लिए बैंकों ने स्थानीय और लक्षित समूहों के बीच से ही लोगों को रोजगार दिया जिनका काम लोगों का अकाउंट खुलवाना था। इन एक लाख 26 हजार लोगों को बैंक मित्र नाम दिया गया जिन्हें अकाउंट खोलने के लिए एक मशीन उपलब्ध कराई गई जिससे वो लोगों के बीच जाकर अकाउंट खोल सकें और लोगों को बैंक तक आकर अकाउंट खुलवाने की परेशानी ना उठानी पड़े। इन बैंक मित्रों को अपने इलाके के लोगों के बारे में पता था। ये उन्हीं की भाषा में बात करते थे। इन्होंने स्थानीय लोगों को अपने स्तर पर राजी किया और उनके अकाउंट खोले। बैंक मित्रों की वजह से बैंक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और ये ऐसे लोग थे जिन्हें सच में जोड़े जाने की जरूरत थी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के बैंक मित्र दुर्गेश सोनी ने 1300 से अधिक अकाउंट खुलवाए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के बैंक मित्र वेदराम ने 2000 से अधिक बैंक अकाउंट खुलवाए।

प्रधानमंत्री ने चुनावों से पूर्व वादा किया था कि हर स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। सरकार के दो साल बीतने के बाद ये कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार में बहुत कमी आई है। मोदी सरकार ने ई-गवर्नेंस, व्यवस्थित नीतिगत सुशासन और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर जवाबदेही और पारदर्शिता तय करने का पूरा प्रयास किया है। पारदर्शी तरीके से 2जी स्पेक्ट्रम और कोल ब्लॉक की बोली और आवंटन इसका बेहतरीन उदाहरण है। इससे केंद्र सरकार के खजाने में तीन लाख करोड़ से अधिक की राशि एकत्रित हुई।

कृत्रिम अंग वितरण: सशक्तीकरण का रिकॉर्ड

पिछले दो वर्षों में सरकार ने विकलांगजनों को कृत्रिम अंग और यंत्र वितरण के 1800 से अधिक कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किए, जबकि पिछले 2014 से पहले के 20 वर्षों में ऐसे सिर्फ 100 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

की तरफ से आयोजित होने वाले इस कैंप में सिर्फ दो वर्षों में ही 100 से अधिक मेगाकैंप भी आयोजित किए जा चुके हैं जिसमें हर एक कैंप में एक करोड़ रुपए से अधिक के यंत्र बांटे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में हुए कैंप में 8000 लोगों को कृत्रिम अंग और यंत्र बांटे गए। इस कार्यक्रम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ये स्कीम तो पहले की सरकारों में भी थी लेकिन मंत्रालय द्वारा प्रक्रियात्मक न्याय सुनिश्चित करने से ही ऐसा संभव हो सका।

मंत्रालय के अधिकारियों ने पहले कॉर्पोरेट कंपनियों को राजी किया कि वो इस स्कीम में अपना सीएसआर फंड का पैसा दें। सांसदों और विधायकों को इस स्कीम से अवगत कराने के लिए जागरूकता कार्यक्रम किए गए और पत्र लिखे गए। हालांकि, इस स्कीम के तहत खर्च का बड़ा हिस्सा मंत्रालय द्वारा ही दिया जाता है लेकिन थोड़ा हिस्सा जनप्रतिनिधियों को भी खर्च

प्रधानमंत्री ने चुनावों से पूर्व वादा किया था कि हर स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। सरकार के दो साल बीतने के बाद ये कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार में बहुत कमी आई है। मोदी सरकार ने ई-गवर्नेंस, व्यवस्थित नीतिगत सुशासन और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर जवाबदेही और पारदर्शिता तय करने का पूरा प्रयास किया है। पारदर्शी तरीके से 2जी स्पेक्ट्रम और कोल ब्लॉक की बोली और आवंटन इसका बेहतरीन उदाहरण है।

करना पड़ता है। पता लगने पर जनप्रतिनिधि तुरंत राजी होने लगे क्योंकि उन्हें बना-बनाया एक बड़ा कार्यक्रम अपने क्षेत्र के लिए मिल रहा था। सही लाभार्थियों के चयन के लिए मंत्रालय ने जिलाधिकारी को सीधे तौर पर विकलांगजनों की फोटो सहित सूची बनाने को कहा जिससे सही सूची तैयार हो सकी। पहले ये काम एनजीओ किया करते थे जिससे कई बार कमियां देखने को मिलती थीं। प्रक्रियात्मक स्तर पर छोटे से बदलाव ने देश के आठ करोड़ विकलांगजनों के को एक बड़ा अवसर उपलब्ध करा दिया।

सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्रालय ने पिछले वित्तीय वर्ष में 3.30 करोड़ छात्रों को 7465 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप बांटी। ये छात्र दलित, ओबीसी और ईबीसी वर्ग के थे। पिछली सरकार में 2012-13, 2013-14 की धनराशि कई राज्यों में

बांटी नहीं जा सकी थी। मोदी सरकार ने राशि के सही समय पर उपयोग के लिए अधिकारी राज्यों में भेजे। मंत्रालय से सभी प्रकार की स्कॉलरशिप की जानकारी को एक प्रपत्र के माध्यम से सांसदों, विधायकों और जिलाधिकारियों को भेजा और उनसे आग्रह किया कि अपने क्षेत्र के कमजोर वर्गों के छात्रों के बीच इन स्कॉलरशिप को प्रचारित करें। इस बार उच्चशिक्षण संस्थानों के दलित और पिछड़े छात्रों ने भी बड़ी संख्या में स्कॉलरशिप प्राप्त की। मंत्रालय ने सोशल मीडिया के माध्यम से इन स्कॉलरशिप को प्रचारित करने का काम किया क्योंकि आज के छात्रों के बीच सोशल मीडिया बहुत लोकप्रिय है।

प्रक्रियात्मक न्याय की जैम त्रिवेणी

सरकार द्वारा प्रक्रियात्मक न्याय सुनिश्चित तक करने के लिए **जैम त्रिवेणी (JAM)**। जनधन, आधार और मोबाइल पर काम किया जा रहा है जिसके तहत कैश ट्रांसफर के लाभ को रिसावमुक्त बनाते हुए सीधे लक्षित व्यक्ति के अकाउंट तक भेजा जा सकेगा। पहले जो योजनाएं बनीं उनमें कई स्तर पर रिसाव रहता था और लक्षित व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंच पाता था। जैम के माध्यम से सब्सिडी की राशि सीधे लक्षित व्यक्ति तक पहुंच सकेगी और इससे सरकार को रिसाव कम करने में मदद मिलेगी और सब्सिडी खत्म करने जैसी बातों पर रोक लगेगी। सरकार का साफ तौर पर माना है कि गरीब को सब्सिडी मिलनी चाहिए, लेकिन बिचौलिया नहीं होना चाहिए। जैम तकनीकी से बिचौलिया समाप्त होंगे और इससे सब्सिडी का रिसाव खत्म होगा ना कि सब्सिडी।

ऊपर दिए गए उदाहरणों से ये साफ होता है कि कैसे मोदी सरकार प्रक्रियात्मक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। प्रक्रियात्मक न्याय सुनिश्चित किए बिना योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए केंद्र सरकार जनसहभागिता, जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है जिससे समाज के निचले स्तर तक सुशासन सुनिश्चित किया जा सके और अंतिम व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल सके।

सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण

आलेख के पहले हिस्से में हमने देखा कि कैसे केंद्र सरकार प्रक्रियात्मक न्याय पर ध्यान देकर समाज के वंचित वर्ग के लिए सुशासन सुनिश्चित कर रही है। इस हिस्से में हम सरकार द्वारा पिछले हाल में सामाजिक न्याय के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।

सकारात्मक कार्यवाही

सकारात्मक कार्यवाही को लेकर मौजूदा सरकार बहुत ही सजग और प्रतिबद्ध है और नए तरीके से प्रयास कर रही है। आजादी के बाद से ही सकारात्मक कार्यवाही के नाम पर नौकरियों में आरक्षण की बात कही गई जो बिल्कुल सही थी, लेकिन जब समाज के दलित और पिछड़े वर्ग से लाखों की संख्या में युवा शिक्षित हो रहे हैं तो ये संभव नहीं कि उन सबके लिए सरकारी नौकरियां उपलब्ध हो पाएंगी। ऐसे में केंद्र सरकार ने नौकरी के साथ-साथ उद्यमिता पर बल दिया है।



सरकार ने 220 रुपये करोड़ का दलित वेंचर वैन्पिटल फंड बनाया है जिसके माध्यम से दलित समाज के युवा अपना उद्यम लगाने के लिए सरकार से ऋण ले सकते हैं। इसमें उन्हें कई

प्रकार की रियायतें दी गई हैं। मुद्रा योजना के तहत 25 लाख से अधिक दलित और पिछड़े वर्ग के युवाओं को शिशु, किशोर और युवा कैटेगरी के तहत छोटे-छोटे लोन दिए गए हैं जिससे वो अपना उद्यम खड़ा कर रहे हैं। सरकार ने हाल में ही एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना स्टैंड अप इंडिया शुरू की है जिसमें दलित, आदिवासी और महिला वर्ग के लोगों को उद्यम शुरू करने के लिए बैंकों से दस लाख से लेकर एक करोड़ रुपये तक का लोन मिलेगा। देश में इस समय 1.25 लाख बैंक शाखाएं हैं। हर शाखा को वंचित वर्ग (दलित, आदिवासी या महिला) के दो लाभार्थियों को लोन देना ही होगा और उन्हें उद्यम खड़ा करने में मदद करनी होगी। इस तरह पूरे देश में 2.50 लाख उद्यमी खड़े होंगे। इस तरह कि मोदी सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वंचित वर्ग से उद्यमी तैयार कर रही है। इनके छोटे-बड़े उद्यमों से ना सिर्फ ये सशक्त होंगे, बल्कि करोड़ों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा और समाज का सबसे वंचित वर्ग समृद्ध और विकसित हो सकेगा।

सामाजिक न्याय के नये कदम

सरकार ने सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के सशक्तीकरण के लिए बहुत से कदम उठाए जिसमें से कुछ प्रमुख नीचे दिए गए हैं।

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के युवाओं को प्राथमिकता दी गई। देश के 5 करोड़ 77 लाख छोटे उद्यमों में से 62 फीसदी उद्यमी दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग से आते हैं।
- दलित, पिछड़े और ईबीसी वर्ग के तीन करोड़ तीस लाख विद्यार्थियों को 7400 करोड़ रुपये से अधिक की स्कॉलरशिप बांटी गई।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश के 23 आईआईटी में पढ़ने वालों सभी दलित, आदिवासी और विकलांग छात्रों की फीस माफ कर दी। जिन परिवारों की वार्षिक आय पांच लाख से कम है उन्हें 66 फीसदी की छूट दी जा रही है और जिसकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है ऐसे हर छात्र की फीस माफ कर दी गई है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों के लिए 2014-15 में नेशनल फैलोशिप शुरू की गई। ओबीसी छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण का खर्च 100 फीसदी तक बढ़ा दिया गया। ओबीसी छात्रों के लिए दिए जाने वाले डॉ. अंबेडकर शिक्षण ऋण के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़ा दी गई।
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने 297 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एक लाख 67 हजार विद्यार्थियों को बांटी और 30 हजार से अधिक पिछड़े युवाओं को कौशल विकास में प्रशिक्षित किया।
- 2014 से अबतक 1800 से अधिक कृत्रिम अंग और यंत्र वितरण के कैंप आयोजित किए जा चुके हैं। एक करोड़ से अधिक की लागत वाले 100 मेगा कैंप भी आयोजित हुए हैं।
- सरकार समाज के वंचित वर्ग के वित्तीय समावेशीकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने पिछले साल 9.40 करोड़ सुरक्षा बीमा पॉलिसी दी जिसमें से 2.96 करोड़ वंचित समाज के लोगों को दी गई। 21 करोड़ से अधिक जनधन के अकाउंट खोले जा चुके हैं जिसमें अधिकतर समाज के दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग से आने वाले लोग हैं।
- प्रधानमंत्री ने अंबेडकर पंचतीर्थ घोषणा की है जिसके तहत भारत रत्न बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर से जुड़े पांच स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा।
- गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना शुरू की गई है जिसके तहत पांच करोड़ महिलाओं

को अगले तीन साल में गैस चूल्हा दिया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में 1.50 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।

- इस वित्तीय वर्ष के बजट को भारत का बजट कहा जा रहा है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र का विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक इस देश के गरीब और वंचित का है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने के लिए रूबन मिशन की शुरुआत की गई है। जिसके तहत 5-7 गांवों का समूह बनाकर उनमें शहरी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस समूह में 20 से 25 हजार लोग हुआ करेंगे।

ऊपर की तमाम बातों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि 2014 में राजनीतिक बदलाव के बाद सरकार समाज के सबसे वंचित वर्ग की आर्थिक स्थिति में बदलाव लाकर बड़े सामाजिक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रही है।

सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय, अंत्योदय और समरसता के लिए प्रतिबद्ध है। ये जरूर है कि इस सरकार ने सुशासन को सामाजिक न्याय से जोड़ने की सफल कोशिश की है।

संदर्भ

- रावल्स, जॉन, (2005): अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, (संशोधित संस्करण), बेलकनेप प्रेस, कैम्ब्रिज
- सेन, अमर्त्य, (2009): द आइडिया ऑफ जस्टिस, बेलकनेप प्रेस, कैम्ब्रिज
- वर्मा, विधु, (2011): नन-डिस्क्रिमिनेशन एंड इन इक्वलिटी इन इंडिया: कंटेस्टिंग बाउंड्री ऑफ सोशल जस्टिस, रट्लिज प्रेस
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय: संवैधानिक प्रावधान <http://socialjustice.nic.in/pdf/constprovmsje.pdf>
- <http://www.financialexpress.com/article/economy/financial-inclusion-at-core-of-governments-focus-pm-narendra-modi/184918/>
- <http://www.freepressjournal.in/govt-gives-rs-200-cr-to-ifci-to-fund-sc-entrepreneurs-thawar-chand-gechlot/603598>
- मेहता, प्रतापभानु: द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडिया
- <https://casi.sas.upenn.edu/khemka/mehta>
- http://www.huffingtonpost.in/2016/04/07/iit-fee-waiver-dalits_n_9630350.html
- <https://www.standupmitra.in/#NoBack>
- <http://www.mudra.org.in/>

* सभी वेब लिंक 15.05.2016 को देखे गए

India's **1** ever
LEADERSHIP PROGRAM for a
CAREER in POLITICS

Founder & Initiator: *Rahul V. Karad*



One-year full time residential
Master's Program In Government

MPG - 12, 2016-17

ADMISSIONS OPEN : BATCH -12 COMMENCES August 1, 2016

CAREER PROSPECTS :

Apart from Career in Electoral Politics, there are various attractive career opportunities in the field of functional politics as Research Associate, Political Analyst, Policy Associate, Political Strategist, Political Consultant, Election management, Election Research & Campaign management, Social media managers, Constituency management, Assisting in Parliamentary Affairs etc.

COURSE SYLLABUS :

- Political Marketing and Branding
- Political Economy
- Public Policy
- Global Politics
- Law, Public Administration and Governance
- Research Methods for Contemporary Political Issues
- Social Media handling

ELIGIBILITY :

Graduate from any faculty is eligible to apply for the selection process of MPG-12. The upper age limit is 30 years as on July 31, 2016.

Contact: **09850897039 / 07720061611**
admissions@mitsog.org

Apply online at **www.mitsog.org**
MIT Campus, Paud Road, Kothrud, Pune - 411 038



POLITICS AS THE BEST CAREER OPTION!

India needs leaders who are dynamic, proactive, capable and knowledgeable. All professions including Medicine, Engineering, Pharmacy, Management, Law etc. employ educated & skilled people in their respective fields. Then why not in Politics, which is as crucial as it concerns the wellbeing of nation and its populace at large. We have under graduate and post graduate programs to address the challenges of other sectors but none for those who envision to enter into politics in a professional way. When we look at the present political scenario, we all feel that India needs Leaders who have a fair idea about what is happening and what they need to do when they take over the mantle. But how do they go about it? Like getting proper guidance, training, knowledge whereby they can form their own perspective, and giving better guidance when leading the country and its citizens. Today's political environment demands knowledge & skills - like Foreign Policy, Political Economy, International relations, Public Policy, Constitution, Five Tier Structure and grass root politics required to win the elections, Election Management, Constituency Development etc.

The political leaders in their active public life are concerned mostly with Social Work focusing on policies related to betterment of the masses. They require trained/skilled manpower to assist them in this endeavor in the following areas - Political Analyst, Political Strategist, Election Consultants, Constituency Managers, Public Relation officer, Social Media analyst, Brand consultants etc.

All these positions require good analytical, research, managerial, leadership & communication skills along with good decision making power. Many professionals work for government and make excellent money, enjoy security in their positions. Think tanks and private firms also provide job opportunities, although the pay in such cases can vary, depending on the grants received and the group's political affiliations. These professionals represent the country in international forums, indulging in debates of grave importance, having meetings with international leaders, passing of bills in parliament etc. They assist to resolve the internal problems and issues as well as we need to make good relation with the other nation.

As professionals work for a corporate organization to enhance its brand equity, a healthy balance sheet and a good customer feedback, politicians are striving hard for their respective political parties and constituency. MIT School of Government, Pune established in 2005, is the only institute in the country to provide experiential learning and training to the young, dynamic leaders of India to take up challenging positions and leadership roles in the democratic fabric of the nation.

ढंग से काम कर रहे केंद्र सरकार के कुछ मंत्रालयों द्वारा किए गए कार्यों को उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। वर्तमान सरकार ने तमाम वेब-पोर्टल्स एवं एप्स के माध्यम से अपनी योजनाओं एवं कार्यों को सार्वजनिक करने की दिशा में बड़ा प्रयास किया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विद्युतीकरण के कार्यों को पारदर्शी बनाने के लिए एक वेब पोर्टल (<http://garv.gov.in/>) एवं *गर्व* नाम से एक मोबाइल एप जारी किया गया है। इस वेब-पोर्टल अथवा मोबाइल एप से कोई भी व्यक्ति राज्यवार, जिलेवार, पंचायतवार सहजता से यह विवरण प्राप्त कर सकता है कि किसी क्षेत्र-विशेष विद्युतीकरण का कार्य कितना हुआ है अथवा कितना शेष बचा है। इस वेब पोर्टल के माध्यम से न सिर्फ कार्य का ब्यौरा प्राप्त किया जा सकता है बल्कि कार्य-प्रगति

राष्ट्रीय ई-शासन के तहत अन्य क्षेत्रों में भी व्यापक स्तर पर काम पारदर्शी ढंग से चल रहा है। ई-टेंडर एवं ई-आक्शन को एक बेहतर उदाहरण माना जा सकता है। चूंकि, पिछले कुछ वर्षों में कोल आवंटन में सार्वजनिक हुई गड़बड़ियों पर नियंत्रण करने एवं ठेकों और नीलामी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ई-आक्शन एवं ई-टेंडर को बढ़ावा दिया जा रहा है।

संबंधी समस्त जानकारी भी हासिल की जा सकती है। इस माध्यम में कार्य की प्रगति से जुड़े अधिकारी से संबंधित संपर्क जानकारी भी सार्वजनिक की गई है।

चूंकि सार्वजनिक स्तर पर विद्युतीकरण से जुड़ी योजनाओं के सार्वजनिक होने की वजह से लापरवाही आदि की संभावना बहुत कम रहती है और कार्य से जुड़े पड़ताल की जानकारी हासिल करना बेहद आसान होता है। अगर कहीं से कोई गलत जानकारी सरकार को किसी निचले स्तर के अधिकारी द्वारा दी जाती है तो उस जानकारी को क्रॉस-चेक करना किसी के लिए भी बेहद आसान हो गया है। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा *दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना* के तहत विद्युतीकरण की दिशा में पारदर्शी ढंग से काम करते हुए मई 2018 तक 18000 उन गांवों हजार गांवों तक बिजली पहुंचाने का

संकल्प लिया गया है जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंच सकी है। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) पर उपलब्ध ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2016 तक 7,445 गांवों तक बिजली पहुंचाने का कार्य पूरा किया जा चुका है। विद्युत् मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार बिजली की उत्पादन क्षमता में 22,506 मेगावाट की बढ़ोत्तरी हुई है तो वहीं 65,554 मेगा वोल्ट एमप. की बढ़ोत्तरी सब-स्टेशन की संख्या में हुई है। 22,100 सर्किट किलोमीटर विद्युत् लाइनों पर काम पूरा हो चुका है। हालांकि, ई-शासन के तहत विद्युतीकरण से जुड़े कार्यों में अलग-अलग स्तर पर अलग वेब-पोर्टल्स उपलब्ध हैं, जहां से संबंधित जानकारियों को सहजता से हासिल किया जा सकता है।

निविदा व नीलामी भी ऑनलाइन

राष्ट्रीय ई-शासन के तहत अन्य क्षेत्रों में भी व्यापक स्तर पर काम पारदर्शी ढंग से चल रहा है। ई-टेंडर एवं ई-आक्शन को एक बेहतर उदाहरण माना जा सकता है। चूंकि, पिछले कुछ वर्षों में कोल आवंटन में सार्वजनिक हुई गड़बड़ियों पर नियंत्रण करने एवं ठेकों और नीलामी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ई-आक्शन एवं ई-टेंडर को बढ़ावा दिया जा रहा है। नीलामी की प्रक्रिया को पूर्णतया ऑनलाइन एवं पारदर्शी बनाने के लिए eauction.gov.in/eAuction/app वेब पोर्टल कार्य कर रहा है। सरकार का प्रयास लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना है कि वे ऑफलाइन नीलामी की बजाए ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया को तरजीह दें। ई-आक्शन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें सब कुछ वेबपोर्टल पर पारदर्शी ढंग से सार्वजनिक होता है और आवेदन से लगाए नीलामी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है।

कुछ इसी प्रकार सरकार द्वारा कोयला ब्लाक आवंटन के लिए ई-आक्शन की नीति केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई है, जो काफी पारदर्शी ढंग से काम करती नजर आ रही है। ई-आक्शन की तरह ही ई-टेंडर एवं ई-खरीद की प्रक्रिया को भी प्राथमिकता के साथ शुरू कर दिया गया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा ई-टेंडर प्रक्रिया को बेहद कारगर ढंग से लागू किया जा रहा है। भारत सरकार

द्वारा सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से संबंधी सभी कार्यों को ई-टेंडर के तहत किया जा रहा है और इसके लिए एक वेबपोर्टल (<https://morth.eproc.in/ProductMORTH/publicDash>) समर्पित किया गया है। इस वेबपोर्टल पर सभी नए टेंडर्स, चल रहे टेंडर्स एवं पूरा हो चुके टेंडर्स की जानकारी उपलब्ध है। हाल में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि वर्ष 2015-16 में 6000 किमी राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य सरकार ने पूरा किया है। सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तकनीक की आधुनिक प्रणालियों को सड़क निर्माण कार्य में इस्तेमाल करके यह लक्ष्य हासिल किया है।

प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत राइट टू पीएम विकल्प के जरिए जनसंवाद का एक अभूतपूर्व मंच उपलब्ध कराया है। भारत जैसे एक विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए यह प्रधानमंत्री से संवाद का यह ऑनलाइन विकल्प इस लिहाज से भी कहा जा सकता है क्योंकि भारत के आमजन की अवधारणा में यह कल्पना की भी बात नहीं थी कि वे प्रधानमंत्री को सीधा पत्र लिखेंगे और उसपर त्वरित कार्रवाई होगी।

मंत्रालय ने आगामी वर्ष 2016-17 के लिए सड़क परियोजनाओं में दोगुने से ज्यादा तेजी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। चूंकि पहले सड़क निर्माण की टेंडर प्रक्रिया बेहद जटिल एवं अपारदर्शी होती थी, लिहाजा प्रगति की रफ्तार का सुस्त होना स्वाभाविक था। अब चूंकि ई-टेंडर के माध्यम से यह पूरी प्रक्रिया तेज तो हुई ही है, साथ ही पारदर्शी भी हुई है लिहाजा काम तेजी से चल रहा है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार सरकार द्वारा प्रतिदिन 18 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है, जिसे 30 किलोमीटर प्रतिदिन तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कोई शक नहीं कि ई-शासन की प्रणाली मजबूत होने की वजह से शासकीय कार्यों में तेजी तो आई ही है, साथ में पारदर्शी ढंग से कार्य भी हो रहा है।

तालिका 1: ई-शासन केंद्रित प्रमुख वेबसाइटें

ई-शासन सेवाएं	वेबसाइट्स	विवरण
प्रधानमंत्री कार्यालय	http://pmindia.gov.in http://pgportal.gov.in	किसी भी विषय पर प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायतें एवं उस पर कार्रवाई।
ई-परिवहन सेवाएं	www.indianrail.gov.in www.irctc.co.in www.nmnh.nic.in www.airindia.com	ई-शासन योजना के तहत ई-परिवहन सेवाओं में हवाई, रेल और सड़क परिवहन आदि से संबंधित ऑनलाइन सेवाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं और आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं।
ई-बाजार सूचना	www.agmarknet.dac.gov.in http://www.eaindustry.nic.in/ http://rkvy.nic.in/	इस ई-सेवा के अंतर्गत कृषि और उसके बाजार से जुड़ी सेवाएं प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण वेबसाइट लिंक की जानकारी दी जाती है।
ई-नागरिक सेवाएं	http://www.uidai.gov.in/ http://www.nrega.nic.in/ http://www.passportindia.gov.in/ http://incometaxindiaefiling.gov.in/ http://www.eci.gov.in/	इस योजना के तहत नागरिकों को इन सेवाओं के कई के लिए सरकारी कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं होती है। वे इन योजनाओं और इनसे मिलने वाला लाभ कार्यालयों में या अपने घर में आराम से बैठे ले सकते हैं।
ई-डाक और संचार सेवाएं	http://www.indiapost.gov.in/ http://www.bsnl.in/	समय के साथ आगे बढ़ते हुए इस सेवा ने अनेक नई तकनीकों को अपनाया है और अब लोगों को त्वरित और सुलभ सेवा देने के लिए संचार प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग कर रहा है।
ई-ग्रामीण विकास से संबंधित जानकारी	http://www.omms.nic.in/ http://indiawater.gov.in/ http://lgdirectory.gov.in/ http://www.kvic.org.in/ http://jsk.gov.in/hindi http://coirboard.gov.in/	ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास की रणनीति में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की मदद से सरकार द्वारा कई ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
ई-शैक्षिक सेवाएं	http://www.ncert.nic.in/ http://mhrd.gov.in/ http://www.nios.ac.in/ http://www.ildc.in/ http://goidirectory.nic.in/	महत्वपूर्ण शैक्षिक सामग्री और पुस्तकें प्राप्त करने के लिए, परीक्षा परिणाम पता करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए ऋण एवं भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों को जानने के लिए यह उपयोगी है।
ई-भारत सूचनाएं	https://india.gov.in/	पूरे भारत से संबंधित राजनीतिक और भौगोलिक जानकारी।
विद्युत आपूर्ति सेवाएं	http://www.ddugjy.gov.in/ http://ujwalbharat.gov.in/ http://powermin.nic.in/hi http://www.vidyut pravah.in/	विद्युत आपूर्ति की स्थिति, विद्युत अवसंरचनाएं, नवीन परियोजनाएं आदि सभी की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है।

* उपरोक्त में से कुछ वेबसाइटें नयी हैं तो कुछ पहले ही लांच की जा चुकी थीं। पुरानी वेबसाइटों को रिलांच कर इनके अर्थ निष्पादन में सहजता लाने का प्रयास हाल में किया गया है।

ई-शासन में जनसंवाद और सुगमता

लोक और तंत्र के बीच संवाद का सुगम होना लोकतंत्र को मजबूत बनाने में बड़ा कारक है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत राइट टू पीएम विकल्प के जरिए जनसंवाद का एक अभूतपूर्व मंच उपलब्ध कराया है। भारत जैसे एक विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए यह प्रधानमंत्री से संवाद का यह ऑनलाइन विकल्प इस लिहाज से भी कहा जा सकता है क्योंकि भारत के आमजन की अवधारणा में यह कल्पना की भी बात नहीं थी कि वे प्रधानमंत्री को सीधा पत्र लिखेंगे और उसपर त्वरित कार्रवाई होगी। इसके लिए

बाकायदे एक वेब माध्यम (<http://pmindia.gov.in/en/interact-with-honble-pm/>) तैयार किया गया है। इस वेब माध्यम से कोई भी आम अथवा खास व्यक्ति प्रधानमंत्री को समस्या, शिकायत अथवा सुझाव से जुड़े पत्र लिख सकता है। इस पत्र को लिखते ही प्रेषक को एक पंजीकरण नंबर प्रधानमंत्री कार्यालय से ऑनलाइन प्राप्त होता है। उस पंजीकरण नंबर के माध्यम से पत्र लिखने वाले व्यक्ति द्वारा <http://pgportal.gov.in/viewstatus.aspx> पर जाकर अपने शिकायत, सुझाव अथवा समस्या पर हुई कार्रवाई अथवा प्रगति की सटीक एवं आधिकारिक जानकारी प्राप्त की

जा सकती है। इस माध्यम की सबसे अच्छी बात यह है कि यह सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से संबद्ध है एवं वहीं से पत्र के विषय से जुड़े विभागों एवं मंत्रालयों को हस्तांतरित की जाती है। पत्र प्रेषक को उक्त अधिकारी का संपर्क सूत्र भी उपलब्ध कराया जाता है जिसके अधीन उसका मामला है। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री से संवाद का यह विकल्प उस अवधारणा को खंडित करने में मदद कर रहा है, जिसमें आम लोग अक्सर यह मान लेते थे कि उनकी सुनवाई प्रधानमंत्री तक संभव ही नहीं है। इस ऑनलाइन माध्यम की गंभीरता और सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है

कि अनेक बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रों का जिक्र किया है जो उन्हें इस ऑनलाइन माध्यम से लिखे गए हैं। आधुनिक तकनीक के माध्यम से स्थापित नवोन्मेषी प्रणाली ने कहीं कहीं पारदर्शिता के साथ शासकीय व्यवस्था में जनसंवाद की संभावना को मजबूत करने का काम किया है। हालांकि इसके अतिरिक्त नरेंद्र मोदी मोबाइल एप के माध्यम से भी प्रधानमंत्री जनता से संवाद को प्राथमिकता देते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त अन्य मंत्रालयों में भी जन-भागीदारी को तरजीह दी जा रही है। रेल मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया फीडबैक सिस्टम पर खास जोर दिए जाने से सुधारों को नई दिशा मिलती दिख रही है एवं जनता में भी आत्म विश्वास बढ़ता नजर आ रहा है।

सरकार ई-शासन में कृषि क्षेत्र को भी जोड़ने की दिशा में तमाम कार्य कर रही है। लिहाज ग्रामीण अंचल को ई-शासन से जोड़ने के लिए यह साक्षरता मिशन बेहद अनिवार्य है। कृषि के क्षेत्र को भी ई-शासन के माध्यम से मजबूत करने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा तेजी से किया जा रहा है। यह बेशक एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है लेकिन सरकार जिस ढंग कार्य कर रही है उससे यह उम्मीद जताई जा सकती है कि इसका सकारात्मक परिणाम भविष्य में देखने को मिलेगा।

ई-शासन और डिजिटल साक्षरता

डिजिटल इंडिया को सफल बनाने एवं निचले स्तर तक सरकार के ई-शासन की पहुंच को सुलभ करने में जो सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है वो ग्रामीण अंचल के लोगों को अत्याधुनिक डिजिटल उपकरणों एवं एप आदि के लिहाज से साक्षर बनाना है। चूंकि, जब तक देश का हर आम व्यक्ति ई-शासन की तकनीकी प्रक्रिया को समझने

(पृष्ठ 24 से जारी ...)

ईरान में चाबहार बंदरगाह के निर्माण के लिए अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दो प्रमुख गलियारों की प्रगति को गति दी जा रही है जिनमें भारत, ईरान और मध्य एशिया को जहाज, रेल-सड़क मार्ग के जरिए जोड़ने वाले अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारे

में सक्षम नहीं होगा तबतक इन ई-शासन से जुड़े तमाम प्रयासों का पूरा लाभ मिलना संभव नहीं है। इस दिशा में सरकार राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रशिक्षण देने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत 10 लाख लोगों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लोगों को मोबाइल एप एवं वेब-पोर्टल्स आदि से जुड़ी जानकारी दी जाएगी एवं उसके उपयोग के लिहाज से उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा।

चूंकि सरकार ई-शासन में कृषि क्षेत्र को भी जोड़ने की दिशा में तमाम कार्य कर रही है। लिहाज ग्रामीण अंचल को ई-शासन से जोड़ने के लिए यह साक्षरता मिशन बेहद अनिवार्य है। कृषि के क्षेत्र को भी ई-शासन के माध्यम से मजबूत करने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा तेजी से किया जा रहा है। यह बेशक एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है लेकिन सरकार जिस ढंग कार्य कर रही है उससे यह उम्मीद जताई जा सकती है कि इसका सकारात्मक परिणाम भविष्य में देखने को मिलेगा। सरकार ने <http://mkisan.gov.in/hindi/> वेबसाइट के माध्यम से किसानों के हितों से जुड़ी तमाम जानकारियों को बिना इंटरनेट के भी उनके मोबाइल पर उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया है। इस पोर्टल का लक्ष्य एसएमएस पोर्टल की अवधारणा पर केंद्रित है जो मोबाइल टेलीफोनी की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए किसानों के बीच उचित समय पर, विशिष्ट एवं समग्र जानकारी पहुंचाने की दिशा में काम कर रहा है। चूंकि गांवों में किसानों के पास अभी इंटरनेट की न तो उपलब्धता है और न ही व्यापक स्तर पर समझ ही बन पाई है, लिहाजा किसानों के हितों से जुड़े इस वेब पोर्टल को मोबाइल संदेश एवं मोबाइल कॉल आधारित बनाया गया है। हालांकि <http://agricoop.nic.in/> एवं <http://www.soilhealth.dac.gov.in/> आदि के माध्यम से कृषि क्षेत्र को भी ई-सेवा से जोड़ने का पूरा प्रयास किया गया है।

और भारत-म्यांमार-थाईलैंड राजमार्ग शामिल हैं जिनसे भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों को काफी लाभ मिलेगा।

संक्षेप में गत 22 महीनों के दौरान सक्रिय और व्यावहारिक कूटनीति ने राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को बढ़ावा देने का कार्य किया है, इससे विश्वव्यापी क्षितिज

कहीं न कहीं जब शासकीय तंत्र में जनसंवाद की प्रक्रिया सुगम होगी तो पारदर्शिता में बढ़ोत्तरी होना स्वाभाविक ही है। वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया के माध्यम से डिजिटल इंडिया की प्रक्रिया को बहुत तेज रफ्तार से विस्तार दिया जा रहा है। सरकार का यह प्रयास स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि शासकीय कार्यों से जुड़े सभी क्षेत्रों को पूर्णतया ऑनलाइन करके शासन को जटिल की बजाए आसान बनाया जाय। इस दिशा में सरकार काफी सफलता से आगे बढ़ती दिख रही है। इसमें कोई शक नहीं कि जब शासकीय कार्यों में जनसंवाद को बढ़ावा मिलता है तो स्वाभाविक रूप से पारदर्शिता स्थापित होती है एवं शासन सुगमता से संचालित होता है। राष्ट्रीय ई-शासन के माध्यम से पारदर्शिता, जनसंवाद एवं सुगमता तीनों ही लक्ष्यों को

राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रशिक्षण देने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत 10 लाख लोगों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लोगों को मोबाइल एप एवं वेब-पोर्टल्स आदि से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी एवं उसके उपयोग के लिहाज से उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा।

आसानी से और कम समय में हासिल किया जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर इसके लक्षण खुलकर सामने आ चुके हैं। भविष्य में इसके और सुदृढ़ होने की उम्मीद है। □

संदर्भ

1. http://www.doitc.rajasthan.gov.in/_layouts/15/Doitc/User/ContentPage.aspx?LangID=Hindi&Id=285
2. <http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=48495>
3. <http://hi.vikaspedia.in/e-governance/>
4. <http://hi.vikaspedia.in/e-governance/online-citizen-services/online-transport-services>

पर भारत की मौजूदगी बढ़ी है और एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में भारत की प्रतिष्ठा और कद ऊंचा हुआ है। इससे अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत के लिए सकारात्मक योगदान देना और विभिन्न चर्चाओं को आकार देना संभव हुआ है। □

सिविल सेवा परीक्षा 2016

हेतु उपयोगी पुस्तकें

<p>Price: ₹ 330/-</p> <p>Price: ₹ 395/-</p> <p>Price: ₹ 395/-</p> <p>Price: ₹ 295/-</p> <p>Price: ₹ 525/-</p> <p>Price: ₹ 295/-</p>	<p>Price: ₹ 450/-</p> <p>Price: ₹ 425/-</p> <p>Price: ₹ 595/-</p> <p>Price: ₹ 725/-</p> <p>Price: ₹ 725/-</p> <p>Price: ₹ 345/-</p>
<p>ISBN: 9781259064166</p> <p>ISBN: 9789385880179</p> <p>ISBN: 9789339205140</p> <p>ISBN: 9789339222734</p> <p>ISBN: 9789339204204</p> <p>ISBN: 9789352601844</p>	<p>ISBN: 9789339217754</p> <p>ISBN: 9780071329477</p> <p>ISBN: 9789339222710</p> <p>ISBN: 9780071329248</p> <p>ISBN: 9780071074919</p> <p>ISBN: 9789339220358</p>

राज्य लोक सेवा की परीक्षाओं हेतु उपयोगी पुस्तकें

<p>शीघ्र प्रकाशित</p> <p>Price: ₹ 280/-</p> <p>Price: ₹ 350/-</p> <p>Price: ₹ 395/-</p> <p>Price: ₹ 285/-</p>
<p>ISBN: 9789385965975</p> <p>ISBN: 9781259064357</p> <p>ISBN: 9789339223236</p> <p>ISBN: 9789339220075</p> <p>ISBN: 9789385965906</p>

Prices are subject to change without prior notice.

मैक्रॉ हिल एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

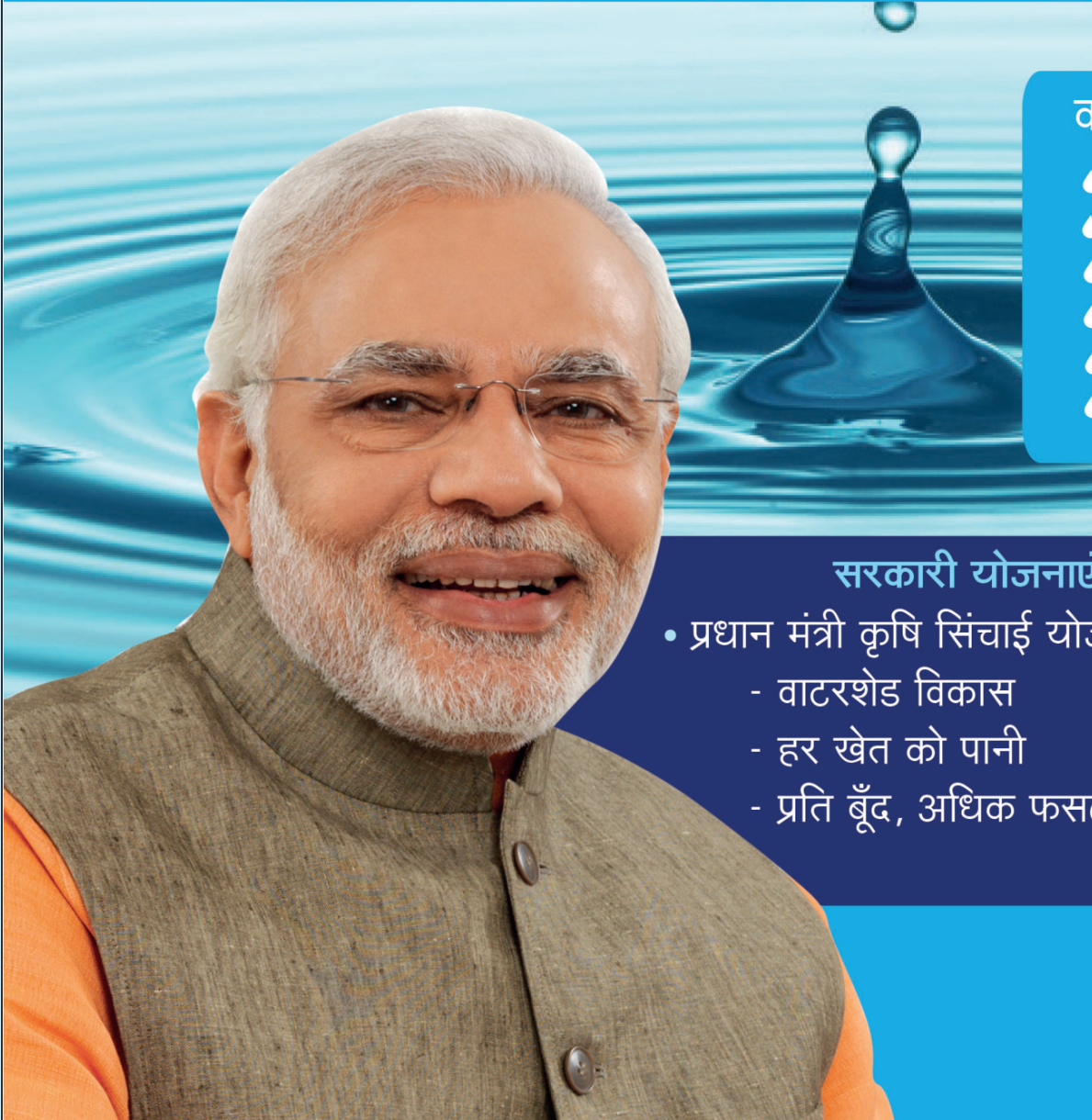
बी-4, सैक्टर-63, जनपद गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201 301



संपर्क करें @ [f /McGrawHillEducationIN](https://www.facebook.com/McGrawHillEducationIN) [/mheducationIN](https://www.twitter.com/mheducationIN) [/company/mcgraw-hill-education-india](https://www.linkedin.com/company/mcgraw-hill-education-india)
टोल फ्री नं०: 1800 103 5875 | ई-मेल: reachus@mheducation.com | खरीदें @ www.mheducation.co.in

"क्या हम गाँव-गाँव पानी बचाने के लिये,
- प्रधानमंत्री के 'मन की बात'

सभी जागरूक नागरिकों, एनजीओ, युवा
स्थानीय शहरी संस्थाओं
सूखे की स्थिति से निपटने के लिए अगले ४-६ हफ्तों
सहयोग करें - सह-निर्माण



- सरकारी योजनाएं
- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना
- वाटरशेड विकास
- हर खेत को पानी
- प्रति बूँद, अधिक फसल

एक अभी से अभियान चला सकते हैं!"
संबोधन में राष्ट्र को संदेश

पुत्रा संगठनों, कृषि समुदायों, पंचायतों,
ओं का तत्काल आह्वान

में एकजुट हों और जल संरक्षण गतिविधियां प्रारंभ करें
र्माण करें - संरक्षण करें

र्षा ऋतू से पूर्व अपने क्षेत्र में निम्नलिखित गतिविधियाँ चलायें:

- तालाब की खुदाई और टंकियों का निर्माण / मरम्मत
- भूजल पुनर्भंडारण संरचना निर्माण
- वर्षा जल संचयन हेतु संरचना निर्माण
- नहर की लाइनिंग बनाना / पानी के चैनल (प्रवाह मार्ग) का सुधार कार्य
- चेक डैम का निर्माण
- वनारोपण / पेड़-पौधे लगाने की तैयारी

जिनसे उपरोक्त गतिविधियों को जोड़ा जा सकता है

जना

ल उत्पादन

- मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार कार्यक्रम
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन



सत्यमेव जयते

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
ग्रामीण विकास मंत्रालय

davp 35301/13/0002/1617

सूखा प्रबंधन में कदमताल की कोशिश

अरविंद कुमार सिंह



आपदा प्रबंधन यूं तो राज्य सूची का विषय है, किंतु केंद्र सरकार ने हाल में इसमें नई सोच का प्रदर्शन करते हुए सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया है। इस वर्ष सजगता बरतते हुए न सिर्फ राज्यों को ससमय वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं बल्कि मराठवाड़ा जैसे क्षेत्र में रेल के जरिए पानी भेजकर हालात संभालने के लिए यथासंभव तालमेल बिठाने के प्रयास किए गए हैं। कृषि एवं किसान मंत्रालय तथा भारतीय मौसम विभाग के बीच समन्वय भी इस दिशा में अहम है। हालांकि इन कोशिशों के परिणाम दूरगामी होंगे, अतः इनका अनुभव करने के लिए धैर्य रखना होगा

लगातार दो वर्षों से मानसून विफल होने के कारण देश का एक बड़ा हिस्सा भयानक सूखे से प्रभावित है। खास तौर पर ग्रामीण अंचलों में पेयजल के साथ कृषि उत्पादन को काफी झटका लगा है। इस समय भारत में 13 राज्य सूखे की चपेट में हैं, लेकिन 10 राज्यों के 256 जिलों में करीब 33 करोड़ लोग इससे सबसे अधिक प्रभावित हैं। जहां स्थिति थोड़ी सामान्य थी वहां भी इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। सूखे से भी अधिक पेयजल संकट ने नागरिकों को परेशान किया है। इस समय देश के 313 जिलों में 1,58,205 गांव और 4.44 लाख बसावटें इसकी चपेट में हैं। मराठवाड़ा और बुंदेलखंड के सूखे ने इस बार थार के सूखे से भी भयानक तस्वीर पेश की है।

खराब मानसून, जलाशयों में पानी की कमी और भूमिगत जल-स्तर में कमी के कारण सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत देना किसी गंभीर चुनौती से कम नहीं है। लेकिन इस बार सूखे में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों और अग्रिम तैयारियों के नाते कई सकारात्मक असर दिख रहे हैं। इन कदमों से सूखे का सामना करने के लिए राज्यों को तैयार करने में काफी मदद मिली है। अन्यथा जितने बड़े दायरे में सूखे का प्रकोप रहा है उसका बहुत ही बुरा असर सामने आ सकता था। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसके आलोक में भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

मराठवाड़ा का लातूर जिला भयावह जल संकट से कराह उठा और उसकी खौफनाक

तस्वीर ने सबको डरा दिया। हालात को गंभीरता से लेते हुए प्रधानमंत्री के स्तर पर इसकी समीक्षा के साथ ही रेलगाड़ी से वहां पानी देने का फैसला किया गया। इसका तत्काल यह असर हुआ कि जो शहर पलायन के लिए तैयार खड़ा था वहां स्थिति कुछ दिनों में सामान्य हो गई। भले ही आज यह शहर टैंकरों से मिलने वाले पानी पर आश्रित है, लेकिन वहां के लोगों ने जल संकट से एक सबक ले लिया है। और जल संचय के सभी संभावित उपायों के साथ नई तैयारी में जुट गए हैं।

सूखा या दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से निपटना प्राथमिक तौर पर राज्यों का विषय है। भारत सरकार उन्हें वित्तीय सहायता और जरूरत होने पर संभार तंत्र संबंधी सहायता प्रदान करती है। अगर कहीं हालात चेन्नई जैसे हुए तो तत्काल केंद्रीय बलों और सेना तक की तैनाती का फैसला होता है। लेकिन इस समय सूखे से निपटने के लिए केंद्र ने काफी सजगता से काम किया।

बिगड़े हालात और सजग पहल

इस बार का सूखा काफी गंभीर है क्योंकि स्थिति बहुत असामान्य है। एक के बाद एक लगातार तीन वर्षों से फसल बर्बाद होने और पानी की अत्याधिक कमी वाले ग्रामीण इलाकों में स्थिति काफी दयनीय है। 2015-16 में की तुलना में 2014-15 में पांच राज्यों के 107 जिले सूखा प्रभावित थे। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून के विफल होने या बारिश कम होने के कारण सूखे की स्थिति बनती है। बारिश का अत्याधिक अस्थायी स्वरूप, स्थानीय स्तर पर इसमें परिवर्तन जैसे कई कारण सूखे की भयावहता बढ़ाते हैं।

लेखक राज्य सभा टीवी में वरिष्ठ सहायक संपादक, रेल मंत्रालय के पूर्व सलाहकार और कृषि, संचार और परिवहन क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय की परियोजना के तहत भारत के अंतर्देशीय जल परिवहन के इतिहास के लेखक। गत वर्ष उन्हें चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ईमेल: arvindksingh.rstv@gmail.com

कृषि मंत्रालय के सूखा प्रबंधन प्रभाग द्वारा तैयार सूखा संकट प्रबंधन योजना 2015 बताती है कि देश के 68 फीसदी बुवाई क्षेत्र में अलग-अलग भयावहता वाले सूखे की संभावना रहती है। पिछले 10 में से चार वर्षों के दौरान बारिश अस्थिर रही है। वहीं जनसंख्या में वृद्धि, तीव्र औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, फसल सघनता, गिरते भूजल जैसे कारणों से प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में कमी आ रही है। आगे समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं।

हालांकि सूखा सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है लेकिन कृषि क्षेत्र पर इसका सबसे अधिक असर पड़ता है। इन सारे पहलुओं की समीक्षा करते हुए केंद्र ने अधिक सजगता दिखाई। भारत सरकार ने सबसे पहले कर्नाटक

सूखा सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है लेकिन कृषि क्षेत्र पर इसका सबसे अधिक असर पड़ता है। इन सारे पहलुओं की समीक्षा करते हुए केंद्र ने अधिक सजगता दिखाई। भारत सरकार ने सबसे पहले कर्नाटक को 1540 करोड़ और छत्तीसगढ़ को 1274 करोड़ रुपये की मदद जारी की। केंद्रीय टीमों ने यहां का दौरा करके हालात का जायजा लिया।

को 1540 करोड़ और छत्तीसगढ़ को 1274 करोड़ रुपये की मदद जारी की। केंद्रीय टीमों ने यहां का दौरा करके हालात का जायजा लिया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई जिसने सारे पक्षों पर लगातार निगाह रखते हुए राज्यों को सहायता देने और वहां की स्थिति की समीक्षा का काम जारी रखा है। सूखे से निपटने के लिए भारत सरकार अब तक राज्यों को 10,275 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है।

मौसम विभाग से तालमेल

वास्तव में केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने अप्रैल, 2015 में भारतीय मौसम विभाग द्वारा मानसून के बारे में की गई भविष्यवाणियों के तुरंत बाद कई कदम उठाए थे। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के साथ राज्यों की मदद से सरकार ने 600 जिलों के लिए एक आकस्मिकता योजना तैयार की। इसी के आधार पर राज्य सरकारों के साथ साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस के

जरिए खेती-बाड़ी से संबंधित जरूरी मसलों पर लगातार संवाद बनाए रखा गया। साथ ही फसली मौसम निगरानी समूह की साप्ताहिक बैठकें आयोजित की गईं। राज्यों को सूखा प्रतिरोधक बीजों की उचित मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई। यही कारण था कि समग्र रूप से कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से बच गया। हालांकि कई इलाकों में खेती-बाड़ी को झटका लगा है लेकिन कुल मिला कर स्थिति नियंत्रण में रही।

मुआवजा के नये नियम

बीते साल भारत सरकार ने किसानों और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सहायता के लिए नियमों में भी बदलाव किया। लंबे समय से किसान मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सरकार ने किसानों को मिलने वाले मुआवजे में 50 फीसदी की बढ़ोत्तरी करते हुए 8 अप्रैल, 2015 को मापदंडों में संशोधन किया। इससे राज्यों को दी जाने वाली राशि में काफी बढ़ोत्तरी हुई। पहले सरकार 50 फीसदी फसलों के नुकसान होने पर ही किसानों की राहत देती थी, जिसे घटा कर 33 फीसदी नुकसान पर राहत देना तय किया गया है। वर्षा सिंचित इलाकों में प्रति हेक्टेयर सहायता 4,500 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये और सिंचित इलाकों में 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ा कर 13,500 रुपये कर दिया गया। इसी तरह प्राकृतिक आपदाओं में मृत्यु के मामले में अनुग्रह राशि 1.5 लाख से बढ़ाकर चार लाख रुपये कर दी गई। इससे बड़ी संख्या में किसान राहत से लाभान्वित हुए।

इसी तरह भारत सरकार से राज्य आपदा कोष को दी जाने वाली धनराशि में भी काफी बढ़ोत्तरी की गई। मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के पहले के पांच वर्षों में राज्यों को 33580.93 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ था लेकिन भारत सरकार ने 2015-16 में इस कोष से राज्यों को पांच वर्षों के लिए आवंटन बढ़ाकर 61 हजार 219 करोड़ कर दिया।

अतीत के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि राज्य सरकारों ने भारत सरकार से 2010-11 से 2013-14 के बीच के चार वर्षों में आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा कोष से एक लाख करोड़ रुपये की मांग की थी। लेकिन केंद्र से राज्यों को 13,762 करोड़ रुपये की स्वीकृत दी गई थी। वित्त वर्ष 2014-15 में राज्यों राष्ट्रीय आपदा कोष

से 42 हजार करोड़ रुपये की राशि की मांग की और सरकार ने 9017.99 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि आवंटित की। वहीं 2015-16 में राज्यों को 13773.34 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई। इस तरह कुल मिला कर राज्यों को बेहतर मदद मिलने से सूखा राहत के कामों में धन की कमी आड़े नहीं आ पाई। खरीफ मौसम 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है जिसमें अब तक का सबसे कम प्रीमियम रखा गया है। इस योजना से भी किसानों का जोखिम कम होगा। बीमा सुरक्षा को 23 फीसदी से 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। इस कदम का भी सकारात्मक असर होना है।

वास्तव में केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने अप्रैल, 2015 में भारतीय मौसम विभाग द्वारा मानसून के बारे में की गई भविष्यवाणियों के तुरंत बाद कई कदम उठाए थे। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के साथ राज्यों की मदद से सरकार ने 600 जिलों के लिए एक आकस्मिकता योजना तैयार की।

पेयजल व खाद्यान्न प्रबंधन

भारत सरकार ने पेयजल संकट का सामना कर रहे गांवों में हैंडपंपों की मरम्मत से लेकर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को सभी सूखा प्रभावित राज्यों में कार्यान्वित करने से सभी वर्गों को काफी राहत मिली है। इसी तरह दोपहर का भोजन योजना को गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी जारी रखना एक अहम फैसला माना जा रहा है। अधिकांश राज्यों को इससे संबंधित सहायता प्रदान कर दी गई है। इसी तरह मनरेगा में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 100 दिन से बढ़ाकर काम के दिन 150 करने से भी पलायन रोकने में मदद मिली है। केंद्र ने 7 अप्रैल, 2016 को सभी राज्यों को सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अप्रैल से जून तक कार्य की गति बनाए रखने को कहा गया है। *दीनदयाल अंत्योदय मिशन* के तहत भी सूखा प्रभावित क्षेत्रों को राहत मिल रही है।

इन कदमों के साथ भारत सरकार ने सूखा रोधी उपायों और जल संरक्षण के लिए भी कई पहल की है। *पनधारा* संबंधित कार्यक्रमों के

लिए 2015-16 के दौरान सूखा प्रभावित राज्यों को 1,064.23 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। मानसून पूर्व तैयारियों के तहत भी कई उपाय किए गए हैं। जिला स्तरीय योजनाएं तैयार कर पेयजल और चारे की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए भी ठोस योजना तैयार की गई है। केंद्रीय योजनाओं से राज्यों को यथासंभव मदद की पेशकश की गई है। प्रधानमंत्री स्वयं मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर राज्य स्तर पर स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। अन्य वर्षों की तुलना में तेजी से फैसले हो रहे हैं।

इसी तरह भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के स्तर पर भी जल संकट और सूखा ग्रस्त क्षेत्रों की स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है। सभी सूखा ग्रस्त राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक कर कृषि, ग्रामीण विकास, पेयजल, पशुपालन, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, जल संसाधन, गृह, वित्त और रेलवे जैसे महत्वपूर्ण

वर्षा सिंचित इलाकों में प्रति हेक्टेयर सहायता 4,500 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये और सिंचित इलाकों में 9,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ा कर 13,500 रुपये कर दिया गया। इसी तरह प्राकृतिक आपदाओं में मृत्यु के मामले में अनुग्रह राशि 1.5 लाख से बढ़ाकर चार लाख रुपये कर दी गई। इससे बड़ी संख्या में किसान राहत से लाभान्वित हुए।

विभागों और मंत्रालयों को पहले से ही सजग किया गया है। मुख्य सचिवों के साथ हुई बैठक के बार भारत सरकार ने कई नए कदम उठाए। इससे चारा उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलने के साथ पेयजल, रोजगार और दूसरे मोर्चों पर राहत मिली। सरकार ने राहत देने के लिए रेलवे और पानी के टैंकों के जरिए जल आपूर्ति जारी रखने और विभिन्न राज्यों को राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 292 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। चारा विकास कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अलग से 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। अधिक चारा उपलब्धता वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में चारा ले जाने के लिए रेलवे मंत्रालय से सहयोग लिया जा रहा है।

पहले राज्यों की ओर से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजे जाते थे, जिसके बाद टीमें भेजने के साथ सहायता तय करने में लंबी प्रक्रिया चलती थी लेकिन अब केंद्र सरकार स्वयं राज्यों से

संवाद कर सूखा प्रभावित जिलों की संख्या और जमीनी हकीकत के बारे में जानकारी जुटा रही है। इसी के तहत केंद्रीय दल स्थिति का जायजा लेने और आवश्यक सहायता का आकलन करने के लिए राज्यों का दौरा कर रहे हैं।

सूखा और अर्थव्यवस्था

यह ध्यान रखने की बात है कि सूखे का कृषि उत्पादन पर भयावह असर पड़ता है। भारत जैसे देश जहां प्राथमिक तौर पर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है वहां एक सूखा करीब-करीब सभी क्षेत्रों पर असर डालता है। यह अलग बात है कि जीडीपी में खेती का योगदान कम होता जा रहा है लेकिन यह 50 फीसदी से अधिक आबादी को अभी भी आजीविका प्रदान कर रही है इस नाते कई लिहाज से अहम है। खेती मानसून पर निर्भर है। ऐसे में कमजोर मानसून होने पर सीधा असर एक बड़ी आबादी पर होता है। सबसे निचले पायदान पर खड़े देहात के गरीब और कमजोर वर्ग पर सबसे अधिक चोट लगती है। साथ ही छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका सुरक्षा प्रभावित होती है।

सूखे का एक और प्रतिकूल असर कृषि वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से होता है। हालांकि इसमें किसान का कोई फायदा नहीं होता लेकिन बिचौलिए सूखे जैसी आपदाओं का खूब फायदा उठाते हैं और जमाखोरी की आशंका रहती है। हालांकि सरकार ने जमाखोरों से निपटने की दिशा में काफी काम किया है। फिर भी सूखे और खाद्य सुरक्षा के बीच घनिष्ठ संबंध है। खास तौर पर छोटे किसान इससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। सूखे से कुछ और क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है जैसे:

- कृषि क्षेत्र में रोजगार में कमी
- पेयजल, अनाज और चारे की कमी
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बुरा असर
- कृषि उत्पादों और पशु उत्पादों पर असर
- ग्रामीणों की क्रय शक्ति पर असर
- आजीविका पर असर और पलायन
- जल संकट से कृषि और सहयोगी गतिविधियों पर असर

सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, जिसे पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है। फिर भी समय पर अग्रिम तैयारी करके इसके प्रभाव को सीमित किया जा सकता है। साथ ही प्रभावित आबादी और खास तौर पर किसानों को राहत

दी जा सकती है। इस दिशा में बेशक केंद्र सरकार ने पहल की। लेकिन असली नतीजे नीचे के स्तर पर क्रियान्वयन से जुड़ी मशीनरी पर निर्भर होते हैं। इसका प्राथमिक दायित्व राज्य सरकारों पर होता है। लेकिन इससे परे कुछ और कदम उठाने की भी जरूरत है।

समाधान के अभिनव कदम

प्रधानमंत्री ने *मन की बात* कार्यक्रम में देश के नागरिकों से जल संचय की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अच्छी बारिश की संभावना को अवसर के साथ चुनौती के रूप में लेना चाहिए और पानी बचाने के लिए गांव-गांव अभियान चलाना चाहिए। बेशक इससे भूजल स्तर ऊपर आएगा और पानी की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। ऐसे होने पर कृषि उत्पादकता भी बढ़ेगी।

पहले राज्यों की ओर से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजे जिसके बाद टीमें भेजने के साथ सहायता तय करने में लंबी प्रक्रिया चलती थी लेकिन अब केंद्र सरकार स्वयं राज्यों से संवाद कर सूखा प्रभावित जिलों की संख्या और जमीनी हकीकत के बारे में जानकारी जुटा रही है। इसी के तहत केंद्रीय दल स्थिति का जायजा लेने और आवश्यक सहायता का आकलन करने के लिए राज्यों का दौरा कर रहे हैं।

केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूजल बोर्ड की तकनीकी टीमों को भी देश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल की स्थिति का मौके पर अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। इनके अध्ययन के आधार पर एक दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार करने के संबंध में भी सरकार ने तैयारी की है।

यह ध्यान रखने की बात है कि हमारे देश में 141 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 55 फीसदी वर्षा सिंचित है। इन इलाकों में जल संचय की दिशा में कई कोशिशें की जा रही हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आवंटन 5700 करोड़ रुपये कर करने के साथ इस बार मनरेगा के तहत पांच लाख खेत तालाब बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। साथ ही पांच वर्षों में लंबित पड़ी 86 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तय किए गए हैं। इनमें से 46 परियोजनाएं दो साल में पूरी होंगी जबकि मार्च 2017 तक

(जारी ... पृष्ठ 41 पर)

समकालीन भारतीय संदर्भ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

दिशा नवानी



किसी भी देश के विकास में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बिना गुणवत्ता शिक्षा के किसी भी देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। ऐसे में सरकार को शिक्षा में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निजी संस्थानों के साथ-साथ सरकारी संस्थानों में भी दी जानी चाहिए। हालांकि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नई-नई योजनाएं लागू कर रही है जो सराहनीय है। उम्मीद की जानी चाहिए कि समावेशी विकास का लक्ष्य हासिल करने में ये योजनाएं कारगर होंगी

भारतीय शिक्षा प्रणाली एक विडंबनात्मक स्थिति में है। हमारे यहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने और रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और उपलब्धियां हासिल करते हैं। दूसरी ओर ऐसे स्कूली विद्यार्थी भी हैं जोकि बुनियादी साक्षरता और कौशल हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी हाशिए पर रह जाते हैं जिनके कारण उनकी स्कूली शिक्षा विशेष रूप से अर्थहीन रह जाती है। इन दोनों प्रकार के विद्यार्थियों में जबरदस्त असमानता है। केवल परीक्षा पास करने के उद्देश्य से निर्धारित पाठ्यपुस्तकों से यंत्रवत रूप से संदर्भरहित तथ्यों और सूचनाओं को याद कर लिया जाता है। संज्ञानात्मकता (और वह भी स्मृति से जुड़ी) पर अधिक जोर दिया जाता है और व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं को नजरंदाज कर दिया जाता है। यह दिलचस्प है कि अब बच्चों को सार्थक शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों, विभिन्न विचारकों के कार्य एवं अनुसंधान अध्ययन से संबंधित सुझाव भी प्रस्तावित किए जा रहे हैं। जहां भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की प्रकृति चिंता का विषय है, वहीं बच्चों को उनकी सामाजिक स्थिति के आधार पर भिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं।

एकाधिक पहचान (जाति, वर्ग, धर्म, जनजाति, लिंग आदि) वाले बच्चे हमारे विविध और असमान समाज में विभिन्न स्तरों पर पाए जाते हैं। इन बच्चों के सामाजिक स्थानों और उनके स्कूलों में समकालिकता पाई जाती है। ऐसे स्कूल भी हैं जहां अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं और

योग्य एवं सक्षम शिक्षक हैं जोकि विशेषाधिकार प्राप्त सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी के समानांतर ऐसे स्कूल भी हैं जो सभी स्तरों पर संघर्ष कर रहे हैं- वहां बुनियादी सुविधाएं अपर्याप्त हैं, अक्षम और निरुत्साहित शिक्षक हैं और विद्यार्थी भी अनिच्छुक एवं अनियमित हैं। हमारे यहां सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में शिक्षा के कई स्तर हैं और भिन्न-भिन्न स्तरों पर औपचारिक शिक्षा प्रणाली अपना कार्य कर रही है। साथ ही औपचारिक शिक्षा से बाहर गैर-औपचारिक शिक्षा (एनएफई) प्रणाली भी विस्तार ले रही है।

हमारी शिक्षा प्रणाली की कमियों की आलोचना अक्सर होती रहती है। अनेक सर्वेक्षणों से इन कमियों के बारे में जानकारी मिलती रहती है। राष्ट्रीय (राज्य और गैर राज्य) और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां स्कूली विद्यार्थियों के प्रदर्शन से संबंधित सर्वेक्षण करते हैं जिनमें इन कमियों को उजागर किया जाता है। वैसे गुणवत्ता, समानता और सामाजिक न्याय के मुद्दे परस्पर एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को केवल कुछ क्षेत्रों के बच्चों तक सीमित नहीं किया जा सकता। गुणवत्ता (पाठ्यक्रम से लेकर शिक्षकों एवं बुनियादी ढांचा आदि तक की गुणवत्ता) का अर्थ यह है कि सभी बच्चों और स्कूलों को अच्छी शिक्षा मिले। गुणवत्ता की प्रकृति समावेशी होनी चाहिए। इसे इस प्रकार समावेशी होना चाहिए जिसमें सभी को सम्मान के साथ एकीकृत किया जाए और कुछ रियायतें देकर एक बड़ी आबादी को बहिष्कृत या अलग-थलग न कर दिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जैसे देश में समान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की प्राथमिक

लेखिका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई के स्कूल ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत सेंटर फॉर एजुकेशन में प्रोफेसर एवं चेयरपर्सन पद पर कार्यरत हैं। ईमेल: dishanawani@yahoo.com

जिम्मेदारी निजी कंपनियों की न होकर, सरकार की होनी चाहिए क्योंकि निजी कंपनियां मुनाफे की तलाश में शिक्षा के क्षेत्र में उतरती हैं। नब्बे के दशक में संरचनात्मक समायोजन की नीति ने नव-उदारवादी वातावरण का निर्माण किया जिसने शिक्षा के क्षेत्र में भी दखल किया। कम लागत वाली कई निजी कंपनियों ने इस क्षेत्र में पदार्पण किया जोकि कम कीमत पर उन लोगों को शिक्षा प्रदान करती हैं जो आम तौर पर मुफ्त सरकारी स्कूलों में जाते हैं और जिनका अपने बच्चों को मिलने वाली शिक्षा से मोहभंग हो गया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

इस संदर्भ में बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) की सराहना की जानी चाहिए जिसने वर्ष 2009 में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया। यह अधिनियम 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को सुनिश्चित करता है। इस अधिनियम में स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के कई प्रावधान हैं जैसे विद्यार्थी शिक्षक अनुपात (पीटीआर) से संबंधित मानदंड और मानक, इमारत और बुनियादी ढांचा, स्कूल के कार्य दिवस, शिक्षक के कार्य के घंटे, जनगणना, संसद, राज्य विधायिका एवं स्थानीय निकायों के चुनाव और आपदा राहत के अतिरिक्त गैर शैक्षिक कार्य के लिए शिक्षकों की तैनाती का निषेध, योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति और शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न का निषेध, शिक्षकों द्वारा बच्चों के दाखिले की प्रक्रिया की स्क्रिनिंग, कैपिटेशन फीस, शिक्षकों द्वारा निजी शिक्षण और मान्यता रहित स्कूलों का संचालन का निषेध। हालांकि इस अधिनियम के प्रावधान मूल रूप से सराहनीय हैं, यह भी महत्वपूर्ण है कि उन्हें पूरी ईमानदारी और जवाबदेही के साथ लागू किया जाए।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क, 2005

इन प्रावधानों के अतिरिक्त यह अधिनियम संदर्भपूर्ण, जीवंत और सार्थक पाठ्यक्रम के महत्व को मान्यता देता है। यह ऐसे माहौल में बच्चों के शिक्षण की वकालत करता है जहां उन्हें किसी प्रकार का भय न हो। हमारी सभी शिक्षा नीतियों और हाल के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम

फ्रेमवर्क (एनसीएफ), 2005 में इस बात को स्वीकार किया गया है कि हमारे पाठ्यक्रम और स्कूल बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि जगाने और बच्चों को स्कूल में बरकरार रखने में असफल रहे हैं। यह भी प्रमुख रूप से कहा जाता है कि गुणवत्ता के मुद्दे को स्कूली बच्चों के शैक्षिक अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए और बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने तथा उनके ज्ञान और अनुभवों का निर्माण करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए।

हालिया सरकारी योजनाएं

अक्सर सरकार को राज्य समर्थित संस्थानों में होने वाली सभी गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। हालांकि सरकार सामाजिक कल्याण के कार्यों, जैसे शिक्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है लेकिन हमारी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए सरकार की पहल का विश्लेषण करना भी महत्वपूर्ण है। सरकार ने प्राथमिक से लेकर उच्चतम शिक्षा तक कई

अधिनियम संदर्भपूर्ण, जीवंत और सार्थक पाठ्यक्रम के महत्व को मान्यता देता है। यह ऐसे माहौल में बच्चों के शिक्षण की वकालत करता है जहां उन्हें किसी प्रकार का भय न हो।

योजनाएं शुरू की हैं। ये योजनाएं व्यापक हैं और सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक रूप से जरूरतमंद विद्यार्थियों तथा विशेष जरूरतों वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाती हैं। साथ ही शिक्षा तक पहुंच बनाती हैं एवं पाठ्यक्रम में तथा शैक्षणिक सुधार पर जोर देती हैं। उदाहरण के लिए *बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ* अभियान के तहत उन स्कूल प्रबंधन समितियों को पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान है जो शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर लड़कियों की पढ़ाई जारी रखने में सौ प्रतिशत सफल होते हैं। इसी प्रकार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की पहल *उड़ान* के तहत वंचित छात्राओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के स्कूल उपरांत व्यावसायिक शिक्षा विशेष रूप से विज्ञान एवं गणित के संबंध में आगे बढ़ने में सहयोग किया जाता है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के भौगोलिक अलगाव और उसकी कमियों को देखते हुए उस क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए भी कई योजनाएं

हैं। इस व्यापक समूह तक पहुंचने बनाने और शैक्षणिक कार्य को अधिक गतिशील बनाने के लिए तकनीक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और विद्यार्थियों को शिक्षा के अवसर मुहैया करा रही है। स्वयं (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स) के तहत आईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे संस्थानों के प्रोफेसर विद्यार्थियों को मुफ्त ऑन लाइन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

निश्चित रूप से यह एक सकारात्मक पहल है, खासकर ऐसे संस्थानों की ओर से अब जजों तक पारंपरिक रूप से कुछ विद्यार्थियों का चयन करते रहे हैं। इसी तरह नेशनल ई-लाइब्रेरी एक ऐसा ऑन लाइन पोर्टल है जोकि केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में विकसित की गई गुणवत्तापूर्ण सामग्री को डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध कराता है और जिसे आसानी से लैपटॉप, स्मार्ट फोन और टैबलेट के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। इससे सूचना की लोकतांत्रिक पहुंच बनती है। इसी प्रकार, नेशनल छात्रवृत्ति पोर्टल को एंड टू एंड स्कॉलरशिप प्रोसीजर के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में परिकल्पित किया गया है जहां से विद्यार्थी भारत सरकार द्वारा प्रदान की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं और लाभ की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) की राष्ट्रीय परिषद् के माध्यम से वार्षिक राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण (एनएसएस) का संचालन करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही मंत्रालय देश में स्कूली शिक्षा डाटा के विभिन्न स्रोतों को केंद्रीकृत करने के लिए व्यय पोर्टल को विकसित करने जा रहा है और शिक्षक शिक्षण संस्थानों के लिए एक पोर्टल की शुरुआत करने वाला है जो उनके कार्य में पारदर्शिता और ग्रेडिंग को सुनिश्चित करेगा। देश भर में लगभग 20 करोड़ बच्चों की निगरानी करने वाली एक प्रणाली को भी शुरू किया जा रहा है जो एक से दूसरी कक्षा में जाने पर बच्चे की प्रगति पर नजर रखेगा और ड्रॉप आउट्स को चिह्नित करेगा।

एनसीएफ 2005 की भावना को बरकरार रखते हुए और स्कूली शिक्षा और बाहर की दुनिया में तालमेल बैठाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय आविष्कार

अभियान (आरए) का गठन किया है। यह एक अभिसरण संरचना है, जो जिज्ञासा एवं रचनात्मकता, विज्ञान एवं गणित से प्यार और बच्चों के बीच तकनीक के कारगर उपयोग को पोषित करती है। एनसीईआरटी की ई-पाठशाला एक नूतन विचार है जोकि सभी स्कूली विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण-संसाधनों की निशुल्क और सहज सुविधा प्रदान करता है।

बच्चों एवं युवाओं को शिक्षा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। ये महत्वपूर्ण कदम हैं जिनकी सराहना की जानी चाहिए। फिर भी हमारा ध्यान केवल इन योजनाओं की अवधारणा और कार्यान्वयन पर नहीं रहना चाहिए। इसकी बजाए हमें संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए ताकि स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। पिछले कुछ वर्षों में कई सर्वेक्षणों से पता चला है कि हमारे स्कूली बच्चों, विशेष रूप से सरकारी स्कूलों के बच्चों के शिक्षण का स्तर अच्छा नहीं है। समस्या की गंभीरता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाए हमें बच्चों के सीख न पाने की स्थिति पर चिंता और विचार करना चाहिए। इनमें से

कुछ सर्वेक्षणों में गणना प्रणाली और साक्षरता पर बल दिया गया है जिसे स्कूलों को निश्चित रूप से प्रदान करना चाहिए लेकिन उन्हें बच्चों को अर्थपूर्ण अनुभव भी प्रदान करने चाहिए। इस संदर्भ में यह कहना भी जरूरी है कि आरटीई अधिनियम 2009 में कक्षा आठ तक के बच्चों के गैर निरोध (एडीपी) से संबंधित प्रावधानों को हटा दिया गया है। अब कक्षा आठ तक के बच्चों को फेल होने पर उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। इससे वे बच्चे दंडित होंगे जिनके लिए शिक्षा ग्रहण करना कई कारणों से मुश्किल है। इसी तरह हालांकि शिक्षक, अध्यापन के स्थान से इतर, बच्चों की शिक्षा के लिए जवाबदेह हैं, फिर भी यह भी जरूरी है कि उन्हें पूरा सहयोग दिया जाए और उनके काम में आने वाली संरचनात्मक परेशानियों को दूर किया जाए। हमारे देश के विविध सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में प्रौद्योगिकी भी एक उल्लेखनीय भूमिका निभा सकती है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के स्थान पर टैबलेट और स्मार्ट फोन का उपयोग करना हानिकारक हो सकता है, विशेष रूप से उन

बच्चों की पढ़ाई के लिहाज से जिन्होंने खास देखभाल की जरूरत है।

हालांकि यह योजनाएं उपयोगी हैं, फिर भी समानता, गुणवत्ता और सामाजिक न्याय के मुद्दों का तालमेल इनसे नहीं किया जाना चाहिए। सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा का अधिकार है इसलिए स्कूलों में एक अनुकूल माहौल बनाने का प्रयास करना चाहिए जहां शिक्षक और विद्यार्थी सार्थक शिक्षण का लाभ उठा सकें। स्कूलों को सभी प्रकार के सुधारों की मौलिक इकाई के रूप में कार्य करना चाहिए। एनसीएफ 2005 की भावना के साथ पाठ्यक्रम, शिक्षण और मूल्यांकन संबंधी सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए और आरटीई अधिनियम 2009 को अनेक मोर्चों पर सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान करनी चाहिए। एनडीपी जैसी धाराओं को हटाने की बजाए उसमें संशोधन करने चाहिए। साथ ही 3-6 एवं 14-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को भी इसके दायरे में शामिल किया जाना चाहिए।

संदर्भ

<http://mhrd.gov.in/school-education>
<http://mhrd.gov.in/schemes-school>
<https://www.scholarships.gov.in/>

सस्ते आवासों के लिए धनराशि बढ़ी

आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने महाराष्ट्र, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 73,205 अतिरिक्त मकानों के निर्माण हेतु 9,005 करोड़ रुपये के निवेश को हरी झंडी दिखाई है। महाराष्ट्र को कुल 8,932 करोड़ रुपये की लागत से 10 शहरों में 71,701 मकान बनाने की अनुमति दी गई है, जिसमें 1,064 करोड़ रुपये केंद्र से मिलेंगे। पंजाब को भटिंडा में झुग्गी के स्थान पर पुनर्विकास के लिए 57 करोड़ रुपये की लागत से 1,280 मकानों के निर्माण की मंजूरी मिली है, जिसमें 12.80 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता होगी। जम्मू-कश्मीर में 3.36 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता सहित कुल 16.07 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी द्वारा निर्माण के घटक के अंतर्गत 224 मकानों के निर्माण की अनुमति दी गई

है। इसमें उधमपुर में 141 और बरामूला में 83 मकानों का निर्माण शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के एएचपी और बीएलसी घटकों के अंतर्गत प्रत्येक मकान को 1.50 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी और निजी डेवलपर्स द्वारा मौजूदा जमीन के मुद्रीकरण के जरिए झुग्गी के मूल स्थान पर पुनर्विकास के तहत प्रत्येक मकान के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इन मंजूरीयों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत किरायायती आवासों के लिए अभी तक मंजूर कुल निवेश 43,922 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जिससे शहरी गरीबों के लिए 6,83,724 मकान बनाए जाएंगे, जिनमें 10,050 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता होगी। पिछले वर्ष जून में आरंभ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 2022 के अंत तक शहरी गरीबों के लिए 2 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य है।

(पृष्ठ 38 से जारी ...)

23 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 12,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

खेती में पानी बचाने की दिशा में अभी और गंभीर उपाय करने की जरूरत है। हमारी कुल पानी खपत का 80 फीसदी खेती में हो रहा है। विश्व बैंक के 2011 से 2015 के आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया में सबसे अधिक स्वच्छ जल का उपयोग खेती और घरेलू जरूरतों के लिए कर रहा है। हमसे अधिक आबादी होने के बाद भी चीन हमसे कम स्वच्छ जल का उपयोग करता है। भारत की सालाना

स्वच्छ जल खपत 761 अरब क्यूबिक मीटर पानी की है, जबकि चीन की 554.1 और अमेरिका की 478.40 अरब क्यूबिक मीटर की। इस तस्वीर को बदलने की जरूरत है।

भारत में पिछले छह दशकों में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में 70 फीसदी की गिरावट आई है। भारत में 1951 में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 5177 घनमीटर थी जो 2011 में 1545 घनमीटर रह गई है। आबादी की बढ़त के साथ पानी की जरूरत बढ़ रही है। हमारी आधी से अधिक आबादी भूजल पर निर्भर है।

बीते सात वर्षों में हमारे 54 फीसदी भूजल में गिरावट आई है। अगर गिरावट ऐसे ही जारी रही तो पेयजल के साथ खेती भी संकट में पड़ जाएगी। इस नाते हमें जल संरक्षण के लिए ठोस रणनीति बनाने के लिए युद्धस्तर पर ठोस प्रयासों की जरूरत होगी। गांवों की जीवन रेखा कहे जाने वाले तालाबों और दूसरे जल निकायों के संरक्षण की दिशा में ठोस पहल करने के साथ बहुत से उपाय करने होंगे। तभी हम सूखे की मार के आवेग को कम कर सकेंगे।

सामान्य अध्ययन का सर्वश्रेष्ठ संस्थान, जिसका लक्ष्य आपको सफलता दिलाना है..

I
A
S



P
C
S

Committed to Excellence

ISO 9001 : 2008 Certified

The Most Experienced & Competent Faculties



Aamod Kr. Kanth



Manikant Singh



Prof. Pushpesh Pant



Alok Ranjan



Dr. Abhishek



Neeraj Singh

Managing Director



Abhay Kumar



Dr. M. Kumar



Deepak Kumar



Rameshwar



Dr. V. K. Trivedi



Divyasen Singh

Co-Ordinator

सामान्य अध्ययन

IAS - 2017

दिल्ली केन्द्र

15 JUNE
6:30 PM

29 JUNE
11:30 AM

इलाहाबाद केन्द्र

14 JUNE
8:00 AM

26 JUNE
5:00 PM

लखनऊ केन्द्र

20 JUNE
9:00 AM

27 JUNE
6:00 PM

DELHI CENTRE

705, 2nd Floor, Main Road,
Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Ph.: 011-27658013, 7042772062/63

ALLAHABAD CENTRE

GS World House, Stainly Road,
Near Traffic Choraha, Allahabad
Ph.: 0532-2266079, 8726027579

LUCKNOW CENTRE

A-7, Sector-J, Puraniya Chauraha
Aliganj, Lucknow
Ph.: 0522-4003197, 8756450894

JAIPUR CENTRE

1-A, Dayal Nagar, Near Narayan
Niwas, Gopalpura Bypass, Jaipur
Ph.: 7240717861, 7240727861

<http://www.gsworldias.com>

<http://facebook.com/gsworld1>

WhatsApp No.
9654349902

ताकि कल-कल बहे गंगा-यमुना

गीता चतुर्वेदी



विकास का अर्थ अच्छी सड़कें, पुल, बिजली व्यवस्था आदि ही नहीं होते हैं। संपूर्ण विकास तभी होगा जब प्रकृति के अनुपम उपहार के तौर पर मिली नदियों की भी सुरक्षा की जाए। सरकार नदियों की साफ-सफाई के विषय में गंभीर है और इस दिशा में सुधार के लिए प्रयास भी कर रही है। नदियों की सफाई का ध्यान रखते हुए सरकार ने नमामि गंगे परियोजना शुरू की है। यहां इस बात की ओर ध्यान देना भी आवश्यक है कि गंगा नदी के साथ-साथ उसकी सहायक नदियों की साफ-सफाई की ओर भी ध्यान दिया जाए

पर्यावरणप्रेमियों की बरसों से मांग थी कि गंगा की सहायक नदियों को साफ किए बिना गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। देर से ही सही, जलसंसाधन मंत्रालय को भी यह बात समझ में आई है। गंगा की सबसे बड़ी और पौराणिक नदियों में चार का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। कान्हा के बचपन की अठखेलियों, किशोरावस्था की क्रीड़ाओं और गोपियों के संग रास को लेकर यमुना जन-जन में विख्यात है। गंगा की दूसरी सहायक नदी घाघरा है। त्रेता युग के प्रतापी अयोध्या राज के शासक रघुवंश की संस्कृति की यह नदी गवाह रही है। हिंदुओं के आराध्य राम की क्रीड़ा स्थली रही घाघरा- जिसे आमजन सरयू के रूप में जानता है, संयोगवश अभी गंगा-जमुना जैसी प्रदूषित नहीं है। उस पर कोई बड़ा बांध भी नहीं है। लिहाजा उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा पर जब वह गंगा में विलीन होती है टिहरी के बाद से कृषकाय बन चुकी गंगा में नया आवेग आता है और यहीं से उसका प्रदूषण भी कम होता है। गंगा की तीसरी बड़ी सहायक नदी गंडक है। जबकि आखिरी प्रमुख सहायक कोसी है। खास बात यह है कि पहले की तीन नदियां जहां गंगा का प्रदूषण बढ़ाती है वहीं कोसी विशाल मात्रा में निर्मल जल उड़ेलकर इसकी प्राकृतिक सफाई शुरू कर देती है। इन तीनों में सबसे ज्यादा बुरी हालत में यमुना है। इसके बावजूद भाई दूज पर हर साल उत्तर प्रदेश स्थित कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में स्नान के लिए लाखों लोग आते हैं। यमुना के किनारे स्थित वृंदावन में तो रोजाना ही देसी-विदेशी

तीर्थ यात्रियों का जनसमुद्र आता ही रहता है। बेशक मथुरा में कुछ लोग यमुना में स्नान कर लेते हैं, लेकिन वृंदावन में तो भूले-भटके ही लोग यमुना में डुबकी लगाते हैं। यमुना मैली तो यहां भी है, लेकिन वह सबसे ज्यादा बुरी हालत में देश की राजधानी दिल्ली के नजदीक नजर आती है। दिल्ली की नगरी संस्कृति का विकास यमुना के किनारे स्थित होने के ही चलते हुआ था। लेकिन दिल्ली में अब यमुना मरणासन्न है। आगे चलकर चंबल-बेतवा उसे कुछ पानी का उपहार दे देती हैं तो वह थोड़ी जीवंत होती है, लेकिन अपनी बड़ी बहन गंगा में समाहित होते-होते प्रयाग में जाकर एक बार फिर वह गंदगी का ही पर्याय नजर आती है। हरियाणा से लेकर दिल्ली होते हुए फिर हरियाणा के उद्योगों का प्रदूषित कचरा लेकर गुजरती यह नदी ना सिर्फ अपने किनारे की जमीन को भी प्रदूषित कर चुकी है, बल्कि गंगा को भी कचरे का प्रवाह बनाने में मददगार साबित हो रही है। यह बात और है कि गंगा खुद भी कानपुर में जमकर प्रदूषित होती है। उसके बाद तमाम शहरों का मल-जल भी उसी में प्रवाहित हो रहा है।

बहरहाल, यमुना की सफाई के लिए भारत सरकार ने यमुना कार्य योजना की शुरुआत की है। जिसके तीसरे चरण की शुरुआत इसी चार मई को हुई। इस योजना के तहत नदी के मूल चरित्र को बरकरार रखने की तैयारी की जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि यमुना कार्य योजना के पहले और दूसरे चरण 15 अरब रुपये खर्च हो चुके हैं, लेकिन खुद जलसंसाधन मंत्रालय ही मानता है कि इससे हालात में कोई बदलाव नहीं आया। बहरहाल नयी कार्ययोजना

में यमुना में लखवाड़-व्यासी परियोजना को भी जोड़ा गया है। जल संसाधन मंत्रालय का मानना है कि यह परियोजना पूरी तरह से लागू हुई तो दिल्ली में यमुना में अतिरिक्त पानी आ सकेगा और मथुरा वृंदावन तक यमुना को प्रदूषण मुक्त किया जा सकेगा। तीसरे चरण की इस कार्ययोजना के लिए केंद्र सरकार ने करीब 8 अरब रुपये के खर्च का अनुमान लगाया है। जिसका 85 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि बाकी का 15 प्रतिशत दिल्ली सरकार वहन करेगी। इसके तहत दिल्ली के ओखला, कोंडली और रिठाला में मौजूद 814 एमएलडी की क्षमता वाले मल शोधन संयंत्रों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही ओखला में 136 एमएलडी क्षमता वाले एक अतिरिक्त मल शोधन संयंत्र लगाने की भी तैयारी है।

जल संसाधन मंत्रालय का मानना है कि लखवाड़-व्यासी परियोजना पूरी तरह से लागू हुई तो दिल्ली में यमुना में अतिरिक्त पानी आ सकेगा और मथुरा वृंदावन तक यमुना को प्रदूषण मुक्त किया जा सकेगा। तीसरे चरण की इस कार्ययोजना के लिए केंद्र सरकार ने करीब 8 अरब रुपये के खर्च का अनुमान लगाया है। जिसका 85 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी जबकि बाकी का 15 प्रतिशत दिल्ली सरकार वहन करेगी।

दिल्ली में घनी आबादी वाले आनंद विहार, झिलमिल कॉलोनी, अशोक विहार और जहांगीर पुरी जैसे इलाकों में सीवर लाइन बेहद बुरी हालत में हैं। जिसकी वजह से सीवर का गंदा मल-जल नजदीकी नालों में जाता है और वह फिर बहकर यमुना में पहुंच जाता है। इस कार्ययोजना के तहत इनकी भी मरम्मत की जाएगी। हाल के कुछ वर्षों में प्रवासी बिहारियों ने यमुना के तट पर दिल्ली में जोर-शोर से छठ पर्व मनाना शुरू किया है। यमुना कार्ययोजना में इसे भी ध्यान में रखते हुए छठ घाटों के पुनरुद्धार का भी कार्यक्रम बनाया गया है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के वस्त्र बदलने के लिए बेहतर कक्ष और प्रसाधन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसके साथ ही जल संसाधन मंत्रालय और दिल्ली सरकार मिलकर वजीराबाद से ओखला तक

यमुना तटों के सौंदर्यीकरण पर काम करेंगे। नदी किनारे पैदल यात्रियों के लिए रास्ता बनाने की भी योजना है, ताकि लोग सुबह-शाम यमुना के किनारे पैदल घूमते हुए नदी के सौंदर्य का आनंद ले सकें। फिलहाल इस योजना के तहत यमुना की सतह पर कचरा उठाने वाली स्वचालित नौका यानी ट्रेश स्कीमर के जरिए काम शुरू भी हो चुका है। इस मशीन की कीमत साढ़े चार करोड़ रुपये है, जिसकी क्षमता रोजाना 10 टन कचरा उठाने की है। भारत सरकार का दावा है कि दिल्ली सरकार की मदद से वह तीन वर्षों में दिल्ली में यमुना का स्वरूप बदल देगी।

गंगा सफाई चूँकि केंद्र सरकार का चुनावी वादा है। फिर प्रधानमंत्री की छवि भी काम करने वाले शख्स की है। लिहाजा केंद्र सरकार अपने वादे को पूरा करने के लिए पूरे जोशों-खरोश के साथ जी-जान से जुटी हुई है। *नमामि गंगे मिशन* की कामयाबी के लिए जैसे जल संसाधन, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, पेयजल व स्वच्छता, पर्यटन, मानव संसाधन विकास, आयुष व नौवहन जैसे सात मंत्रालय इस चुनौती का मुकाबला करने की दिशा में कोई कोर-कसर भी नहीं रख रहे हैं। गंगा की शुद्धि के लिए केंद्र सरकार ने बजट में 20 हजार करोड़ की राशि आवंटित कर ही चुकी है। लेकिन, अब तक खास प्रगति होती नजर नहीं आ रही है। वैसे प्रगति तुरंत नजर आएगी भी नहीं, क्योंकि यह काम बड़ा और दीर्घकाल में नतीजे देने वाला है। इस पर विचार करने से पहले गंगा के प्रदूषण को लेकर कुछ आंकड़ों पर भी गौर किया जाना चाहिए।

सरकार भी मान चुकी है कि औद्योगिक रसायनयुक्त अवशेष, शहरी सीवेज, ठोस विषैला कचरा, रेत व पत्थर की चुनाई और बांधों से गंगा की तिल-तिलकर धीमी मौत मर रही है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के मुताबिक जगह-जगह बांध बनने से गंगा का पानी सुरंगों में गायब हो रहा है। गंगा में सीवर के साथ-साथ उद्योगों का विषैला कचरा जाने से संकट और गहरा गया है। देश के 25 फीसदी जल की अकेली स्रोत वाली गंगा के किनारे ही देश की तकरीबन 26 फीसदी आबादी ना सिर्फ बसी हुई है, बल्कि 13 करोड़ लोगों की रोजी-रोटी भी सीधे तौर पर गंगा नदी से ही जुड़ी हुई है। ऐसी नदी में तमाम योजनाओं के बावजूद रोजाना

बिना शोधित 1,2051 मिलियन लीटर सीवेज गंगा में गिराया जा रहा है। गंगा में दिनों दिन घटती ऑक्सीजन के लिए यह भी एक बड़ा कारक है। जलीय जीव तो गायब हो चुके हैं। कानपुर की जाजमऊ की 425 टेनरियों का 41 एमएलडी रसायनयुक्त कचरा और सीसामऊ सहित 14 बड़े नालों की गंदगी सीधे गंगा में जा रही है। इसके चलते गंगाजल में क्रोमियम लेड और अन्य घातक रसायन मिल रहे हैं।

केंद्र सरकार को पेश गंगा पर स्टेट्स रिपोर्ट के अनुसार नदी नरौरा से बलिया तक सबसे ज्यादा प्रदूषित है। पटना में 172 नालों का गंदा पानी सीधे गंगा में गिर रहा है। यहां 186 एमएलडी सीवेज बिना ट्रीटमेंट के गंगा में जा रहा है। यहां केवल 109 एमएलडी सीवेज की रोजाना ट्रीटमेंट की व्यवस्था है लेकिन होता केवल 64 एमएलडी ही है। गंगा के प्रदूषण

फिलहाल इस योजना के तहत यमुना की सतह पर कचरा उठाने वाली स्वचालित नौका यानी ट्रेश स्कीमर के जरिए काम शुरू भी हो चुका है। इस मशीन की कीमत साढ़े चार करोड़ रुपये है, जिसकी क्षमता रोजाना 10 टन कचरा उठाने की है। भारत सरकार का दावा है कि दिल्ली सरकार की मदद से वह तीन वर्षों में दिल्ली में यमुना का स्वरूप बदल देगी।

की शुरुआत तो हरिद्वार से ही हो जाती है। बिजनौर की फैक्टरियां गंगा में विषैला रसायन धोल रही हैं। उसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल से रोजाना गंगा में दो करोड़ 90 लाख लीटर प्रदूषित कचरा गिरता है। गंगा में गंदे पानी के चिह्नित 26 नाले उत्तराखंड में, 68 नाले उत्तर प्रदेश में गिरते हैं, जबकि उत्तराखंड के दो, उत्तर प्रदेश के 40 बिहार के 23 और पश्चिम बंगाल के 22 नाले गंगा में गिरते हैं। एनजीटी के कड़े रूख के बावजूद हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। हालात यह है कि गोमुख से उत्तरकाशी तक छोटे-बड़े तकरीब दस कस्बों में से एक में भी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। इसी तरह गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक गंगा के किनारे सैकड़ों की तादाद में बसे साधु-सन्ध्यासियों के मठों-आश्रमों का मल-मूत्र और गंदगी भी गंगा में ही बहाई जा रही है। कुंभ, मेला, पर्व आदि के समय तो स्थिति और भयावह हो जाती है। देवप्रयाग में अलकनंदा

और भागीरथी के मिलने के बाद ही गंगा अपनी यात्रा शुरू करती है। वहां पर भागीरथी और अलकनंदा में सीधे तौर पर छह नाले मिलते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक हरिद्वार में गंगा में ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है। हरिद्वार से नरौरा तक कुछेक जगहों पर प्रदूषण के चलते गंगाजल काला हो जाता है।

इन आंकड़ों की जानकारी इसलिए जरूरी है, ताकि हम जान सकें कि गंगा किस हालत में है। बहरहाल यमुना कार्य योजना को जहां गति दी जा रही है। वहीं दूसरे मोर्चों पर भी सरकार तेजी से काम कर रही है। राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की अधिकार प्राप्त संचालन समिति ने उत्तराखंड में हरिद्वार से उत्तराखंड की सीमा तक, उत्तर प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर, बिहार में बक्सर, हाजीपुर और सोनपुर, झारखंड में साहेबगंज, राजमहल और

गंगा किनारे बड़ी मात्रा में वन लगाकर नदी का ना सिर्फ जल प्रवाह बढ़ाया जा सकेगा, बल्कि प्रदूषण को कम भी किया जा सकेगा। इसके अलावा इसमें गंगा के किनारे के पांच राज्यों में गंगा से संबंधित विभिन्न अध्ययनों को बढ़ावा देना और इस परियोजना की कामयाबी को अन्य नदियों के संबंध में इस्तेमाल किया जाना शामिल है। इस परियोजना पर पांच वर्ष की अवधि के दौरान 2294 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

कन्हैया घाट में गंगा के किनारे साथ ही दिल्ली में यमुना पर घाटों और श्मशान स्थलों के विकास की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। जिन पर करीब 2446 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह पूरी रकम केंद्र सरकार देगी। जिसकी सहायता से गंगा के किनारों को सुंदर और बेहतर बनाना इसका लक्ष्य है। इस बीच गंगा के किनारे जंगल लगाने की भी योजना बनाई गई है। गंगा नदी विकास प्राधिकरण को इस सिलसिले में सौंपी रिपोर्ट के मुताबिक गंगा किनारे बड़ी मात्रा में वन लगाकर नदी का ना सिर्फ जल प्रवाह बढ़ाया जा सकेगा, बल्कि प्रदूषण को कम भी किया जा सकेगा। इसके अलावा इसमें गंगा के किनारे के पांच राज्यों में गंगा से संबंधित विभिन्न अध्ययनों को बढ़ावा देना और इस परियोजना की कामयाबी को अन्य नदियों के संबंध में इस्तेमाल किया

जाना शामिल है। इस परियोजना पर पांच वर्ष की अवधि के दौरान 2294 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मंजूर की गई सभी परियोजनाओं की समीक्षा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के समूह द्वारा गठित स्वतंत्र इकाइयों द्वारा की गई नमामि गंगे के तहत है। गंगा के किनारे वन लगाने के उपायों की समीक्षा वन और पर्यावरण मंत्रालय के महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति ने की। अधिकार प्राप्त संचालन समिति की अध्यक्षता केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सचिव करते हैं। समिति के अन्य सदस्यों में केंद्रीय वन और पर्यावरण, वित्त, शहरी विकास और विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधियों के अलावा गंगा किनारे के पांच राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

गंगा की सफाई के लिए किनारे वाले इलाकों में खास स्वच्छता अभियान भी चलाने की तैयारी है। इसकी शुरुआत नौ मई को झारखंड के साहिबगंज में नौ परियोजनाओं के साथ की गई है। इसके तहत झारखंड में 83 किलोमीटर तक बहने वाली गंगा के किनारे बसे सभी 78 गांवों की खुले में शौच से मुक्त बनाया जाना है। गौरतलब है कि झारखंड में गंगा नदी बेसिन में 78 गांवों में 45,000 परिवार बसे हैं। इन परियोजनाओं के तहत ना सिर्फ गंगा की सफाई की जा रही है, बल्कि यहां के निवासियों के स्वास्थ्य और रोजगार को भी बढ़ावा देने का काम किया जाना है। इसके तहत इन गांवों में डिग्रेडेबल यानी नष्ट करने योग्य ठोस अपशिष्ट के संग्रह, भंडारण और कम्पोस्ट खाद बनाने और बायोडिग्रेडेबल सामग्री के लिए छोटे उद्योगों 78 इकाइयां

स्थापित की जानी हैं। इसके साथ ही करीब 5,460 परिवारों को पशु और कृषि अपशिष्ट के लाभदायक उपयोग के लिए कीड़े वाली खाद के इस्तेमाल के लिए कम्पोस्ट खाद बनाने की ट्रेनिंग और सुविधा देने की भी तैयारी है। पशुओं का गोबर बहकर गंगा में ना जाए, इसके लिए 1,860 परिवारों को बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए मदद भी देने की तैयारी है। इन 78 गांवों में सामुदायिक भागीदारी से 10,000 से अधिक सोख्ता गड्ढों को भी बनाया जाना है। नमामि गंगे मिशन की झारखंड की इस योजना को यूएनडीपी, सामुदायिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की देखरेख में चलाया जाना है।

गंगा की सफाई के लिए जितने जरूरी किनारे बसे सामुदायिक इलाकों की सफाई और कचरा के साथ मल निपटान व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाना है, उतना ही जरूरी है

गंगा की सफाई के लिए किनारे वाले इलाकों में खास स्वच्छता अभियान भी चलाने की तैयारी है। इसकी शुरुआत नौ मई को झारखंड के साहिबगंज में नौ परियोजनाओं के साथ की गई है। इसके तहत झारखंड में 83 किलोमीटर तक बहने वाली गंगा के किनारे बसे सभी 78 गांवों की खुले में शौच से मुक्त बनाया जाना है।

गंगा की सहायक नदियों की सफाई। यमुना कार्ययोजना अगर कामयाब होगी तो तय है कि गंगा की सफाई का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो जाएगा। □

विशेष आधार पंजीकरण अभियान

भारतीय विशिष्ट पहचान क्रमांक प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार पंजीकरण से बची रह गई आबादी के पंजीकरण के लिए चार राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों: हरियाणा, गोवा, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में एक विशेष अभियान आरंभ किया। जहां (2015 के जनसंख्या के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार) आधार की 100 प्रतिशत से अधिक पहुंच है। 12 मई, 2016 तक देश भर में 101.26 करोड़ आधार क्रमांक दिए जा चुके हैं। चार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रायोगिक अभियान 13 मई से 15 जून, 2016 के बीच ही चलाया जाएगा।

18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के ही नामांकन के आवेदन ही <https://wenrol.uidai.gov.in> पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे। मोबाइल नंबर तथा अन्य जनसांख्यिक विवरण भी अनिवार्य होगा क्योंकि जैसे ही नामांकन का आवेदन जमा होगा, वैसे ही मोबाइल ओटीपी आधारित सत्यापन किया जाएगा। इस प्रयोग से होने वाले अनुभव के आधार पर यह विशेष अभियान अन्य राज्यों में भी आरंभ किया जाएगा। <https://wenrol.uidai.gov.in> पद पोर्टल पर निकटतम नामांकन केंद्र खोजने की सुविधा भी उपलब्ध है।

'पतंजलि' संस्थान के कक्षा कार्यक्रम से मूलतः संबंधित सर्वश्रेष्ठ परिणाम



सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन बैच

निःशुल्क
कार्यशाला

14 जून
11:30 am

P.T. स्पेशल 2016

निःशुल्क
कार्यशाला

16 जून
6:30 pm

I
A
S

दर्शनशास्त्र

I
A
S

UPPCS TOPPER-2015



SIDDHARTHA YADAV
(B.Tech)

1
Rank
Old Rajendra Nagar
2013 Batch
Marks in
PHILOSOPHY
288/400



RAGHVENDRA
KR. DWIVEDI

दर्शनशास्त्र
में
सर्वश्रेष्ठ
अंक
294

सबसे बेहतर वैकल्पिक विषय क्यों?

छोटा सिलेबस, स्पष्ट पाठ्यक्रम,
लोकप्रिय एवं अंकदायी विषय
निबंध एवं GS में अत्यंत उपयोगी
लाखों तथ्यों को रटने की विवशता नहीं
High Success Ratio

UPPCS के अधिकांश टॉपर
दर्शनशास्त्र एवं 'पतंजलि' के साथ

**JAIPUR
CENTRE**

**RAS — PT 2016
Special Batch**

फाउंडेशन बैच
6 जून

प्रथम
बैच

8 AM

द्वितीय
बैच

4 PM

**GWALIOR
CENTRE**

MPPSC - 2016

मुख्य परीक्षा

बैच-प्रारंभ
जून प्रथम सप्ताह

PATANJALI

HEAD OFFICE
202, 3rd Floor, Bhandari House,
Mukherjee Nagar
Ph.: 011- 32966281, 9810172345

BRANCH OFFICE
104, 11nd Floor, Near Axis Bank
Old Rajinder Nagar
Ph.: 9811583851, 9555043146

BRANCH OFFICE
31, Satya Vihar, Lal Kothi, Near Jain
ENT Hospital, New Vidhan Sabha, Jaipur
Ph.: 9571456789, 9680677789

कौशल विकास और निजी क्षेत्र

प्रमोद भसीन



ऐसे समय में, निजी क्षेत्र की भागीदारी और भूमिका बिल्कुल अपरिहार्य है और कौशल विकास के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा इसी तरह के प्रयासों के जरिए समर्थन किया जाना चाहिए। यह समय भारत के निजी क्षेत्र के लिए है, कि वे इन प्रमुख सरकारी पहलों से नजदीकी से जुड़कर इन्हें आगे ले जाएं। हमारी जनसांख्यिकी, हमें दुनिया को कार्य बल प्रदान करने में बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम निजी क्षेत्र और सरकार के बीच एक उत्कृष्ट भागीदारी का निर्माण करें। हमें एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन संयुक्त रूप से हम इस कमजोरी को भारत के लिए एक बड़ी सफलता और ताकत बना सकते हैं

क

म श्रम लागत और प्रचुर प्रतिभा संपन्न होना भारत का विशिष्ट लक्षण है जिसने स्पष्ट रूप से एक ज्ञान आधारित देश के रूप में इसकी वैश्विक स्थिति और प्रतिस्पर्धात्मकता को स्थापित किया है। वर्ष 2030 तक भारत में कार्यकारी बल की संख्या एक अरब के करीब होगी। ऐसे में भारत के भविष्य को तेज गति देने और आर्थिक विकास हेतु यहां के लोगों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण मुहैया करना एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। इसके अलावा, भारत की स्थिति को एक प्रभावी कार्यशील अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूत करने के लिए मानव संसाधन को कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करना आज समय की जरूरत है और यह अपरिहार्य बन गया है कि हम एक देश के रूप में यह अहसास करें और इसमें निवेश करें। कौशल विकास और प्रशिक्षण पर काफी जोर देने के बावजूद अभी भी यहां कुशल श्रम शक्ति की कमी है। अतः मानव संसाधन विकास को देश के समग्र विकास के लिए तेजी से महत्व मिलेगा।

2025 तक भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश का वैश्विक कार्यबल में 35 प्रतिशत योगदान देने की उम्मीद है। यह एक व्यापक आर्थिक संपदा है और हमारी सबसे बड़ी ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। हमें अपने मिशन और क्षमता को पूरा करने के लिए इसका अत्यधिक लाभ उठाना चाहिए। हालांकि, इस विशाल जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ लेने के लिए हमें बड़े पैमाने पर कौशल विकास और रोजगार पहल की आवश्यकता है। पिछले वर्ष जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,500

करोड़ रुपये की योजना कुशल भारत अभियान का शुभारंभ किया, जिसका लक्ष्य 2022 तक विभिन्न कौशलों में 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करना है। इस पहल में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए 2015 राष्ट्रीय नीति, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) योजना और कौशल ऋण योजना आदि शामिल हैं। जहां, कौशल विकास पर निस्संदेह मजबूती से ध्यान केंद्रित है, वहीं 2022 तक 500 मिलियन (50 करोड़) लोगों को कुशल बनाने के लक्ष्य को हम कैसे पूरा करेंगे, इस बारे में अभी भी थोड़ी अस्पष्टता है।

भारत ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था, जिसके कारण कौशल में भारी कमी आई। जब तीव्र आर्थिक विकास ने भारत में कुशल श्रमिकों की मांग को दस गुणा तक बढ़ा दिया, तब भारत के सभी आर्थिक क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की भारी कमी उजागर हुई। हमारी समस्या की जड़ रोजगार की कमी नहीं है, अपितु ऐसे रोजगारपरक, कुशल प्रतिभा की कमी है जो तेजी से फैल रहे उद्योग की जरूरत को पूरा कर सके। भारत में प्रतिवर्ष 30 लाख स्नातक नौकरी के लिए तैयार होते हैं, उनमें से केवल पांच लाख युवाओं में ही नौकरी पाने की क्षमता होती है। आईटी, बीएफएसआई, हेल्थकेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल, ऑटो और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं सहित अन्य क्षेत्र में श्रमशक्ति की भारी कमी है।

हाल ही में एक आंकड़े के अनुसार, सिर्फ 10 वयस्कों में से एक में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की बात कही है। राष्ट्रीय नमूना

लेखक बीपीओ कंपनी जेनपैक्ट के चेयरमैन, संस्थापक तथा पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन व अन्य देशों में वित्तीय, प्रौद्योगिकी तथा बीपीओ सेवाओं में उनका विशाल अनुभव है। ईमेल: zorema.darkim@skillsacademy.co.in

सर्वेक्षण कार्यालय ने इस साल के शुरू में शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर 2011-12 राउंड के आधार पर आंकड़े जारी किए थे।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि 15-59 वर्ष की आयु वर्ग में, केवल 2.2 प्रतिशत लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण और 8.6 प्रतिशत लोगों ने गैर-औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने की बात कही है। यही नहीं, व्यावसायिक प्रशिक्षण की दर बमुश्किल बढ़ी है, 2004-05 और 2011-12 में जब अंतिम बार आंकड़े एकत्रित किए गए। वर्ष 2009 में यूपीए सरकार ने एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कौशल नीति की घोषणा की थी और राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड का गठन किया था, जिसके उपरांत भी कुछ खास सुधार होता हुआ नहीं दिखा। भारत, विश्व भर में सबसे बड़ी कार्यशील आबादी (15-59 वर्ष) वाला दूसरा देश है, अतः इस जन समूह को कौशल युक्त बनाना, देश की संवृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका

प्रमुख नौकरी सर्जक और नियोक्ता होने के नाते, निजी क्षेत्र के पास कौशल विकास कार्यक्रमों के दायरे गुणवत्ता और स्थिरता को प्रभावित करने की क्षमता है। वह न केवल औपचारिक बल्कि अनौपचारिक क्षेत्र के लिए भी समान रूप से इन कौशल प्रशिक्षितों को रोजगार और आजीविका से जोड़ने में सक्षम है।

निभाता है। यह जरूरी है कि उन्हें उत्पादक बनाने के लिए इस आयु वर्ग को पर्याप्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

वर्तमान व्यावसायिक शिक्षा मोटे तौर पर एक कल्याणकारी दृष्टिकोण के स्थान पर एक मांग आधारित दृष्टिकोण की तरफ बढ़ रही है। विभिन्न महत्वाकांक्षी कौशल विकास पहलों के साथ, निजी क्षेत्र को पारिस्थितिकी को कुशल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

प्रमुख नौकरी सर्जक और नियोक्ता होने के नाते, निजी क्षेत्र के पास कौशल विकास कार्यक्रमों के दायरे गुणवत्ता और स्थिरता को प्रभावित करने की क्षमता है। वह न केवल औपचारिक बल्कि अनौपचारिक क्षेत्र के लिए भी समान रूप से इन कौशल प्रशिक्षितों को रोजगार और आजीविका से जोड़ने में सक्षम है। हालांकि, कुछ उद्योगों के अलावा निजी क्षेत्र ने जरूरत के मुताबिक हमारे कर्मचारियों

कौशल, नौकरी और सशक्तीकरण

विकास की ओर भारतीय महिलाओं की छलांग

दीनदयाल अंत्योदय योजना

- ग्रामीण निर्धन परिवारों को महिला स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित करना।
- 3045 प्रखंडों में फैले 1,76,414 गांवों में 26 लाख स्वयं सहायता समूह संगठित/समृद्ध किए गए।

स्टैंड अप इंडिया

- अनुसूचित जाति/जनजाति को महिलाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहन
- पांच सौ करोड़ रुपये का आबंटन

प्रशिक्षण

- वर्ष 2015-16 में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी संस्थान ने 7247 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया
- पिछले दो वर्षों में एकोकृत कौशल विकास योजना के तहत 2.69 लाख महिलाओं में से 70 प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण

नौकरी

- 2015-16 में सबसे अधिक नौकरी महिलाओं को भागीदारी मनरेगा में
- मिड डे मील योजना में 25.74 लाख रसोई या सह सहायता में से 90% से अधिक महिलाएं हैं

को कुशल और प्रशिक्षित करने में निवेश नहीं किया है। दुनिया भर के ज्यादातर देशों में, जहां व्यावसायिक कौशल बहुत ज्यादा स्वीकार किए गए हैं, उद्योग ने न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक रूप में कौशल विकास के लिए योगदान दिया है। इस क्षेत्र में कुशल श्रम शक्ति की एक उपभोक्ता के रूप में गुणवत्तापूर्ण ज्ञान की एक गैर लाभ सुविधा के रूप में या शिक्षा प्रदान करने के लिए एक लाभ उद्यम के रूप में, आदि कई भूमिकाएं हैं, जिन्हें निजी क्षेत्र निभाते हैं।

निजी क्षेत्र, एक उपभोक्ता के रूप में अपनी पहली भूमिका उपलब्ध जनशक्ति को उपयुक्त कौशल में प्रशिक्षित कर और अंत में उन्हें रोजगार प्रदान करके लाभान्वित कर, निभा सकते हैं। एक गैर लाभ कार्यसुविधा के रूप में, कंपनियां, समाज को धन देकर और निवेश के माध्यम से उसे वापस कर सकती हैं। एक लाभ उद्यम के रूप में वे स्कूलों, प्रशिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों का निर्माण कर एक निश्चित मूल्य पर शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करके अपनी भूमिका निभा सकते हैं।

ऐसे कई तरीके हैं जिससे कि निजी क्षेत्र, भारत में कौशल विकास परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकते हैं।

• **उद्योग की मांग का पूर्वानुमान:** निजी क्षेत्र की भूमिका उद्योगों को मांग के मुताबिक बेहतर कुशल जनशक्ति की आपूर्ति करने

की योग्यता से निर्धारित होती है। चूंकि यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार की (वेतनभोगी, सविदा, मजदूरी पर आधारित) नौकरियां उत्पन्न करता है और उनका उपयोग करता है। अतः उसे उत्पन्न होने वाली मांग के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। वह अपने उपयोग के लिए प्रशिक्षित, रोजगारपरक, कुशल जनशक्ति की एक संसाधन स्रोत की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। नौकरी में भूमिकाओं, मजदूरी, स्थानों और संख्याओं पर निजी क्षेत्र के माध्यम से विशेष जानकारी, प्रशिक्षण प्रदाताओं को उसी के हिसाब से उनके लिए कार्यक्रमों की योजना बनाने में सक्षम बनाता है और उद्योग की ओर से की गई मांग के मुताबिक कौशल/ विशेषज्ञता प्रदान किया जाना सुनिश्चित करता है। इससे एक उपयुक्त प्रतिभा संपन्न कार्य बल तैयार करने में सहूलियत होती है। इससे

निजी क्षेत्र, एक उपभोक्ता के रूप में अपनी पहली भूमिका उपलब्ध जनशक्ति को उपयुक्त कौशल में प्रशिक्षित कर और अंत में उन्हें रोजगार प्रदान करके लाभान्वित कर, निभा सकते हैं। एक गैर लाभ कार्यसुविधा के रूप में, कंपनियां, समाज को धन देकर और निवेश के माध्यम से उसे वापस कर सकती हैं।

नौकरी और कौशल के बीच असंगतता में कमी आती है।

• **गुणवत्ता और औद्योगिक मानदंड की स्थापना:** मौजूदा नौकरियों में कौशल अंतर की पहचान करने और राष्ट्रीय व्यवसाय मानक (एनओएस) के माध्यम से मौजूदा और नई नौकरी में भूमिकाओं का विकास करने और उन्हें मान्यता देने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों हेतु गुणवत्ता मानकों की स्थापना करने में निजी क्षेत्र अपना योगदान कर सकते हैं।

• **प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ रणनीतिक साझेदारी:** सभी निजी कंपनियों के पास प्रशिक्षण देने के कार्यक्रमों के लिए आवश्यक पहुंच, जानकारी और विशेषज्ञता या इन-हाउस क्षमता नहीं है। उन्हें अपने मानव संसाधन आवश्यकता को अद्यतन करने और अपनी जरूरतों के लिए एक

प्रतिभा पाइपलाइन तैयार करने के लिए लगातार प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ गठजोड़ करना चाहिए।

- **नौकरी प्रशिक्षण और प्रशिक्षुता के लिए उद्योग को सुगम बनाना:** किसी भी चुने हुए कौशल में प्रशिक्षण और विशेषज्ञता के उच्च स्तर को पाने के लिए उद्योगों से जुड़कर और अपने हाथ से व्यावहारिक प्रशिक्षण व अनुभव प्राप्त करने के महत्व के विषय में जागरूकता बढ़ रही है। निजी क्षेत्र को बढ़ी संख्या में प्रशिक्षुओं को नौकरी पर प्रशिक्षण और प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) के अवसर मुहैया कराने के लिए अपने दरवाजे खोल देने चाहिए।
- **कौशल विकास कार्यक्रमों की दिशा में सीएसआर कोष का उपयोग:** निजी क्षेत्र के पास व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश करने के लिए अपेक्षित धन है। 2 प्रतिशत सीएसआर मंजूरी के साथ, कंपनियों को इस कोष का उपयोग कौशल विकास कार्यक्रमों में रचनात्मक निवेश करने के लिए करना चाहिए।

• **प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे में निवेश:** कंपनियां प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ साझेदारी कर बुनियादी ढांचे, सुविधाओं, प्रौद्योगिकी और शिक्षा सास्त्र सहित विभिन्न क्षेत्रों कौशल प्रशिक्षण प्रदान पर खर्च कर सकते और अनुपूरक बन सकते हैं। वे विशेष प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं /उपकरण के लिए भी धन मुहैया करा सकते हैं या उसे सस्ता कर सकते हैं, जिसमें प्रशिक्षण साझेदारों के लिए निवेश करना बहुत महंगा साबित हो सकता है।

क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी), प्रशिक्षण प्रदाताओं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और सरकारी निकायों के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से निजी क्षेत्र किसी भी कौशल प्रशिक्षण पहल की सफलता को महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित कर सकता है।

एक उभरती सेवा संचालित अर्थव्यवस्था के रूप में हमारी प्रतिस्पर्धा में बढ़त के लिए गुणवत्तापूर्ण मानव पूंजी के साथ हमारे विकास को बढ़ावा देने के लिए, एक कुशल कार्यबल रखने के महत्व का एहसास करने हेतु, यह

महत्वपूर्ण है। कौशल और शिक्षा से शिक्षार्थी के रोजगार में वृद्धि होगी। अर्जित ज्ञान के साथ, श्रमिक, भारत की प्रतिस्पर्धा में बढ़त निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकता में योगदान देंगे।

विभिन्न सुधारों, नीति में परिवर्तन और बेहतर वित्तीय परिदृश्य जो संभवतः देश को एक ज्ञान स्थली में बदल सकता है, के माध्यम से इसमें सरकार द्वारा एक स्पष्ट प्रयास किया गया है। ऐसे समय में, निजी क्षेत्र की भागीदारी और भूमिका बिल्कुल अपरिहार्य है और कौशल विकास के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा इसी तरह के प्रयासों के जरिए समर्थन किया जाना चाहिए। यह समय भारत के निजी क्षेत्र के लिए है, कि वे इन प्रमुख सरकारी पहलों से नजदीकी से जुड़कर इन्हें आगे ले जाएं। हमारी जनसांख्यिकी, हमें दुनिया को कार्य बल प्रदान करने में बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम निजी क्षेत्र और सरकार के बीच एक उत्कृष्ट भागीदारी का निर्माण करें।



SYNERGY

AN INSTITUTE FOR CIVIL SERVICES EXAMINATION

OUR PROGRAMME

PUBLIC ADMINISTRATION

ETHICS MODULE

G.S CLASS PROGRAMME

TEST SERIES PROGRAMME (MAINS & P.T.)

MAINS OPTIONAL TEST SERIES

FOR NEW BATCHES AND COURSES:- KINDLY VISIT ON - synergy.edu.in & synergyraftar.com

TO **"ASSESS YOUR PREPARATION"** Join Our RUNNING PROGRAMME

(BOTH ENGLISH & HINDI MEDIUM)

UPSC PRELIMS TEST SERIES:- STARTED FROM 8TH MAY

(BOTH ENGLISH & HINDI MEDIUM)

UPSC PRELIMS TEST SERIES:- 4 MODEL TEST (ON 10TH & 14TH JULY)

(BOTH ENGLISH & HINDI MEDIUM)

MAINS PREPARATORY TEST SERIES:- 4 MODEL TEST (I, II, III & IV PAPER) (ON 18TH & 19TH JUNE)

YOU CAN DOWNLOAD OUR PREVIOUS QUESTION PAPER & DETAILED ANSWER FROM OUR WEBSITE:- www.synergyraftar.com

HEAD OFFICE:

Mukh. Nagar:- 102, 1st Floor, Manushree Building,
Comp. (Behind Post Office), Delhi - 09 Ph: 011-27653494, 27654518

BRANCH OFFICE:

Karol Bagh:- 16-A/2, 1st Floor, Ajmal Khan Road, W.E.A.,
New Delhi - 05 Ph: 011-25744391

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

यो

ग के सर्वव्यापी आकर्षण को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा का प्रस्ताव भारत ने पेश किया था और रिकॉर्ड 175 सदस्य देशों ने उसका समर्थन किया। यह प्रस्ताव पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में रखा था, जिसमें उन्होंने कहा, “योग हमारी प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। योग में शरीर एवं मस्तिष्क, विचार एवं कार्य एक हो जाते हैं। यह सर्वांगीण दृष्टिकोण है, जो हमारे स्वास्थ्य एवं हमारे सुख की दृष्टि से बहुत मूल्यवान है। योग व्यायाम मात्र नहीं है, यह आत्मा, विश्व एवं प्रकृति के साथ एकीकरण के भाव को प्राप्त करने का तरीका है।”

योग प्राचीन शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जो भारत में आरंभ हुई। ‘योग’ शब्द संस्कृत से लिया गया है और उसका अर्थ है मिलना अथवा एक होना, जो शरीर एवं चेतना के मिलन का द्योतक है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का लक्ष्य योग के विभिन्न लाभों के प्रति पूरे विश्व को जागरूक बनाना है। 21 जून, 2015 को आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने सकारात्मक प्रतिक्रिया की और यमन को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र के अन्य सभी 193 सदस्य देशों ने इसमें हिस्सा लिया। विभिन्न देशों में व्याख्यान, प्रदर्शन एवं सामान्य



योग संहिता पर आधारित सामूहिक योगाभ्यास, योग क्लबों एवं सामुदायिक संगठनों में बैठकें एवं योग कॉन्सर्ट, योगार्थन, योग वॉक्स, फिल्म एवं वृत्त चित्र प्रदर्शन तथा छायाचित्र प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। भारत सरकार ने भी 21 जून, 2015 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जीवंत तरीके से मनाया, जिसमें देश भर के लोगों ने इस दिन सामूहिक योगाभ्यास कर उत्साह के साथ हिस्सा लिया। दो गिनीज विश्व रिकॉर्ड बने- 35,985 प्रतिभागियों के साथ सबसे बड़ा योग अभ्यास एवं एक ही योग सत्र में सबसे अधिक देशों (84) के नागरिकों की सहभागिता।

इस वर्ष भी यह दिवस आयोजित करने की योजना है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का प्रतीक चिह्न अर्थात् लोगो निम्नलिखित संकेत देता है: लोगो में दोनों मुड़े एवं जुड़े हाथ योग अर्थात् मिलन का प्रतीक हैं, जो व्यक्तिगत चेतना के सार्वभौम चेतना अर्थात् ब्रह्म से एकाकार होने अर्थात् मस्तिष्क एवं शरीर के मध्य, मनुष्य एवं प्रकृति के मध्य सामंजस्य तथा स्वास्थ्य एवं सुख के सर्वांगीण दृष्टिकोण का द्योतक है। भूरी पत्तियां पृथ्वी के तत्त्व की प्रतीक हैं, हरी पत्तियां प्रकृति की प्रतीक हैं, नीला रंग जल तत्त्व का द्योतक है, चमक अग्नि की प्रतीक है और सूर्य ऊर्जा एवं प्रेरणा के स्रोत की ओर संकेत करता है। यह लोगों मानवता के प्रति सौहार्द एवं शांति का प्रतीक है, जो योग का सार है। 21 जून का दिन और शब्द “सद्भाव व शांति के लिए योग” लोगों के नीचे दिखते हैं।

भारतीय विश्वविद्यालयों में योग शिक्षण

अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण की 2014-15 की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार 25 विश्वविद्यालय एवं 18 कॉलेज योग में स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर रहे हैं। नीचे दिए गए दो योग विश्वविद्यालय यूजीसी की सूची में हैं:

(1) लाकुलिश योग विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, (2) स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान (मानद विश्वविद्यालय), बेंगलूर।

सरकार ने विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा पर एक समिति का गठन किया है। समिति का उद्देश्य कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में योग के संकाय की योग्यता निर्धारित करना है तथा यह भी देखना है कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में संकाय की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अभी जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, उनमें बदलाव की आवश्यकता तो नहीं है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

(क) एनईटी पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए उप-समिति की नियुक्ति, (ख) विश्वविद्यालयों में सात कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जैसे (अ) योग में 6 से 12 महीने का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम, (आ) 3 से 6 वर्ष का योग विज्ञान में स्नातक - बीएससी (योग) पाठ्यक्रम, (इ) योग में 1 से दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीवाई), (ई) योग चिकित्सा में 1 से 2 वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीवाईटी), (उ) योग में दो से 4 वर्ष की स्नातकोत्तर उपाधि - एमएससी (योग), (ऊ) 3 से 5 वर्ष की पीएचडी - योग, (ए) 4 से 6 वर्ष की पीएचडी (एकीकृत) - योग।

समिति ने योग शिक्षकों की योग्यता के संबंध में भी सलाह दी है। समिति ने विश्वविद्यालयों में योग के संवर्द्धन के लिए अन्य सिफारिशें भी की हैं।

योग: आधुनिक जीवनशैली व अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता

ईश्वर वी बासवरेड्डी



विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी इलाज में चिकित्सा के प्राचीन प्रणालियों को शामिल करने की जरूरत पर जोर दिया है। डब्ल्यूएचओ ने सुरक्षा और क्षमता के मूल्यांकन के लिए रणनीतिक दिशा-निर्देश दिए हैं। यहां इस बात पर भी जोर दिया गया है कि समय की कसौटी पर खरी उतरी योग की प्रणाली को सिर्फ साक्ष्यों अभाव के कारण नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। योग की क्षमता और शक्तियों को अहमियत देने की जरूरत है। इस प्रणाली का इस प्रणाली के अधिकतम इस्तेमाल के लिए नीतिगत पहल और रणनीतिक हस्तक्षेप की जरूरत है

वास्तव में योग एक अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक अनुशासन है, जिसका जोर मस्तिष्क और शरीर, इंसान और प्रकृति के बीच सामंजस्य पर रहता है। यह स्वस्थ जीवन के लिए कला और विज्ञान दोनों ही है। योग के संपूर्ण दृष्टिकोण अच्छी तरह से स्थापित हो चुके हैं और यह जीवन के हर क्षेत्र में सामंजस्य स्थापित करता है। लिहाजा यह रोगों से बचाव, सेहतवर्द्धक और जीवन शैली से जुड़ी कई गड़बड़ियों एवं कमियों को ठीक करती है। आज दुनिया भर में योग की लोकप्रियता सिर्फ कुछ रोगों के इलाज में सक्षम रहने के कारण नहीं, बल्कि योग करने से व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक तनाव से निजात मिलता है और बेहतर जीवन का अनुभव होता है।

इस वजह से इन दिनों योग दुनिया भर में बेहतर जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। योग को चेतना की प्राचीन संस्कृति, जागरूकता का विज्ञान, मन की संतुलित स्थिति और काम में उत्कृष्टता से समझा जा सकता है। यह अनिवार्य है कि यह अद्भुत संस्कृति चारों तरफ फैले, ताकि दुनिया में हर व्यक्ति को इसका फायदा मिल सके। दुर्भाग्य से कई लोग योग को शारीरिक और मानसिक शांति के लिए सिर्फ आसन और प्राणायाम समझने की गलती करते हैं। इससे उलट योग का नजरिया विस्तृत है। अगर योग को जीवन के एक मार्ग के तौर पर अपनाया जाए तो यह अनमोल उपहार किसी को भी साधारण से असाधारण व्यक्तित्व में बदल सकता है।

खुद को बेहतर बनाने की हर कोशिश योग है। अलग-अलग देशों में अलग-अलग समय में लोगों ने बेहतर ज्ञान के लिए स्वयं को अनुशासित बनाया और अपने और अपने परिवेश पर नियंत्रण बनाया। भारत में यह योग के जरिए हुआ है। इस प्रक्रिया में किसी के व्यक्तित्व का संपूर्ण नियंत्रण है, ताकि लोग अपने भीतर सत्य की खोज कर सकें। आज भी इसकी प्रासंगिकता योगी की खोज और उसके अनुभव से सीधे तौर पर जुड़ी है।

अपनी शंकाओं पर काबू पाकर गहरी शांति का अनुभव करना, जीवन के उद्देश्य की खोज, लंबे समय तक जीवन के इन बुनियादी मुद्दों पर चिंतन करने के बाद योगी को इनका जवाब मिला। हर व्यक्ति के पास पूर्ण स्पष्टता, करुणा और देखभाल के साथ एक खूबसूरत जीवन जीने का विकल्प है। इसी चीज को जीवन की कला और विज्ञान, जिसे योग कहते हैं, इसके जरिए कोई व्यक्ति सीखता है।

प्राचीन और आधुनिक समय में योग

माना जाता है कि योग का अभ्यास सभ्यता की शुरुआत के साथ ही है। योग को व्यापक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का एक 'अमर सांस्कृतिक परिणाम' माना जाता है और इसने मानवता के आध्यात्मिक और भौतिक उत्थान में अहम योगदान देकर इस बात को साबित भी किया है। अलग-अलग तरह के दर्शनों, परंपराओं, वंशावलियों और योग के गुरु-शिष्य परंपराओं के कारण योग के अलग-अलग पारंपरिक आश्रमों का उदय हुआ। जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म-योग, ध्यान योग,



पातञ्जल योग, कुंडिलिनी योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग, राज योग, जैन योग, बुद्ध योग आदि। प्रत्येक आश्रम के अपने सिद्धांत और अभ्यास हैं, जिनसे योग के उद्देश्यों को हासिल किया जा सकता है। योग की धरती, भारत के विभिन्न सामाजिक रीति-रिवाजों और संस्कारों में पारिस्थितिक संतुलन, दूसरे विचारों के प्रति सहिष्णुता और सभी जीवों प्रति करुणा और प्रेम साफ नजर आता है।

एक सार्थक जीवन के लिए योग को रामाबाण माना जाता है। व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होने के कारण योग अभ्यास स सभी धर्मों, जातियों और देशों के लोगों के लिए बड़े काम की चीज है। इन दिनों लाखों-करोड़ों लोगों को योग के अभ्यास से फायदा हुआ है, जिसे प्राचीन समय से अब तक महान प्रख्यात योग गुरुओं ने संभाला और प्रोत्साहित किया है। आज दुनिया भर योग जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। व्यापक तौर पर जिन योग साधना का अभ्यास किया जाता है वे हैं: यम, नियम, आसन, प्रणायाम, प्रत्यचार, धरना, ध्यान, समाधि/सम्यमा, बुद्ध एवं मुद्रा, शत-कर्म, युक्त-आहार, युक्त-कर्म, मंत्र जाप आदि है।

आधुनिक जीवन शैली व स्वास्थ्य संबंधी लाभ

आधुनिक जमाने की जीवनशैली से स्वास्थ्य से जुड़ी कई चुनौतियां पैदा हो गई हैं और दुनियाभर में लोगों को होने वाली कई बीमारियों की वजह भी है। तनाव एवं खानपान की

गलत आदतों के कारण सेहत बिगड़ रही है और मधुमेह, दमा, दिल की बीमारियां, कैंसर और अपच की बीमारियां हो रही हैं। क्या योग इन सभी बीमारियों का रामबाण इलाज हो सकता है?

आधुनिक समय की ज्यादातर बीमारियां खासतौर पर पुरानी असंक्रामक बीमारियां गलत जीवन शैली की वजह से होती हैं। इन बीमारियों को दूर करने में योग काफी फायदेमंद है और यह दर्शाता है कि विज्ञान और अध्यात्म को हमेशा अलग करके देखने की जरूरत नहीं है। योग में जीवन शैली

योग से होने वाले फायदों को तीन स्तरों पर जाना जा सकता है। शारीरिक स्तर पर यह सेहतमंद बनाता है। मानसिक स्तर पर इससे ध्यान बढ़ता है, तनाव दूर होता है और काम करने की क्षमता बढ़ती है। आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो यह मानवीय मूल्यों को बढ़ाता है और जीवन में शांति लाता है।

से जुड़ी समस्याओं और मानसिक बीमारियों को दूर करने की क्षमता है। बीमारियों के निजात खासतौर पर तनाव और मानसिक परेशानियों से होने वाले रोगों के इलाज और स्वास्थ्य बेहतर बनाने में योग की अहमियत वैज्ञानिक तौर पर जांचने के लिए दुनियाभर में कई अनुसंधान अध्ययन हुए हैं। स्वास्थ्य पर योग के प्रभाव को समझने के लिए जैव रासायनिक, मनोवैज्ञानिक और नैदानिक (क्लीनिकल) पक्षों का नियंत्रित प्रयोगों में अध्ययन किया गया।

अध्ययन से पता चला है कि योग स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और अंतः स्रावी प्रणाली पर अपने प्रभाव के जरिए योग अभ्यास करने वाले के कोशिकीय और आणविक पहलुओं पर असर डालता है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि योगाभ्यास करने वालों में स्वायत्त संतुलन के साथ उनकी तंत्रिका प्रणाली भी मजबूत होती है जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया की रफ्तार धीमी होती है। योगाभ्यास करने वालों की पाचन क्रिया दुरुस्त होती है और तनाव कम होता है।

अध्ययन से इस बात के भी संकेत मिले कि योग करने से तनाव झेलने की क्षमता बढ़ती है, शरीर लचीला होता है, शारीरिक क्षमता बेहतर होती है और थर्मोरेगुलेटरी क्षमता बढ़ती है। योग शरीर की प्रतिरक्षा की क्षमता बढ़ाकर बीमारियों से भी बचाता है। योग उच्च रक्तचाप, मधुमेह और धमनी की बीमारियों से बचाव में भी कारगर है। योग का अभ्यास करने से मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों में दवाओं का इस्तेमाल कम करना पड़ता है और यह दिल की बीमारियों से भी बचाव में मदद करता है।

योग से होने वाले फायदों को तीन स्तरों पर जाना जा सकता है। शारीरिक स्तर पर यह सेहतमंद बनाता है। मानसिक स्तर पर इससे ध्यान बढ़ता है, तनाव दूर होता है और काम करने की क्षमता बढ़ती है। आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो यह मानवीय मूल्यों को बढ़ाता है और जीवन में शांति लाता है।

- लचीलापन बढ़ाने में मददगार।
- मांसपेशियों की ताकत में इजाफा।
- श्वसन, ऊर्जा और जीवन शक्ति में सुधार।





- संतुलित चयापचय बनाए।
- वजन घटाने में सहयोगी।
- दिल और धमनियां स्वस्थ।
- शारीरिक तंदरुस्ती।
- बेहतर प्रतिरक्षा।
- हृदय सेहतमंद।

योग के मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ नीचे बताए गए हैं

- तनावमुक्त होने का अहसास।
- वर्तमान क्षण से खुशी बटोरना।
- मन और विचारों पर नियंत्रण।
- मानसिक स्पष्टता में इजाफा।
- एकाग्रता और ध्यान में बढ़ोतरी।
- आत्म अनुशासन का विकास।
- कल्पना और रचनात्मकता (विशेष रूप से बच्चों में) का विस्तार।
- मन में प्रसन्नता और संतोष का भाव।
- आत्म जागरूकता में बढ़ोतरी।
- आत्मविश्वास में इजाफा।
- सकारात्मकता में बढ़ोतरी।
- मानसिक ताकत और आत्मसंयम का विकास।
- कुछ मानसिक गड़बड़ियों के लक्षणों में सुधार। (एक प्रकार का पागलपन और एडीएचडी भी शामिल)



- चिंता और अवसाद के लक्षणों को कम करने में मददगार।
 - आत्म ज्ञान को प्रोत्साहन।
 - शरीर की ऊर्जा केंद्रों को उत्तेजित करने में सहयोगी।
 - दैनिक जीवन में सकारात्मक अनुभवों को प्रकट करने की क्षमता में इजाफा।
 - जीवन और जीवन के मकसद के बीच संबंध की खोज।
- एक आंतरिक चेतना के साथ में अपने धुन में होने का भाव पैदा करने में मददगार।
- दूसरों और दुनिया से जुड़ने का गहरा भाव पैदा करता है।



निष्कर्ष

भारत में युवाओं की बड़ी आबादी है और यह प्रशंसनीय है कि वे स्वस्थ जीवनशैली और व्यक्तित्व के विकास में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अपने जीवन से तनाव दूर करने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जरूरत है कि युवा तबका योग को अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा बना ले। भारत सरकार ने हाल के दिनों में योग को प्रोत्साहित करने और इसके विकास के लिए कई पहल किए हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के बड़े और कामयाब समारोह से हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। इस आयोजन से योग के स्वास्थ्य संबंधी फायदों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी और दुनियाभर में योग गुरुओं की मांग में इजाफा हुआ। आयुष मंत्रालय ने भारत के गुणवत्ता नियंत्रण से संपर्क करके योग गुरुओं को प्रमाणित



करने को कहा है। आयुष मंत्रालय देश के अलग-अलग इलाकों में आयुष अस्पताल शुरू करने की योजना बना रहा है। मंत्रालय ने योग को सशस्त्र बलों, अर्द्धसैनिक और पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण का हिस्सा बनाने की शुरुआत की है। कर्मचारी एवं प्रशिक्षण विभाग ने नई दिल्ली में गृह कल्याण केंद्र में योग प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा में छह केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों को शुरू किया जा रहा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी इलाज में चिकित्सा के प्राचीन प्रणालियों को शामिल करने की जरूरत पर जोर दिया है। डब्ल्यूएचओ ने सुरक्षा और क्षमता के मूल्यांकन के लिए रणनीतिक दिशा-निर्देश दिए हैं। यहां इस बात पर भी जोर दिया गया है कि समय की कसौटी पर खरी उतरी योग की प्रणाली को सिर्फ साक्ष्यों अभाव के कारण नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। योग की क्षमता और शक्तियों को अहमियत देने की जरूरत है। इस प्रणाली का इस प्रणाली के अधिकतम इस्तेमाल के लिए नीतिगत पहल और रणनीतिक हस्तक्षेप की जरूरत है।

सेहतमंद जीवनशैली के लिए योग के नियंत्रक और विकास के पहलुओं को देखने के बाद उचित प्रशासनिक तंत्र और सरकार के निरंतर सहयोग की जरूरत है ताकि योग की अहमियत को बढ़ावा दिया जा सके। एक शांत व्यक्ति ही परिवार में शांति ला सकता है। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और अंत में पूरी दुनिया में शांति और सद्भाव लाने का जरिया है। □

→ सिविल सर्विस परीक्षा के इतिहास में पहली बार IAS/PCS दोनों में चयनित मेंटर द्वारा मार्गदर्शन ←

ट्रांसफार्मर
IAS For IAS & PCS

अब बदलेगी हिन्दी
मीडियम की दुनिया

ट्रांसफार्मर
IAS

इंग्लिश मीडियम से बेहतर मार्गदर्शन अब हिन्दी मीडियम में

• टीचिंग हेड •

टी.एन.कौशल



"हिन्दी माध्यम से लगातार गिरती सेलेक्शन दर ने मुझे सर्विस से ब्रेक लेकर यहां आने को प्रेरित किया।"

↓ कौन हैं टी.एन.कौशल ?

- JNU-दिल्ली, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और नवोदय विद्यालय से शिक्षा प्राप्त
- 2007 में UPPCS द्वारा CTO और 2008 में ट्रेजरी ऑफिसर के पद पर चयनित
- 2009 में U.P. में SDM के रूप में चयनित
- 2010 में IAS में चयन और IRS (इनकम टैक्स) में पोस्टिंग
- 2012 से IFS (भारतीय विदेश सेवा) ऑफिसर के रूप में कार्य

"जूता बनाने वाले को कभी पता नहीं होता कि जूता कहां काटेगा, वह जूता पहनने वाला ही जान सकता है। आई.ए.एस. बनाने का दावा करने वाले ये नहीं जान सकते कि समस्या कहां है, वह आई.ए.एस. में सफल होने वाला ही जान सकता है।"

→ UPPCS-2015 में टॉपर वान्या सिंह सहित 20+सेलेक्शन ←

★ Answer writing इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ★

Free +3 day value-addition course for 2016 PCS-aspirants

नोट—यह प्रोग्राम टी.एन. कौशल सर के डायरेक्ट मार्गदर्शन में चलेगा

GS में 300, अनिवार्य हिन्दी व निबंध में 100, एवं वैकल्पिक विषय में 250 से अधिक अंक पाने की रणनीति सीखें

Art of answer writing

कितना लिखें, कैसे लिखें—वैल्यू एडिशन
अंडरलाइन, डायग्राम, ग्राफ का प्रयोग कैसे करें।
वाइट में लिखें कि पैराग्राफ में लिखें।



Vanya Singh
(female topper)

Art of effective-writing

रेखाचित्र, flow-chart और ग्राफ बनाकर अधिक अंक पाने की रणनीति कोटेशन (विचारकों के प्रसिद्ध कथनों) द्वारा उत्तर लेखन की प्रभावी शैली का विकास जो प्रश्न नहीं आते या कम आते हैं उन्हें कैसे डील करें?

★ IAS सिग्नेचर कोर्स (फाउंडेशन+एडवांस्ड) ★

कोचिंग संस्थान बताते हैं कि 'क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है', इससे कहीं आगे यहां आप सीखेंगे कि 'कैसे पढ़ना है और उसे कैसे exam में use करना है'

Exam management

एकजाम के दिनों में नींद न आने की समस्या का हल।
एकजाम के दिन क्या खाएं, कौन से पेन का प्रयोग करें।
एकजाम के प्रेशर को हैंडल करना।
एकजाम हॉल की गलतियों से बचाव

Time Management

लिखने पढ़ने की गति बढ़ाना
अगर आप 1 मिनट में 200 शब्द पढ़ते हैं तो
इस कोर्स के बाद 400 शब्द पढ़ने लगेंगे।
एकजाम हॉल में टाइम सेविंग

Ethics-पेपर IV

टी.एन.कौशल

अधिकतम 50 छात्रों का बैच

सभी शिक्षा शास्त्री मानते हैं कि 300-400 छात्रों की भीड़ के बैच में केवल प्रवचन संभव है, गहन अध्ययन नहीं। अब आप को निर्णय करना है कि आप दिल्ली भीड़ का हिस्सा बनने आते हैं या IAS बनने।

रक्षा
अध्ययन

★ UP-PCS 2016 मेंस का विशेष थ्रस्ट कोर्स ★

(वीकली क्लासेस + टेस्ट सीरीज+कैश कोर्स+QIP)

हिन्दी
साहित्य

by-

सीशल वर्क
आर.कुमार

निबंध
टी.एन.कौशल

ALL टेस्ट सीरीज
2 टेस्ट निशुल्क

अनिवार्य हिन्दी
एच. के. मिश्र

इतिहास
टी.एन.कौशल

आर.प्रभा
(JNU स्कालर)

अनिवार्य हिन्दी—सरकारी पत्र लेखन के सचिवालय से प्राप्त प्रारूप
दर्शन शास्त्र—दिलीप कुमार भूगोल—एस.के.ओझा

निबंध अभिव्यक्ति कौशल के निखार पर बल
लोक प्रशासन—बी. के. त्रिपाठी राजनीति विज्ञान—पी.के.सिंह

→ फ़ैचाइजी/ब्रांच-पार्टनरशिप/कोलेबोरेशन के लिए संपर्क करें ← Wanted-faculty and councillor for branch office

Rajsthan PCS

Weekend batch

MP PCS+BPSC मेंस

Distance/Postal कोर्स

A-1, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, चावला रेस्टोरेण्ट के सामने,
मेन रोड, मुखर्जी नगर

नई दिल्ली 09953126338 09717156339



योग साधकों का मूल्यांकन एवं प्रमाणन

रवि पी सिंह
मनीष पांडे



योग संस्थानों के प्रमाणन की योजना उन मूलभूत नियमों में सामंजस्य बिठाने की दिशा में उठाया कदम है, जिन नियमों पर योग प्रशिक्षण आधारित होना चाहिए एवं इसका उद्देश्य योग शिक्षकों को प्रशिक्षित करने वाले संस्थानों पर विचार किए बगैर उनके लिए परिणाम के मानदंड तैयार करना भी है। मानव शरीर एवं मस्तिष्क के स्तर पर कार्य करने वाले ऐसे अभ्यास आधारित महत्वपूर्ण विज्ञान हेतु यह आवश्यक है कि आरंभ में ही नियम बना दिए जाएं और उन्हें बाज़ार की शक्ति के भरोसे नहीं छोड़ा जाए, जो भारतीय ग्रंथों में समाहित इस विज्ञान की मूल प्रकृति को दूषित कर सकती हैं

भा

रतीय ग्रंथों में योग को प्राचीन विज्ञान कहा गया है, जिसे ऋषियों ने विकसित किया था और शताब्दियों से जिसका अभ्यास किया जा रहा है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के संदर्भ देकर कई वर्षों से योग पर साहित्य तैयार किया गया है। यह पूरे विश्व में फैला हुआ है और इसकी लोकप्रियता तथा मानव मस्तिष्क एवं शरीर पर इसके प्रभाव को पूरे विश्व में स्वीकार किया जाता है। किंतु, अधिकतर लोगों को यह नहीं पता कि योग का विकास जीवन को परिवर्तित करने वाले अनुभव के रूप में हुआ है, जिसमें मानव सभ्यता को बेहतर बनाने की संभावना है।

योग शब्द संस्कृत के शब्द 'युज' से आया है, जिसका अर्थ है 'मिलना' अथवा 'एकाकार होना'। योग को भारतीय समाज एवं संस्कृति में व्याप्त आध्यात्मिक एवं सिद्ध पद्धति माना जाता है। योग के कुछ रूपों (जैसे श्वास पर नियंत्रण, सामान्य ध्यान एवं विशिष्ट शारीरिक मुद्राएं धारण करना अर्थात् आसन) का स्वास्थ्य संबंधी हानियों को दूर करने एवं मानसिक शांति के लिए दुनिया भर में अभ्यास किया जाता है। प्रसिद्ध ऋषि पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए कहा था "योगः चित्त वृत्ति निरोधः", जिसका अर्थ है "मस्तिष्क में परिवर्तन को रोकना ही योग है।" चित्त का अर्थ है मस्तिष्क, वृत्ति का अर्थ है विचारों में संवेग और निरोधः का अर्थ है रोकना।

योग की सही तिथि एवं इतिहास के बारे में विभिन्न प्रकार के अनुमान हैं। किंतु योग की परंपरा अनुमानों से भी अधिक प्राचीन है। भारत में सबसे सम्मानित ग्रंथों जैसे महाभारत²

और भगवद्गीता³ में योग के विस्तृत प्रसंग हैं। गीता ने तीन प्रकार के योग बताए हैं: कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। यह जीवन जीने की पद्धति है, जिसका उल्लेख 1900 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व के मध्य वेदों में मिलता है। पतंजलि के योग सूत्रों में बताए गए पारंपरिक योग में योग के अष्टांगी मार्ग⁴ का उल्लेख है, जो अंग हैं यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान एवं समाधि।

योग सूत्रों में राजयोग की पद्धतियां छिपी हैं, जिन्हें अष्टांग प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया गया है। योग की दार्शनिक परंपरा कपिल मुनि के सांख्य दर्शन पर आधारित है। मस्तिष्क को केंद्र माना गया है। पतंजलि का द्वितीय सूत्र योग को परिभाषित करते हुए कहता है— सभी मानसिक परिवर्तनों का रुकना एवं भटकते हुए सभी विचारों का रुकना ही योग है। योग सूत्रों में मस्तिष्क पर जोर दिया गया है किंतु बाद की योग परंपराओं जैसे हठ योग में अधिक जटिल आसनों अथवा शारीरिक मुद्राओं पर जोर दिया गया है।

आजकल शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं की सहायता से ब्रह्मांड की जीवनी शक्ति अथवा 'कुंडलिनी' के जागरण के लिए भी योग किया जाता है। इस क्रिया में शारीरिक स्तर पर विभिन्न योग क्रियाएं अथवा 'आसन' किए जाते हैं, जिनका लक्ष्य शरीर को स्वस्थ रखना होता है। मानसिक पद्धतियों में मस्तिष्क को अनुशासित एवं श्रेष्ठ बनाने के लिए श्वसन अभ्यास अर्थात् 'प्राणायाम एवं 'ध्यान' किया जाता है।

योग की लोकप्रियता ने दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया है, जो योग

रवि पी सिंह भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) के महासचिव हैं। वह सरकार की कई प्रमुख योजनाओं के अगुआ रहे हैं। इन योजनाओं में लोकसेवाओं में जन शिकायत निष्पादन, एमएसएमई के लिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना, स्वच्छता सर्वेक्षण, योग साधकों का प्रमाणन आदि प्रमुख हैं। ईमेल: sg@qc.in.org मनीष पांडे भी इसी संस्थान में संयुक्त निदेशक हैं। वह भी कई फ्लैगशिप योजनाओं से संबद्ध रहे हैं जिनमें योग साधकों का प्रमाणन भी शामिल है। वह एनएबीजीवी में तकनीकी विशेषज्ञ भी हैं। ईमेल: manish.pande@qc.in.org

द्वारा जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस अत्यंत सफल भारतीय पद्धति में इन लोगों की आस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि दुनिया भर में योग का अभ्यास करने तथा उसे सीखने के इच्छुक लोगों को प्रशिक्षित करने,

योगाभ्यास का प्राथमिक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करने के मामले में सभी संस्थानों का पैमाना एक ही नहीं होगा। जीवन का परिवर्तन करने वाले अनुभव के रूप में योग के लोकप्रिय होने के साथ ही कम समय के लिए आरंभ होने वाले उन व्यावसायिक उपक्रमों को समाप्त करना आवश्यक होगा, जो प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित मूल्यों को समाप्त कर सकते हैं। संस्थानों को मान्यता प्रदान करने से समर्पित संस्थानों को पहचानना आसान हो जाएगा।

रास्ता दिखाने एवं परामर्श देने के लिए इसके आधार एवं ज्ञान का यथोचित उपयोग किया जाए। इसके लिए उन्हें योग का प्रशिक्षण देने हेतु विश्वसनीय एवं सक्षम व्यक्तियों का समूह तैयार करने के लिए तंत्र बनाना होगा ताकि वे इस प्राचीन भारतीय विज्ञान का संपूर्ण लाभ उठा सकें। यह तंत्र तैयार करने के लिए विभिन्न उपायों की आवश्यकता है, जिनमें से एक है योग पेशेवरों की क्षमता का आकलन कर उन्हें प्रमाणित करना। इसमें उनसे पूछा जाएगा कि योग क्यों किया जाए और कैसे किया जाए। योग्यता के मूल्यांकन की प्रक्रिया को वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया गया। ज्ञान, कौशल एवं परिपक्वता के आधार पर योग पेशेवर को प्रशिक्षक, शिक्षक, विशारद अथवा आचार्य की श्रेणी में बांटा जा सकता है। मूल्यांकन की प्रणाली को इस तरह तैयार किया जाता है कि योग पेशेवर का स्तर प्रशिक्षक से बढ़कर जैसे-जैसे आचार्य तक पहुंचता है, प्रदर्शन के स्थान पर अनुभव को अधिक वरीयता दी जाती है।

दूसरा उपाय है योग सिखाने वाले संस्थानों के लिए मान्यता देने का ढांचा तैयार करना, जिसके अंतर्गत योग के दक्षता की डिग्री, डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। योगाभ्यास का प्राथमिक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करने के मामले में सभी संस्थानों का पैमाना एक ही नहीं होगा। जीवन का परिवर्तन करने वाले अनुभव के रूप में योग के लोकप्रिय

होने के साथ ही कम समय के लिए आरंभ होने वाले उन व्यावसायिक उपक्रमों को समाप्त करना आवश्यक होगा, जो प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित मूल्यों को समाप्त कर सकते हैं। संस्थानों को मान्यता प्रदान करने से समर्पित संस्थानों को पहचानना आसान हो जाएगा।

योग विद्यालय प्रमाणन योजना में 4 विभिन्न स्तरों पर योग विद्यालयों का प्रमाणन करने का प्रावधान है। पहला स्तर है बेसिक— जिसमें वे स्कूल आते हैं, जिनमें योग पेशेवरों की स्वैच्छिक प्रमाणन योजना के कम से कम दो आरंभिक स्तरों (प्रशिक्षक एवं शिक्षक) की योग शिक्षा देने की क्षमता है। दूसरा स्तर है स्टेबल—जिसमें वे योग विद्यालय आते हैं, जो बेसिक की आवश्यकताएं पूरी करने के साथ ही योग एसोसिएशन से मंजूरी प्राप्त शिक्षण अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से कम से कम आधी योग शिक्षा देने में सक्षम हैं तथा आईएसओ 29990:2010 की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। तीसरा स्तर मैच्योर स्तर है— जिसमें स्टेबल स्तर की आवश्यकताएं पूरी करने के साथ ही आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण/प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने की क्षमता भी हो। सर्वोच्च स्तर आश्रम स्तर है, जो मैच्योर स्तर की आवश्यकताएं पूरी करने के साथ ही आश्रम जैसी व्यवस्था में 200 घंटे अथवा अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में योग शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। प्रत्येक स्तर के लिए आवश्यकताएं अलग-अलग निर्धारित की गई हैं। इन प्रमाणित विद्यालयों से निकलने वाले छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए दिन भर चलने वाले पुस्तकीय एवं प्रायोगिक मूल्यांकन के बजाए मौखिक साक्षात्कार लेकर उन्हें योग पेशेवर प्रमाणन प्रदान किया जाएगा, जैसा सीधे आने वाले आवेदक के लिए किया जाता है।

चुनौती

योग पेशेवर की क्षमता का मूल्यांकन करने में यह चुनौती है कि शिक्षक से छात्र को प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन हो सकता है अथवा नहीं। दूसरी समस्या यह आती है कि क्या अन्य व्यक्ति चित्त का परीक्षण, मूल्यांकन एवं मापन कर सकते हैं। क्या किसी अन्य व्यक्ति के लिए यह देखना संभव है कि किसी व्यक्ति के मन में किस प्रकार की वृत्ति चल है?²

योग पेशेवरों का प्रमाणन चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि योग को अनुभवजन्य विज्ञान माना जाता

है। कुछ लोग मानते हैं कि योग में ज्ञान एवं कौशल का प्रमाणन उसे अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयास है। योग का सार उसकी व्यक्तिपरकता, गहराई एवं विवेचना में है।

वर्तमान चुनौती का एक आयाम शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान कर रहे योग संस्थानों से भी आता है। हमारे देश में और दुनिया भर में कई प्रतिष्ठित योग संस्थान हैं एवं असंख्य छोटे संस्थान हैं, जो योग के संवर्द्धन में जुटे हैं तथा योग शिक्षकों का प्रशिक्षण देने के लिए पाठ्यक्रम चलाते हैं। विभिन्न संस्थानों के ये पाठ्यक्रम समयावधि और सामग्री दोनों में एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। इसीलिए इन शिक्षकों में भी कौशल तथा ज्ञान के मामले में विशेषज्ञता तथा दक्षता के स्तर अलग-अलग होते हैं। इसके अलावा विभिन्न संस्थानों में अभ्यास भी अलग-अलग होते हैं। ये भिन्नताएं ही इस विज्ञान को जीवंत एवं समावेशी बनाती हैं। किंतु इनके कारण योग सीखने वालों के मन में अनिश्चिन्ता भी आती है कि योग का सही रूप कौन सा है और किसका पालन करना आवश्यक है।⁶

जब कोई चलन लोकप्रिय होता है, विभिन्न वर्ग अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार उसकी विवेचना करने लगते हैं। जब ऐसी शैक्षिक एवं कई बार शिक्षा से इतर चर्चाएं स्वयं को उस मूल आधार से बिल्कुल अलग कर देती हैं, जिन पर ये शताब्दियों से आधारित रही हैं तो विषय की गंभीरता कम हो जाती है। योग पर भी स्वाभाविक रूप से यह खतरा मंडरा रहा है।

कई वर्षों से भारत एवं विदेश में गुरुओं ने योग की अपनी व्याख्याओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, जिसे उनके अनुगामी तब तक अपनाते रहे हैं, जब तक उससे उन्हें संतुष्टि,

योग पेशेवरों का प्रमाणन चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि योग को अनुभवजन्य विज्ञान माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि योग में ज्ञान एवं कौशल का प्रमाणन उसे अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयास है। योग का सार उसकी व्यक्तिपरकता, गहराई एवं विवेचना में है।

शांति एवं स्वास्थ्य प्राप्त हुआ है। कभी-कभी ये व्याख्याएं प्रतिपादक के अनुभवों पर आधारित होती हैं, जो प्रत्येक आश्रम अथवा संस्थान के लिए अलग-अलग होती हैं। योग को अधिक से अधिक वैज्ञानिक, अधिक से अधिक

सर्वव्यापी एवं वस्तुनिष्ठ बनाने की प्रक्रिया में प्रमाणन की योजना क्या योग के व्यक्तिपरक, अनुभवजन्य, अनूठे पक्षों की बलि नहीं चढ़ा देगी? यह भी बड़ी चुनौती है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए इस योजना

स्वैच्छिक योग पेशेवर प्रमाणन योजना का केंद्र बिंदु उन योग पेशेवरों की योग्यता को प्रमाणित करना है, जो प्रशिक्षकों के रूप में योग का अभ्यास कराते हैं, शिक्षकों के रूप में शिक्षा एवं प्रशिक्षण देते हैं, विशारद के रूप में दुनिया भर में औपचारिक तथा अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से इस विज्ञान का अभ्यास करते हैं एवं इसे प्रोत्साहित करते हैं।

को तैयार करते समय कुछ मूलभूत निर्देश तय किए गए। यह तय किया गया कि प्रमाणन की प्रक्रिया योग से उसका सार न छीने एवं विभिन्न योग विद्यालयों/संस्थानों का अनूठापन समाप्त नहीं करे। योग को वैज्ञानिक बनाकर उसका आकर्षण बढ़ाया जाना चाहिए, किंतु उसके दार्शनिक, अनुभवजन्य एवं आध्यात्मिक पक्षों की बलि नहीं चढ़ाई जानी चाहिए। योग को सार्वभौमिक आकर्षण वाला विज्ञान बनाने के प्रयास में व्यक्तिपरकता एवं अनुभव के सार को गंवाया नहीं जाना चाहिए।

समाधान

विश्व भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को तब और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, जब संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों के कारण योग को हमारी प्राचीन विरासत एवं धरोहर के रूप में पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। एक तरह से भारत ने योग में विश्व नेता के रूप में अपनी भूमिका को पुनः स्थापित किया। इसके साथ ही योग को उसके वास्तविक एवं विशुद्ध स्वरूप में संजोने एवं बढ़ावा देने का बड़ा दायित्व भी आ गया है।

यह सब करने के लिए और 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा होने के कारण आयुष मंत्रालय ने योग पेशेवरों के मूल्यांकन एवं प्रमाणन हेतु योजना तथा योग संस्थानों के प्रमाणन की योजना तैयार करने हेतु भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) को यह देखते हुए चुना कि क्यूसीआई के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर

के सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों पर आधारित गुणवत्तापूर्ण प्रारूप तैयार करने में महारत है।

स्वैच्छिक योग पेशेवर प्रमाणन योजना का केंद्र बिंदु उन योग पेशेवरों की योग्यता को प्रमाणित करना है, जो प्रशिक्षकों के रूप में योग का अभ्यास कराते हैं, शिक्षकों के रूप में शिक्षा एवं प्रशिक्षण देते हैं, विशारद के रूप में दुनिया भर में औपचारिक तथा अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से इस विज्ञान का अभ्यास करते हैं एवं इसे प्रोत्साहित करते हैं अथवा आचार्य के रूप में इस विज्ञान की रोगनिरोधी एवं उपचारात्मक आवश्यकताओं के लिए चिकित्सकीय ज्ञान से परिचित हैं एवं उसका प्रयोग करते हैं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएसओ 17024:2012 में निर्धारित सिद्धांतों एवं आवश्यकताओं का पालन किया जाता है। विभिन्न स्तरों के योग पेशेवरों के प्रमाणन की क्यूसीआई की योजना सभी प्रकार की विविधताओं को समाहित करते हुए सभी योग साधकों के योग संबंधी कौशल एवं ज्ञान के लिए स्वीकार्य मानदंड तैयार करने का प्रयास है, जिसमें साधकों ने योग का औपचारिक अथवा अनौपचारिक प्रशिक्षण किसी भी संस्थान से प्राप्त किया हो सकता है। यह प्रमाणन सभी प्रमाणित योग पेशेवरों की योग के अभ्यास एवं सिद्धांतों की मूलभूत एवं सामान्य समझ का साक्षी होगा। एक प्रकार से प्रमाणन योग साधकों के कौशल एवं ज्ञान दोनों की गुणवत्ता की गारंटी देगा। साथ ही प्रमाणन के प्रस्तावित स्तरों में योग साधकों के दो महत्वपूर्ण पहलुओं कौशल एवं ज्ञान के आधार पर योग पेशेवरों का एक अनुक्रम तैयार करने का विचार भी है।

योग संस्थानों के प्रमाणन की योजना उन मूलभूत नियमों में सामंजस्य बिठाने की दिशा में उठाया कदम है, जिन नियमों पर योग प्रशिक्षण आधारित होना चाहिए एवं इसका उद्देश्य योग शिक्षकों को प्रशिक्षित करने वाले संस्थानों पर विचार किए बगैर उनके लिए परिणाम के मानदंड तैयार करना भी है। मानव शरीर एवं मस्तिष्क के स्तर पर कार्य करने वाले ऐसे अभ्यास आधारित महत्वपूर्ण विज्ञान हेतु यह आवश्यक है कि आरंभ में ही नियम बना दिए जाएं और उन्हें बाज़ार की शक्ति के भरोसे नहीं छोड़ा जाए, जो भारतीय ग्रंथों में समाहित इस विज्ञान की मूल प्रकृति को दूषित कर सकती हैं। प्रमाणन की इस प्रक्रिया के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते समय योग को एकदम

विशुद्ध रूप में स्थापित करने एवं प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

यह योजना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं एवं वैश्विक मानक एवं प्रमाणन प्रणाली के अनुरूप तैयार की गई है, ताकि प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य हो। इससे योग में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को समान प्रशिक्षण सुनिश्चित होगा और इस प्रकार का ज्ञान एवं प्रशिक्षण देने वाले योग शिक्षकों का प्रशिक्षण भी सुनिश्चित होगा।

योग संस्थानों के प्रमाणन की प्रक्रिया एक मानक की सहायता से तैयार की गई है, जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों एवं संस्थान में अपनाई जा रही प्रक्रिया के परिणामों पर ध्यान देता है। यह मानक प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों पर भी जोर देता है। चूंकि संस्थान की योग्यता पर ध्यान केंद्रित होगा, इसलिए इससे योग पाठ्यक्रम की संरचना, विकास एवं आपूर्ति तथा कौशल एवं ज्ञान के समुचित मूल्यांकन एवं आकलन में सहायता मिलेगी। योजना इस प्रकार से तैयार की गई है कि इससे व्यक्तिगत संस्थान को अपनी विरासत बरकरार रखने एवं आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलता है।

इसका उद्देश्य ऐसे योग पेशेवरों अथवा संस्थानों के चयन में संगठनों एवं व्यक्तियों की सहायता करना है, जो दक्षता एवं क्षमता विकास के विषय में संगठन अथवा व्यक्तियों की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को पूरा करते हों। क्यूसीआई *तृतीय पक्ष मूल्यांकन* के वैश्विक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए योग पेशेवरों तथा योग संस्थानों के प्रमाणन की योजनाएं संचालित करेगी। यह प्रक्रिया योग पेशेवरों/योग संस्थानों द्वारा पूरा किए जाने वाले दक्षता मानकों के रूप में परिभाषित

योग संस्थानों के प्रमाणन की प्रक्रिया एक मानक की सहायता से तैयार की गई है, जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों एवं संस्थान में अपनाई जा रही प्रक्रिया के परिणामों पर ध्यान देता है। यह मानक प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों पर भी जोर देता है।

करने, प्रमाणन प्रक्रिया विकसित कर मूल्यांकन की प्रक्रिया को परिभाषित किए जाने तथा आधिकारिक मान्यता के माध्यम से मूल्यांकन इकाइयों की दक्षता एवं परिचालन की आवश्यकताएं निर्धारित करने के साथ आरंभ होती है।

क्यूसीआई ने योजना तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की बहुपक्षीय समिति बनाई है, जिसमें सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व है। योजना की शीर्ष समिति अर्थात् संचालन समिति का अध्यक्ष श्री श्री रवि शंकर कर रहे हैं तथा उसे दो सहायक समितियों तकनीकी समिति एवं प्रमाणन समिति से सहायता प्राप्त हो रही है। तकनीकी मानक विकसित करने वाली तकनीकी समिति की अध्यक्षता डॉ. एच. आर. नागेंद्र कर रहे हैं तथा प्रमाणन की प्रक्रिया हेतु नियम तैयार करने वाली प्रमाणन समिति की अध्यक्षता श्रीमती हंसाजी जे. योगेंद्र कर रही हैं। इन समितियों में विभिन्न पक्षों जैसे योग विभूतियों, योग विद्यालयों, संबंधित मंत्रालयों यथा आयुष, वाणिज्य मंत्रालयों, शैक्षिक संस्थानों, उपभोक्ता संगठनों, संभावित प्रमाणन एजेंसियों आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं।

इस संबंध में संपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक सलाहकार समिति है, जिसमें समितियों के प्रमुख एवं स्वामी रामदेव, ब्रह्म कुमारी शिवानी, सद्गुरु वासुदेव जग्गी जैसी योग विभूतियां हैं। क्यूसीआई ने अब योग पेशेवरों के प्रमाणन की योजना तैयार कर ली है, जिसके निम्नलिखित भाग हैं:

1. सहभागी संगठनों एवं समितियों का स्वरूप, घटक, भूमिकाएं एवं दायित्व।
2. प्रमाणन के मानदंड-प्रमाणन के मानक, जो विशेषज्ञों की तकनीकी समिति की चर्चाओं के बाद तय किए जाएंगे।
3. प्रमाणन की प्रक्रिया-आरंभिक मूल्यांकन, निरीक्षण की आवृत्ति, मूल्यांकनकर्ताओं की आवश्यकताएं आदि।
4. प्रमाणन इकाइयों की आवश्यकताएं।

एक समर्पित वेबसाइट www.yoga certification.qci.org.in बनाई गई है तथा सभी जानकारी इस पर उपलब्ध है।

अवसर: प्रमाणित व्यक्तियों को प्रोत्साहन

भारत सरकार ने क्यूसीआई की योजना का समर्थन किया है और विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर योजना को सक्रियता के साथ बढ़ावा देती रही है। सफल योग पेशेवरों को जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों पर आयुष मंत्रालय की मोहर है, जिससे इसे आवश्यक विश्वसनीयता प्राप्त होती है और यह गर्व का विषय बन जाते हैं।

सरकार योग पेशेवरों को विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है, जिसमें सरकारी भर्तियों में वरीयता देना, वर्तमान पेशेवरों को क्यूसीआई योग पेशेवर प्रमाणन से अपनी योग्यता प्रमाणित कराने का अधिकार देना, सीबीएसई, केंद्रीय विद्यालय संगठन जैसे विभिन्न बोर्डों से योग शिक्षकों की नियुक्ति में प्रमाणन लागू करने का आग्रह करना, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय जैसे विभिन्न विभागों को वीजा जारी करने में ढिलाई देने, वीजा शुल्क समाप्त करने अथवा कम करने जैसी रियायतों की घोषणा करने के लिए कहना शामिल है।

सरकार योग पेशेवरों को विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहित करने पर विचार करती रही है, जिसमें सरकारी भर्तियों में वरीयता देना, वर्तमान पेशेवरों को क्यूसीआई योग पेशेवर प्रमाणन से अपनी योग्यता प्रमाणित कराने का अधिकार देना, सीबीएसई, केंद्रीय विद्यालय संगठन जैसे विभिन्न बोर्डों से योग शिक्षकों की नियुक्ति में प्रमाणन लागू करने का आग्रह करना, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय जैसे विभिन्न विभागों को वीजा जारी करने में ढिलाई देने, वीजा शुल्क समाप्त करने अथवा कम करने जैसी

रियायतों की घोषणा करने के लिए कहना शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद से अनुरोध किया गया है कि विदेश में सभी नियुक्तियों के लिए प्रत्याशियों को इस योजना के अंतर्गत प्रमाणन पाना अनिवार्य कर दिया जाए। आयुष मंत्रालय ने पहले प्रयास में ही सफल होने वाले प्रथम 2000 प्रत्याशियों के शुल्क की 100 प्रतिशत वापसी क्यूसीआई के माध्यम से किए जाने की घोषणा की है।

क्यूसीआई को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि योग पेशेवर योजना विश्व भर में आरंभ कर दी गई है। क्यूसीआई के एक दल ने मूल्यांकन हेतु जापान का दौरा किया, जहां 13 योग पेशेवरों को इस योजना के अंतर्गत प्रमाणित किया गया है। ऐसा विचार है कि एक समय के उपरांत योग पाठ्यक्रम संचालित करने वाले विश्वविद्यालय, औपचारिक एवं अनौपचारिक योग संस्थान अथवा विद्यालय, हेल्थ रिसॉर्ट, स्पा, योग स्टूडियो पेशेवरों को केवल तभी भर्ती करेंगे, जब उन्हें क्यूसीआई योग योजना के अंतर्गत प्रमाणन प्राप्त हो।

संदर्भ

1. पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच हुए योग के महानतम प्रतिपादक पंतजलि ने योग सूत्र का संकलन किया, जो योग दर्शन का मूलभूत ग्रंथ है एवं मस्तिष्क एवं चेतना के दार्शनिक पक्षों का बहुत प्रमुख ग्रंथ हैं
2. महाभारत भारत के दो महान महाकाव्यों में से एक, दूसरा रामायण है
3. भगवद्गीता महाभारत का अंग है तथा इसमें 18 अध्याय हैं। पंतजलि योग सूत्र के साथ यह भी योग पर अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है
4. पंतजलि के अष्टांग योग का अंतिम लक्ष्य कैवल्य प्राप्त करना है, जहां मानव जीवन के सभी कष्टों का अंत हो जाता है
5. डॉ. जे योगेंद्र एवं अन्य, 2016, लेख, योग एंक्रेडिटेशन नॉर्म्स, पृष्ठ 50
6. डॉ. गणेश राव, योग विशेषज्ञ, भारतीय गुणवत्ता परिषद

योजना

आगामी अंक

जुलाई 2016

जल: एक अनमोल संसाधन





योग: स्वस्थ व तनावमुक्त जीवन का संतुलन

ईश्वर एन आचार्य
राजीव रस्तोगी



आज की व्यस्त जीवनशैली में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख पाना एक जटिल कार्य हो गया है लेकिन इसी जीवनशैली में थोड़ा-सा बदलाव कर व कुछ आदतों को सम्मिलित कर हम स्वयं को स्वस्थ व तनावयुक्त रख सकते हैं। योग स्वास्थ्य व तनावमुक्त जीवन की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। योग के महत्व को समझते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अब मान्यता मिल चुकी है। गत वर्ष 21 जून को प्रथम विश्व योग दिवस के आयोजन के बाद से अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने योग के प्रति अपना दृष्टिकोण बदला है

योग स्वास्थ्य, समग्र जीवन की परंपरागत प्रणाली है और भारत से उपजा प्राचीन विज्ञान है, जिसकी जड़ें इस देश की परंपरा और संस्कृति में समाई हैं। इसका विकास हजारों वर्ष पहले संतों और ऋषियों ने किया था। बढ़ती चुनौतियां जो स्वास्थ्य सेवा की बदलती आवश्यकताओं के लिए उत्तरदायी हैं, उनसे निपटने के लिए योग पद्धतियां अब दुनिया भर में व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाने लगी हैं। योग अपनी सादगी, किफायत और जीवन शैली के साथ ही साथ मनोदैहिक विकारों से निपटने की क्षमता कारण विश्व में सभी के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। योग शारीरिक भंगिमाओं, श्वसन संबंधी आसनों और प्राणायाम का मिश्रण है, जो व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को संतुलित रूप से निखारता और विकसित करता है।

समाज के विभिन्न तबकों के लोग अब योग पद्धतियों से ज्यादा से ज्यादा अवगत हो रहे हैं और योग की भूमिका अब केवल सकारात्मक स्वास्थ्य के रक्षण एवं प्रोत्साहन तक ही नहीं, बल्कि विभिन्न बीमारियों/ परिस्थितियों की रोकथाम और उनसे निपटने में भी है। वैज्ञानिकों और अन्य चिकित्सा व्यवसायियों ने तनाव और अन्य मनोदैहिक कारणों से होने वाले विकारों की रोकथाम और उनसे निपटने में योगिक जीवन के महत्व को समझा है। ज्यादा स्वस्थ, सार्थक, संतुलित और तनावमुक्त जीवन बिताने वाले युवाओं सहित समस्त लोगों के लिए योग के लाभ समय की कसौटी पर खरे उतरने वाले, बेहद किफायती, सरल और उपयोगी हैं।

योग की लोकप्रियता भारत ही नहीं विदेश तक जा पहुंची है और बहुत से देशों में युवाओं द्वारा योग पद्धतियों का अभ्यास किया जा रहा है। योग में क्षेत्र, धर्म, जाति, संप्रदाय और राष्ट्रीयता की कोई सीमा नहीं है। योग के द्वार सभी के लिए खुले हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा स्वास्थ्य को मात्र रोग अथवा रुग्णता का अभाव नहीं, अपितु संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली की अवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। उसने चौथे आयाम यानी *आध्यात्मिक सुख* का भी सुझाव दिया है। संपूर्ण स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक सुख के मिश्रण के माध्यम से प्राप्त होता है।

यहीं योग की भूमिका प्रारंभ होती है। यह हमारे व्यक्तित्व का संपूर्ण एवं संतुलित तरीके से अर्थात् जीवन के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्तरों का एक ही समय विकास करता है। इसका नियमित अभ्यास हमारी क्षमता बढ़ाता है और विश्वास के स्तर को बेहतर बनाता है। योग में युवाओं को ज्यादा स्वस्थ, संतुलित, तनावमुक्त और सार्थक जीवन की दिशा में परिवर्तित करने की शक्ति है। यह व्यक्ति को सिखाता है कि वह क्या करे और क्या न करे (पांच यम और पांच नियम)। योग पद्धतियों का पालन आसान है और उन्हें आवश्यकता के अनुसार हमारी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है।

औद्योगिकीकरण और भाग-दौड़ भरी महानगरीय जीवन शैली ने हमारे समक्ष

परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के वैश्विक संवर्द्धन के लिए समझौता

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने पारंपरिक एवं पूरक चिकित्सा में उपचार की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए सहयोग हेतु ऐतिहासिक परियोजना सहयोग समझौते (पीसीए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

पीसीए का लक्ष्य डब्ल्यूएचओ पारंपरिक एवं पूरक चिकित्सा रणनीति:

2014-2023 के विकास एवं क्रियान्वयन में डब्ल्यूएचओ का सहयोग करना है तथा यह पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित करने में

योगदान करेगा। 2016 से 2020 की अवधि के लिए पीसीए पहली बार योग में प्रशिक्षण के लिए डब्ल्यूएचओ का मानदंड दस्तावेज तैयार करेगा और आयुर्वेद, यूनानी एवं पंचकर्म चिकित्सा के लिए डब्ल्यूएचओ के मानदंड प्रदान करेगा। पारंपरिक चिकित्सा उत्पादों एवं पद्धतियों के लिए नियामकीय ढांचा स्थापित करने एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में उनके एकीकरण को प्रोत्साहित करने समेत पारंपरिक चिकित्सा की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होगा।

प्रदूषण, तनाव, चिंता आदि जैसी चुनौतियां बढ़ा दी हैं। इनसे निपटते हुए हमारी जीवन शैली प्रभाव से लेकर देर रात तक बहुत तेज रफ्तार वाली और यांत्रिक बन चुकी है। रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे खान-पान की आदतें स्वस्थ नहीं हैं। डिब्बाबंद भोजन, फास्ट फूड, जंक फूड, अधिक कैलोरी वाले भोजन के अलावा धूम्रपान, मदिरा, मादक पदार्थों के सेवन और उचित आराम एवं कसरत के अभाव ने हमें असहिष्णु बना दिया है, जिसकी परिणति विविध प्रकार के मनोदैहिक रोगों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गठिया, पीठ दर्द आदि में हुई है। इन कारणों से मानसिक बीमारियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा पाया गया है कि बड़ी संख्या में लोग अवसाद, स्किजोफ्रीनिया, मदिरा और मादक पदार्थों के इस्तेमाल से संबंधित विकारों से पीड़ित हो रहे हैं। योग उपचार का चीर-फाड़ रहित (नॉन इन्वेसिव) तरीका है, जो शरीर और मस्तिष्क का उपचार विभिन्न प्रकार की पद्धतियों जैसे आसन, प्राणायाम, शटकर्म, सूर्य नमस्कार और ध्यान के माध्यम से प्रभावपूर्ण तरीके से करता है। चिंता, अवसाद, तंत्रिका रोग, व्यवहारगत हानियां/विकार, अरुचि आदि जैसे विविध प्रकार के मानसिक रोग और सिरदर्द, ब्रॉकाइटिस, दमा, मधुमेह, स्वप्रतिरक्षित विकार आदि जैसी मनोदैहिक बीमारियों से योगाभ्यास के माध्यम से बहुत अच्छे से निपटा जा सकता है।

तनाव और चिंता युवाओं की सबसे आम समस्याओं में से एक है। तनाव चाहे शारीरिक हो या मानसिक, बाहरी अथवा आंतरिक कारणों

से होता है। जीवन में आए बदलाव, कार्य या स्कूल, रिश्तों के उलझाव, वित्तीय समस्याएं, अत्यधिक व्यस्तता और बच्चे व परिवार तनाव के सामान्य बाहरी कारण माने जा सकते हैं। हालांकि, स्थाई चिंता, निराशावाद, अपने बारे में नकारात्मक बातें करना, अव्यवहारिक अपेक्षाएं/उत्कृष्ट से कम कुछ भी स्वीकार न करने का स्वभाव, विकल्पों पर गौर न करना, लचीलेपन का अभाव, सब कुछ या कुछ भी नहीं वाला दृष्टिकोण, तनाव के सामान्य आंतरिक कारण माने जाते हैं। भावनात्मक असंतुलन, अस्थिरता और चिंता, मानसिक तनाव की सामान्य अभिव्यक्तियां हैं। ये मनोदैहिक रोगों की स्थितियां हैं, जिनमें सिरदर्द, अनिद्रा, एंठन, चकत्ते, पाचन संबंधी विकार, पेट्टिक अल्सर, कोलाइटिस, घबराहट, उच्च रक्तचाप, कोरोनरी श्राम्बोसिस, डिस्मेनरीआ आदि जैसी शिकायतें होती हैं। आसन, प्राणायाम और ध्यान के नियमित अभ्यास की उनसे निपटने में बहुत बड़ी भूमिका है। आसन शरीर और मस्तिष्क को स्थिरता एवं विश्रान्ति देते हैं, चिंतन की नई प्रक्रिया का मार्ग खोलते हैं और एकाग्रता को विकसित करते हैं, जिससे अंततः उस व्यक्ति के दृष्टिकोण में बदलाव आता है। गहरे सांस लेना, योग निद्रा और ध्यान का अभ्यास नकारात्मक दृष्टिकोण में कमी लाते हैं तथा शांति व आंतरिक आनंद लाते हैं और आशावादी चिंतन उत्पन्न करते हैं।

युवाओं द्वारा अपनी जीवनशैली को ज्यादा स्वस्थ, संतुलित और तनावमुक्त बनाने

के लिए उसमें स्वस्थ जीवनशैली की कुछ आदतें शामिल की जा सकती हैं। ये आदतें तंदुरुस्त रहने और बीमारियों की रोकथाम के लिए अच्छी हैं। ये सरल, किफायती, पालन करने में आसान हैं और इन्हें आवश्यकता के अनुसार दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। प्राकृतिक जीवनशैली एक-दूसरे के बीच प्रेम और आसक्ति बढ़ाती है और भावनात्मक लगाव उत्पन्न करती है। यह शांति, भाईचारे और आशावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। इनमें से कुछ आदतें निम्नलिखित हैं :

संतुलित भोजन

पहली और सबसे महत्वपूर्ण आदत है संतुलित भोजन। जहां तक हो सके हमारा भोजन अवश्य प्राकृतिक स्वरूप में होना चाहिए। हमारी खुराक में ताजा मौसमी फल, ताजा हरी पत्तेदार सब्जियां और अंकुरित वस्तुएं आदि पर्याप्त मात्रा में शामिल होनी चाहिए। क्षारीय होने के कारण, यह भोजन सेहत को बेहतर बनाने, शरीर की शुद्धि करने और उसे रोगों से प्रतिरक्षित रखने में सहायता करता है।

उपवास

उपवास स्वास्थ्य के रक्षण की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। यह पूरे पाचन तंत्र को आराम पहुंचाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान, भोजन को पचाने वाली महत्वपूर्ण ऊर्जा पूरी तरह शरीर के विशहरण में संलग्न हो जाती है। यह शरीर और साथ ही साथ मस्तिष्क के विकारों को मिटाने का शानदार उपाय है। अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए फलों का रस और फलों का सेवन करते हुए साप्ताहिक उपवास रखने की सलाह दी जाती है।

नियमित व्यायाम

किसी भी तरह का नियमित व्यायाम या यौगिक पद्धतियां अच्छी सेहत के लिए अनिवार्य हैं। इनसे रक्त संचरण बढ़ता है और शरीर में लचीलापन आता है। इनसे एजिंग प्रॉसेस (बुढ़ापे की प्रक्रिया) में कमी आती है और अच्छी सेहत बरकरार रहती है। इस उद्देश्य के लिए हम सुबह की सैर, दौड़, जॉगिंग, योगासन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम अथवा अपनी क्षमता और पसंद के मुताबिक बागवानी आदि जैसे शारीरिक कार्य का चयन कर सकते हैं। व्यायाम शरीर को स्फूर्ति देते हैं, ऊर्जा बढ़ाते

हैं और अन्य मनोदैहिक फायदों सहित नई एवं आशावादी सोच उत्पन्न करते हैं। जाने-माने प्राकृतिक चिकित्सक डॉ. हेनरी लिंडलर का कहना है, “व्यायाम उत्तकों में मौजूद बीमार उत्पन्न करने वाले पदार्थों के संग्रह में हलचल पैदा करते हैं, धमनी और शिंया के संचरण को बढ़ाते हैं, फेफड़ों का उनकी पूर्ण क्षमता में फैलाव करते हैं, और इस प्रकार ऑक्सीजन का ग्रहण बढ़ाते हैं तथा अपशिष्ट और रोग फैलाने वाले पदार्थों को त्वचा, गुर्दे, आंतों, और श्वसन प्रणाली के जरिए बाहर करने में बहुत असरदार ढंग से प्रोत्साहित करते हैं।”

आराम

यौगिक क्रियाओं के अलावा, उचित आराम यानी अच्छी नींद भी अच्छी सेहत के लिए आवश्यक है। अच्छी नींद हमें ताजगी देती है, हमें खुश और फुर्तीला रखती है। पूरी नींद नहीं लेने से तनाव व चिंता उत्पन्न होती है और सेहत बिगड़ती है। इसलिए अच्छी नींद से कभी समझौता नहीं करना चाहिए।

पर्याप्त मात्रा में पानी पीना

पर्याप्त मात्रा में पानी पीना विकारों की रोकथाम और सेहत बरकरार रखने के लिए अच्छा है। पानी शरीर की विशाक्तता को समाप्त करता है और शरीर को आंतरिक तौर पर स्वच्छ करता है। स्वस्थ जीवन शैली की आदतों के रूप में कुछ स्वर्णिम नियम जिनका सभी को पालन करना चाहिए वे निम्नलिखित हैं:

1. रात को जल्दी सोना और सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्ममूर्हूर्त में जागना चाहिए। सात घंटे की गहरी नींद लेने की कोशिश करनी चाहिए।
2. साधारण, संतुलित और सात्विक भोजन करना चाहिए।
3. चीनी, नमक, गरिष्ठ भोजन, लाल मिर्च, ज्यादा मसालों और अचार आदि की मात्रा

योग उपचार का चीर-फाड़ रहित (नॉन इन्वेसिव) तरीका है, जो शरीर और मस्तिष्क का उपचार विभिन्न प्रकार की पद्धतियों जैसे आसनों, प्राणायाम, शटकर्म, सूर्य नमस्कार और ध्यान के माध्यम से प्रभावपूर्ण तरीके से करता है। चिंता, अवसाद, तंत्रिका रोग, व्यवहारगत हानियां/विकार, अरुचि आदि जैसे विविध प्रकार के मानसिक रोग और सिरदर्द, ब्रोंकाइटिस, दमा, मधुमेह, स्वप्रतिरक्षित विकार आदि जैसी मनोदैहिक बीमारियों से योगाभ्यास से बहुत अच्छे से निपटा जा सकता है।

- घटानी चाहिए। चाय और कॉफी कम पीनी चाहिए। सभी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन बंद कर देना चाहिए। घी और तेल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। योग साधक के लिए शाकाहारी भोजन अच्छा है।
4. भोजन का समय तय होना चाहिए। सुबह योगाभ्यास करने के आधे घंटे बाद नाश्ते में फल या अंकुरित अनाज या दलिया

- लेना चाहिए। दोपहर के भोजन में गेहूं की रोटी, भाप में पकी सब्जियां, सलाद और छाछ का सेवन किया जा सकता है। सब्जियों और सलाद की मात्रा रोटी से अधिक होनी चाहिए।
5. भोजन के साथ पानी नहीं पीने की सलाह दी जाती है। भोजन से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में पानी पीने की आदत डालनी लीजिए।
6. रोजाना सुबह या शाम को प्रार्थना या ध्यान करना चाहिए। इससे चिंता और तनाव से मुक्ति मिलती है, शरीर और मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है।
7. योग क्रियाओं और शटकर्म शरीर की आंतरिक और बाह्य सफाई के लिए महत्वपूर्ण है।
8. प्रकृति पर भरोसा करना चाहिए। यह आपको सकारात्मक और विश्वास से भरपूर बनाता है।
9. ज्यादा खाने की आदत से बचना चाहिए। भूख नहीं होने पर भोजन नहीं करने के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। भूख लगने पर खाना चाहिए और जब कुछ भूख बाकी हो, तो खाना बंद कर देना चाहिए। मौसमी फलों का सेवन करते हुए सप्ताहिक उपवास रखना चाहिए।
10. ज्यादा से ज्यादा पैदल चलने की सलाह दी जाती है। यह शरीर और मस्तिष्क के लिए लाभदायक है।

भारत: दुनिया में सबसे तेज वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था



I
A
S

सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों की विश्वसनीय संस्था

P
C
S

आस्था IAS

कक्षा के साथ भी, कक्षा के बाद भी...

सामान्य अध्ययन



R. Kumar

कक्षा की विशेषताएं

- आधुनिक तकनीक के साथ नियमित कक्षा
- अद्यतन एवं परीक्षोपयोगी अध्ययन सामग्री
- प्रत्येक कक्षा की विडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध

★ अर्थव्यवस्था	आर. कुमार
★ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	आर. कुमार
★ राजव्यवस्था, गवर्नेंस, एथिक्स	राजीव रंजन सिंह
★ सामाजिक मुद्दे एवं न्याय	पंकज मिश्रा
★ भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	सुबोध मिश्रा
★ इतिहास एवं कला संस्कृति	डॉ. संजय सिंह, एस पी. शाही
★ आंतरिक सुरक्षा	IAS Allied
★ अंतरराष्ट्रीय संबंध	आर. कुमार, निपुण आलम्बायन

नया फाउंडेशन बैच प्रारम्भ...

14 June

आपकी सफलता,
हमारा संकल्प...

आवासीय सुविधा, पत्राचार पाठ्यक्रम एवं घर बैठे ऑनलाइन क्लासरूम सुविधा उपलब्ध

M-1A Jyoti Bhawan, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9
9540038080, 9810664003, 8800233080



योग: स्वास्थ्य एवं जीवनशैली का विकास

एच आर नागेंद्र



योग चिकित्सा में पहला सत्य तो यही है कि यह मानवीय तंत्र को वैज्ञानिक एवं संपूर्ण दृष्टि में देखता है। मानव शरीर के क्रियाकलाप में प्राण की भूमिका का समग्र ज्ञान आवश्यक है। योग विज्ञान के अनुसार आधि के कारण एवं प्राण में विकृति आने अथवा प्राण में कमी आने के कारण रोग होते हैं। योग विज्ञान रोगों को दो व्यापक श्रेणियों में बांटता है: (1) परिस्थितिजन्य रोग एवं (2) प्रारब्ध कर्म के कारण होने वाले रोग। दोनों स्थितियों में प्राण के प्रवाह में रुकावट आती है किंतु उनके उपचार में अंतर है। योग चिकित्सा में प्राण के शुद्धिकरण में जीवनशैली तथा महत्वपूर्ण भूमिका होती है

योग शब्द मूल रूप से संस्कृत के युज् से आया है, जिसका अर्थ है मिलन, जोड़ना और निर्देश देना तथा ध्यान केंद्रित करना। 3,000 वर्ष से भी पुरानी परंपरा वाले योग को अब पाश्चात्य जगत में सर्वांगीण स्वास्थ्य पद्धति माना जाता है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान इसे पूरक एवं वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में मान्यता देते हैं। योग के नियमित अभ्यास से शक्ति, सहनशीलता और आत्म नियंत्रण बढ़ते हैं। इस प्रकार लगातार योग से जीवन के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, आत्मबोध होता है तथा शांति एवं प्रसन्नता से भरपूर जीवन जीने के लिए अधिक ऊर्जा की अनुभूति होती है। योगाभ्यास तनाव से उबरने के लिए शारीरिक मजबूती प्राप्त करने में सहायक होता है तथा संतुलन की अनुभूति के साथ इससे मस्तिष्क एवं शरीर का मिलन कराया जा सकता है।

पाश्चात्य जगत में योगाभ्यास के सबसे सामान्य पक्ष हैं: हठयोग की शारीरिक मुद्रा एवं श्वास संबंधी अभ्यास तथा ध्यान। हठयोग विभिन्न शारीरिक मुद्राओं तथा आसनों का प्रयोग करते हुए शरीर की क्षमता में वृद्धि करता है। हठयोग की श्वसन पद्धति में सांस को लंबे समय तक खींचने, बिना प्रयास के सांस रोके रखने और उसे बाहर निकालने पर जोर दिया जाता है। मुद्राएं तथा आसन करते समय शरीर के ऊर्जा मार्ग में अवरोध खत्म होते हैं एवं शरीर की ऊर्जा प्रणाली अधिक संतुलित हो जाती है।

यद्यपि योग तनाव कम करने की पद्धति से इतर बहुत कुछ है, किंतु तनाव स्वास्थ्य पर

कई प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव डालता है और योग संभवतः तनाव से लड़ने का अब तक का सबसे संपूर्ण तरीका है। तनाव माइग्रेन, अल्सर और पेट खराब रहने जैसे उन रोगों का ही कारण नहीं होता, जिन्हें तनाव से जोड़ा जाता है बल्कि यह हृदयाघात, मधुमेह और हड्डियों की कमजोरी (ऑस्टियोपोरोसिस) जैसे गंभीर रोगों का भी कारण माना जाता है।

योग के दर्शन और अभ्यास की व्याख्या सबसे पहले पतंजलि ने प्राचीन ग्रंथ योग सूत्र में की थी, जिसे योग पर प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में व्यापक मान्यता प्राप्त है। आज कई लोग योग का अर्थ केवल आसन मानते हैं, जो योग का शारीरिक अभ्यास होता है किंतु आसन व्यक्ति को आरोग्य प्रदान करने में प्रयोग होने वाला एक माध्यम मात्र है। पतंजलि ने आत्मबोध एवं आत्मज्ञान के लिए अष्टांग का मार्ग बताया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है *आठ अंग*। आठ अंग सार्थक एवं उद्देश्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने के नीतिपरक सिद्धांतों से मिलकर बने हैं, जो नैतिक एवं नीतिपरक व्यवहार एवं आत्मानुशासन के नुस्खे की तरह कार्य करते हैं। पतंजलि के अष्टांग को आधार बनाकर विभिन्न योग शास्त्र विकसित हुए हैं। उनमें से प्रत्येक के पास रोगों से बचाव एवं उपचार की अपनी पद्धतियां हैं। यहां तक कि श्री बाबा रामदेव ने भी कपालभाति एवं प्राणायाम को दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया है।

वर्तमान में योग अत्यंत लोकप्रिय हो गया है और अनेक संगठनों ने योग सिखाना आरंभ कर दिया है। किंतु योग चिकित्सा का वैज्ञानिक

लेखक एस व्यास (मानद विश्वविद्यालय) में कुलपति एवं चेयरमेन हैं। इन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान मिल चुके हैं। वह अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी रहे हैं। ईमेल: hrnagendra1943@gmail.com, hrn@vyasa.org

मॉडल विकसित कर योग के मानकीकरण पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। योग चिकित्सा का मॉडल क्या है? इसीलिए योग के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्षों में पर्याप्त अनुसंधान कर इस चिकित्सा की वैज्ञानिक प्रकृति तय करना आवश्यक है।

हमारा शरीर मात्र दिखने वाली शारीरिक संरचना का नहीं बना है, हमारे भीतर चार अन्य अदृश्य अंग (सूक्ष्म एवं कारक आवरण) भी हैं। हम सभी में पांच आवरण अथवा कोष होते हैं।

1. अन्नमय कोष - पोषण युक्त आवरण
2. प्राणमय कोष - ऊर्जा युक्त आवरण
3. मनोमय कोष - मानसिक आवरण
4. विज्ञानमय कोष - बौद्धिक आवरण
5. आनंदमय कोष - आनंदकारक आवरण

हमारे कर्म और संस्कार (स्मृतियां एवं अनुभव) कोषों में ही संग्रहीत रहते हैं। वे

पतंजलि ने आत्मबोध एवं आत्मज्ञान के लिए अष्टांग का मार्ग बताया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आठ अंग। आठ अंग सार्थक एवं उद्देश्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने के नीतिपरक सिद्धांतों से मिलकर बने हैं, जो नैतिक एवं नीतिपरक व्यवहार एवं आत्मानुशासन के नुस्खे की तरह कार्य करते हैं।

आत्मा तथा परमात्मा के बीच दीवार खड़ी करते हैं। इसीलिए मोक्ष का अर्थ होता है आत्मा को कोषों की सीमाओं से मुक्त करना। किसी के साथ जुड़ने के लिए हमें भी उसके जैसी विशेषताएं विकसित करनी होंगी, जिसके साथ हम जुड़ना चाहते हैं। जब तक हम स्वयं को कोषों से मुक्त नहीं करते हैं तब तक हमारे भीतर अहम रहेगा और हम स्वयं को क्षुद्र 'मैं' मानते रहेंगे तथा परमात्मा के साथ हमारा मिलन नहीं हो सकेगा। किंतु दूसरी ओर धरती पर हमारे अस्तित्व के लिए पांचों कोष भी अपरिहार्य हैं। उनके बगैर हम जी नहीं सकते। कोषों पर विजय प्राप्त करना और उनसे मुक्त होना मानसिक शुद्धिकरण एवं विकास की गहन प्रक्रिया है। जब कोई अशुद्धि नहीं बचती, कोई छया बची नहीं रह जाती तब हमारे जीवन के अंत में सूक्ष्म शरीर भी विलीन हो जाता है तथा हमारी आत्मा अनंत, अलौकिक प्रकाश में मिल जाती है तथा उसे परमानंद, परम ज्ञान,

परम शक्ति एवं परम मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दैहिक शरीर अन्नमय कोष है। हम जो भोजन खाते हैं तथा जिस वातावरण एवं समाज में रहते हैं उसका इस पर प्रभाव होता है। इसीलिए योग शिक्षा इस बात पर जोर देती है कि सकारात्मक एवं लाभप्रद मानवीय संचार के साथ ही स्वस्थ एवं सात्विक भोजन हमारे दैहिक एवं मानसिक विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मांस, मदिरा एवं नशे के सेवन से हमारी प्राणशक्ति कमजोर होती है तथा हमारे भीतर नकारात्मकता आती है। दूध एवं सब्जियों से युक्त संपूर्ण भोजन हमारे शरीर को समुचित पोषण प्रदान करता है।

प्राणमय कोष ब्रह्म शक्ति प्राण का सूक्ष्म आवरण होता है जो दैहिक शरीर के चारों ओर रहता है। इससे आभामंडल की रचना होती है, जो हम में से प्रस्फुटित होता है। प्राण सूक्ष्म पोषण है, जो भोजन एवं पेय पदार्थों के ही समान जीवन के लिए आवश्यक है। प्रत्येक श्वास के साथ हम ऑक्सीजन ही नहीं, बल्कि प्राण भी लेते हैं। सभी प्रकार के भोजन हमें पोषक तत्व ही नहीं बल्कि प्राण भी प्रदान करते हैं। हमारे प्राण पर बाह्य वातावरण के साथ ही हमारे विचारों एवं भावनाओं का निर्णायक प्रभाव होता है तथा अन्य कोष भी उससे प्रभावित होते हैं।

मनोमय कोष अर्थात् मानसिक ऊर्जा का आवरण प्राणमय कोष से भी अधिक सघन एवं शक्तिशाली है। मन एवं विचार पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए विचारों पर नियंत्रण बहुत कठिन है। मस्तिष्क की तीव्र अनियंत्रित गति के कारण ही मानसिक उद्वेग उत्पन्न होते हैं तथा तनाव होता है। इसे आधि कहते हैं, जो प्राणमय कोष के असंतुलन के कारण अन्नमय कोष तक पहुंचकर व्याधि बन जाती है। मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त करने से ही ऐसी घटनाओं, तनाव एवं रोगों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। मस्तिष्क पर नियंत्रण का सर्वोत्तम तरीका अच्छे विचारों को जगाना तथा उनके माध्यम से मस्तिष्क को स्थिर करना एवं शांत रहना है। यम एवं नियम का पालन करने, समझने, दान करने, प्रार्थना करने एवं मंत्रोच्चार करने से हमारे कर्मों में सुधार आता है।

विज्ञानमय कोष बौद्धिक इकाई है। इसे सकारात्मक भी बनाया जा सकता है और नकारात्मक भी। यह हमारे समाज तथा हमारे

वातावरण से हम पर पड़ने वाले प्रभावों पर निर्भर करता है। इसकी रचना जीवनपर्यंत अनुभव, पालन-पोषण एवं शिक्षा से होती है तथा उन सभी का योग इसमें निहित होता है। किंतु बुद्धि सदैव हमें सबसे अच्छी सलाह नहीं देती है। प्रायः यह सत्य को अनसुना करती है और हमारी इच्छाओं के अनुरूप आकलन करती है। बुद्धि बहुत उपयोगी हो सकती है किंतु यह बड़ी बाधा भी बन सकती है। इसीलिए हमें सदैव बुद्धि एवं विवेक दोनों से काम लेना चाहिए।

आनंदमय कोष आनंद की इकाई है। यह ऐसा आवरण है, जहां से अन्य चार आवरण उत्पन्न होते हैं तथा संस्कार एवं वासनाओं का उद्भव होता है एवं इसे शुद्ध करना कठिन नहीं होता है। इसका कारण यह है कि हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति एवं आराम तथा आनंद की अभिलाषा शक्तिशाली प्रेरक तथा निर्णायक

हमारे कर्म और संस्कार (स्मृतियां एवं अनुभव) कोषों में ही संग्रहीत रहते हैं। वे आत्मा तथा परमात्मा के बीच दीवार खड़ी करते हैं। इसीलिए मोक्ष का अर्थ होता है आत्मा को कोषों की सीमाओं से मुक्त करना। किसी के साथ जुड़ने के लिए हमें भी उसके जैसी विशेषताएं विकसित करनी होंगी, जिसके साथ हम जुड़ना चाहते हैं।

शक्ति है। अनंत एवं परम आनंद से घिरे हुए आनंद के कई स्तर हैं। पहला कुछ निश्चित शर्तों पर निर्भर करता है, जैसे हमारी इच्छाओं की पूर्ति एवं अन्य अनुकूल परिस्थितियां तथा बाद का स्तर बिना शर्त के होता है और बाह्य स्थितियों का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। स्थायी संतोष एवं महा आनंद हमें तभी प्राप्त होते हैं, जब हमारा स्वयं से साक्षात्कार हो जाता है, अन्य सभी आनंद सीमित एवं क्षणभंगुर हैं। हम ज्ञान के माध्यम से ही स्वयं को आनंदमय कोष से मुक्त कर सकते हैं। भक्ति हमें इस लक्ष्य के निकट ले जाती है किंतु अंतिम चरण की प्राप्ति केवल सत्य के ज्ञान से ही हो सकती है। तभी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।

योग को मस्तिष्क एवं शरीर की चिकित्सा का तरीका माना जाता है, जिसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक पक्षों को एक साथ लेकर स्वास्थ्य, विशेष रूप से

तनाव संबंधी रोगों में सुधार किया जाता है। प्रमाण बताते हैं कि तनाव हृदय रोग, कैंसर एवं हृदयाघात तथा अन्य गंभीर रोगों का प्रमुख कारण है। इसलिए तनाव से निपटने एवं नकारात्मक भावनात्मक स्थिति से मुक्ति पाने तथा रोग पर सकारात्मक रूप से नियंत्रण करने पर जोर दिया जाता है। योग को तनाव से निपटने की संपूर्ण विधि माना जाता है।

योग तनाव कम करने की पद्धति से इतर बहुत कुछ है, किंतु तनाव स्वास्थ्य पर कई प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव डालता है और योग संभवतः तनाव से लड़ने का अब तक का सबसे संपूर्ण तरीका है। तनाव माइग्रेन, अल्सर और पेट खराब रहने जैसे उन रोगों का ही कारण नहीं होता, जिन्हें तनाव से जोड़ा जाता है बल्कि यह हृदयाघात, मधुमेह और हड्डियों की कमजोरी (ऑस्टियोपोरोसिस) जैसे गंभीर रोगों का भी कारण माना जाता है।

और इसमें इस प्रकार की दैहिक गतिविधियां होती हैं, जिनसे तनाव कम होता है। योग का वैज्ञानिक अध्ययन हाल के वर्षों में बढ़ा है तथा इसके चिकित्सकीय प्रभावों एवं लाभों का आकलन करने के लिए परीक्षण भी किए गए हैं।

यह सत्य है कि योग क्रियाएं रोगों के उपचार में प्रभावी हैं। किंतु यह कैसे कार्य करता है? इस पद्धति का वैज्ञानिक आधार क्या है? योग चिकित्सा का तरीका क्या है? इन प्रश्नों का सही, तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक उत्तर दिए बिना योग चिकित्सा पद्धति अधूरी ही रहेगी।

योग चिकित्सा में पहला सत्य तो यही है कि यह मानवीय तंत्र को वैज्ञानिक एवं संपूर्ण दृष्टि में देखता है। मानव शरीर के क्रियाकलाप में प्राण की भूमिका का समग्र ज्ञान आवश्यक है। योग विज्ञान के अनुसार आधि के कारण एवं प्राण में विकृति आने अथवा प्राण में कमी आने के कारण रोग होते हैं। योग विज्ञान रोगों को दो व्यापक श्रेणियों में बांटता है: (1) परिस्थितिजन्य रोग एवं (2) प्रारब्ध कर्म के कारण होने वाले रोग। दोनों स्थितियों में प्राण के प्रवाह में रुकावट आती है किंतु उनके उपचार में अंतर है। योग चिकित्सा में प्राण के शुद्धिकरण में जीवनशैली तथा जीवन के प्रति दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

योग विज्ञान सिद्ध करता है कि हमारे जीवन के सभी पक्षों पर प्राण के समन्वय का प्रभाव पड़ता है। प्राण विभिन्न रूपों में हमारे शरीर में प्रवाहित होता है। आधुनिक विज्ञान प्राण को जीवनी शक्ति, रोगों से लड़ने की क्षमता, जैव-विद्युत तथा विद्युतचुंबकीय ऊर्जा आदि कहता है। वास्तव में ये सभी प्राण के विभिन्न रूप हैं। जिसने प्राण की प्रकृति को थोड़ा सा भी समझ लिया है, उसने अपने ज्ञान के अनुसार ही प्राण चिकित्सा, रेकी आदि की तकनीक विकसित कर ली है। किंतु योग में प्राण का समग्र ज्ञान आवश्यक होता है। योग मानता है कि प्राण का प्रवाह रुकने पर हमारा दैहिक शरीर सूक्ष्म शरीर से अलग हो जाता है। दैहिक भाषा में इसी को मृत्यु कहते हैं।

स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन हेतु प्राण का संरक्षण एवं वृद्धि आवश्यक है। योग का आरंभिक जोर स्वास्थ्य रक्षा पर रहता है। योग विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि योग संबंधी जीवन शैली को अनदेखा करना ही रोगों का मूल कारण है। यदि योग द्वारा बताई गई जीवन शैली का नियमित रूप से पालन किया जाता है तो परिस्थितिजन्य रोगों से पूर्ण मुक्ति संभव है। योग पद्धतियां कर्मों के कारण होने वाले रोगों की समस्या का भी समाधान कर सकती हैं। इस प्रकार योग सभी को रोग मुक्त स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकता है।

यह अर्चिभित करने वाला तथ्य है कि मनुष्य अपने भीतर स्थित प्राण का प्रयोग नहीं करता है और बाद में इसकी कमी से होने वाले कष्टों पर दुख व्यक्त करता है। प्राण को संयम के द्वारा संरक्षित किया जा सकता है तथा जीवन को आनंदमय बनाने के लिए इसका सही प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। किंतु दुख की बात है कि मनुष्य अपनी अनभिज्ञता के कारण स्वयं को कभी तृप्त नहीं होने वाली निरंकुश पाशविक आकांक्षाओं का दास बना लेता है तथा पशुवत जीवन जीता रहता है। योगियों की जीवन शैली में बाह्य एवं आंतरिक जीवन के बीच संतुलन साधा जाता है। यदि जीवन संतुलित होता है तो क्षमता, विशेषज्ञता एवं सफलता तुरंत मिल जाती है। सही जीवनशैली हो तो प्राण का निर्बाध प्रवाह होता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि योगपूर्ण जीवन शैली रोग मुक्त जीवन का स्वर्णिम सिद्धांत है। आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा एवं योग क्रियाएं प्राण प्रवाह के मार्ग में आ रहे अवरोधों को आसानी से दूर कर देती हैं एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करती हैं।

योग चिकित्सा में जीवन का यौगिक दृष्टिकोण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। आज विश्व भर के वैज्ञानिक इस बात पर एकमत हैं कि मनुष्य को होने वाले अधिकतर रोग मनोदैहिक प्रकृति के होते हैं। जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण नहीं होने से ही मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यदि हमारा विश्वास, आस्था, लक्ष्य एवं जीवन के उद्देश्य सही हैं और जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण संतुलित है तो हमारी जीवन ऊर्जा का समुचित उपयोग हो सकता है तथा इससे मनोवैज्ञानिक तनावों एवं व्यग्रता से हमें आसानी से मुक्ति मिल जाएगी। जीवन में यौगिक दृष्टिकोण अपनाया जाए तो तनाव संबंधी समस्याओं के कारण प्राण की हानि से छुटकारा मिल सकता है।

इस प्रकार संपूर्ण जीवन जीने के विज्ञान के रूप में योग न केवल निदान के उपरांत जीवन की गुणवत्ता सुधार सकता है बल्कि इसे विकल्प के रूप में भी आजमाया जा सकता है क्योंकि इससे शल्य चिकित्सा, विकिरण एवं रसायन चिकित्सा के प्रभाव कम होते दिखे हैं। आसन, मंद श्वास, ध्यान एवं निर्दिष्ट कल्पना जैसी विभिन्न योग क्रियाएं सभी कार्यों के बीच समन्वय करने एवं सभी स्तरों पर संतुलन स्थापित करने में सहायक होती हैं।

योग से संबंधित अध्ययन न केवल बेहतर हो रहे हैं, बल्कि भारत एवं अमेरिका में इनकी संख्या भी बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में ही पीठ के दर्द, तंत्रिका तंत्र के रोगों, अनिद्रा, कैंसर, हृदय रोग और क्षय रोग में भी योग के प्रभाव पर शोध हुए हैं। अध्ययनों में यह भी बताया जा रहा है कि योग किस तरह कार्य करता है। योग के कई लाभप्रद

हम सभी में पांच आवरण अथवा कोष होते हैं। 1. अन्नमय कोष - पोषण युक्त आवरण, 2. प्राणमय कोष - ऊर्जा युक्त आवरण, 3. मनोमय कोष - मानसिक आवरण, 4. विज्ञानमय कोष - बौद्धिक आवरण, 5. आनंदमय कोष - आनंदकारक आवरण

प्रभावों में प्रमुख हैं: शक्ति, लचीलेपन एवं संतुलन में वृद्धि, प्रतिरक्षा तंत्र में मजबूती, रक्त शर्करा एवं कॉलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी तथा मनोवैज्ञानिक स्थिति में सुधार। तनाव में कमी तो योग का सबसे बड़ा प्रभाव पहले से है। □



IAS/PCS

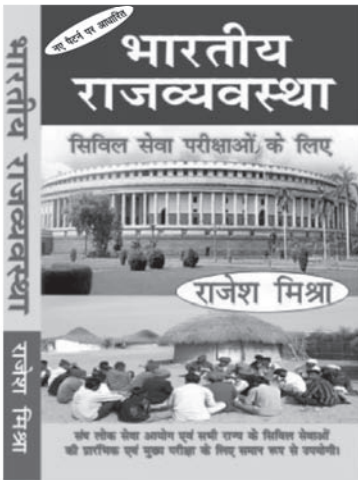
सरस्वती

राजनीति विज्ञान

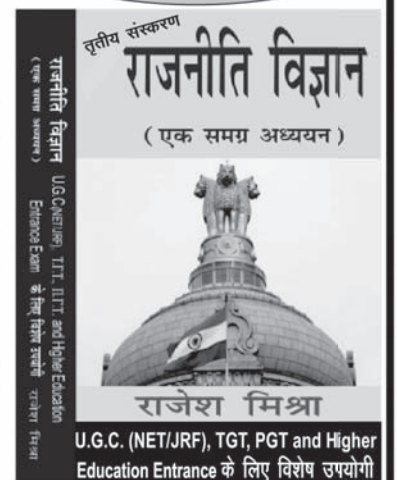
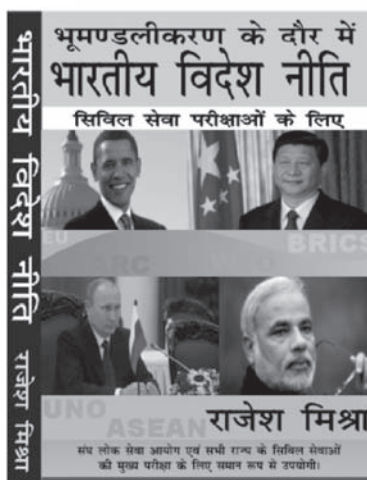
द्वारा **राजेश मिश्रा**The most trusted name in **Political Science****राजनीति विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ संस्थान**

- ★ सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम का सबसे ज्यादा भाग कवर करने वाला विषय।
- ★ वर्तमान पाठ्यक्रम में राजनीति विज्ञान सामान्य अध्ययन का ही विस्तार है।
- ★ हमारे संस्थान के विद्यार्थियों में उ०प्र० टॉपर, उत्तराखण्ड में तीसरा स्थान, बिहार में तीसरा एवं चौथा स्थान, झारखण्ड टॉपर एवं मध्यप्रदेश में 13वीं एवं राजस्थान में 9वीं, 18वीं एवं 25वीं स्थान प्राप्त किया है।
- ★ सिविल सेवा परीक्षा में 28वीं रैंक, 55वीं रैंक, 111वीं रैंक तथा 175वीं रैंक प्राप्त किया है।
- ★ परिणाम अध्ययन की गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं।
- ★ सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का मार्गदर्शन संस्थान के द्वारा किया गया है।
- ★ हमारे संस्थान की सफलता दर सर्वाधिक बेहतर है।

सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी पुस्तकें

**नया बैच
25 मई**

राजव्यवस्था एवं भारतीय विदेश नीति की सबसे प्रमाणिक एवं बेहतर पुस्तक जो अत्यधिक सरल एवं अपडेटेड है।



**A-20, 102, 1st Floor, Indraprasth Tower, (Near Batra Cinema)
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009**

Ph.: 011-27651250, 09899156495

E-mail : saraswati.ias@gmail.com Visit us : www.saraswatiias.com

प्रधानमंत्री उज्वला योजना

प्रधानमंत्री उज्वला योजना प्रधानमंत्री द्वारा 1 मई, 2016 को बलिया में आरंभ की गई। योजना का लक्ष्य गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) के पांच करोड़ लाभार्थियों को रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन प्रदान करना है, जिसके लिए 8,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार के प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1,600 रुपये प्रदान किए जाते हैं। योग्य बीपीएल परिवारों की पहचान राज्य सरकारों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के साथ परामर्श के माध्यम से की जाएगी। यह योजना तीन वर्षों- वित्त वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में लागू की जाएगी। देश के इतिहास में यह पहला मौका है, जब निर्धनतम परिवार की करोड़ों महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली कोई कल्याण योजना लागू की जाएगी। हमारे देश में गरीबों को रसोई गैस (एलपीजी) बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है। एलपीजी सिलिंडरों का प्रसार प्रमुख रूप से शहरी एवं कस्बाई क्षेत्रों में है, जहां ये अधिकतर मध्यम

वर्ग एवं सम्पन्न वर्ग में सिमट जाते हैं। किंतु जीवाश्म ईंधन से भोजन पकाने में स्वास्थ्य को गंभीर जोखिम होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमानों के अनुसार रसोई में अस्वच्छ ईंधनों के कारण ही भारत में करीब 5 लाख मौतें हो जाती हैं। ऐसी अधिकतर असामयिक मौतें हृदय रोग, दिल के दौरों, फेफड़ों की गंभीर बीमारियों और फेफड़े के कैंसर जैसे असंक्रामक रोगों के कारण होती हैं। घर के भीतर वायु प्रदूषण छोटे बच्चों में विभिन्न गंभीर श्वास रोगों का भी कारण है। विशेषज्ञों के अनुसार रसोई में खुली आग रखना एक घंटे में 400 सिगरेट जलाने के बराबर है। बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से देश में सभी जगह रसोई गैस की पहुंच सुनिश्चित होगी। यह उपाय महिलाओं को सशक्त बनाएगा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। इससे मेहनत भी कम होगी खाना पकाने में वक्त भी कम लगेगा। रसोई गैस की आपूर्ति श्रृंखला से ग्रामीण युवाओं को रोजगार भी प्राप्त होगा।

उजाला (उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल): 10 करोड़ बल्बों का वितरण

उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल (उजाला) ऊर्जा बचाने और कार्बन उत्सर्जन में 30-35 प्रतिशत कमी लाने के लिए भारत सरकार का कार्यक्रम है, जो 10 करोड़ एलईडी बल्बों के वितरण के साथ बहुत सफल साबित हुआ है। उजाला योजना ने ऊर्जा बचाने वाली लाइटिंग के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 2014-15 में केवल 30 लाख एलईडी बल्ब वितरित किए गए थे। 2015-16 में एलईडी बल्ब का वितरण 15 करोड़ के पार पहुंच गया, जिनमें 9 करोड़ बल्ब उजाला के अंतर्गत वितरित किए गए और शेष योगदान उद्योग जगत का रहा। भारत सरकार को विश्वास है कि इस वर्ष 20 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण होगा। अनुमान है कि 77 करोड़ पुराने अक्षम बल्ब बदलने का लक्ष्य उजाला के अंतर्गत लगातार प्रयासों और उद्योग की सहायता से मार्च 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। ऊर्जा बचाने वाली घरेलू लाइटिंग

दुनिया भर में ऊर्जा बचाने में सबसे अधिक योगदान कर रही है और भारत में 10 करोड़ एलईडी बल्बों के वितरण के साथ प्रति वर्ष 1,298 करोड़ किलोवाट प्रति घंटा बिजली की बचत हो रही है। इससे देश को 2,600 मेगावाट बिजली क्षमता से बचने में भी मदद मिली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश को प्रतिवर्ष 12 करोड़ टन कार्बन मोनो ऑक्साइड उत्सर्जन घटने से फायदा हुआ है। एलईडी बल्ब सीएफएल के मुकाबले आधी और सामान्य बल्बों की अपेक्षा 10 प्रतिशत ही बिजली खर्च करते हैं। उजाला दुनिया में सबसे बड़ा सब्सिडी रहित एलईडी कार्यक्रम है। इन बल्बों का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की इस कार्यक्रम से बहुत बचत हुई है। राज्य सरकारें स्वेच्छा से इस योजना को अपना रही हैं और 13 राज्यों में यह योजना पहले से चल रही है। ईईएसएल महीने भर के भीतर कुछ अन्य राज्यों में वितरण आरंभ करने जा रही है।

उजाला योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बचत

उजाला योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को उजाला के डैशबोर्ड www.delp.in पर जाकर अपने आसपास निकटतम वितरण किरायास्क ढूँढें। उजाला योजना अब क्रांति बन चुकी है और हर व्यक्ति इससे जुड़ा है। एलईडी बल्ब अपनाने से बचने वाली ऊर्जा देश में कहीं किसी एक घर को रोशन करने में मदद कर रही है।

ऊर्जा की अनुमानित वार्षिक बचत	1,298 करोड़ किलोवाट प्रतिघंटा
पीक लोड में अनुमानित कमी	2,600 मेगावाट
उपभोक्ताओं के बिल मूल्य में अनुमानित वार्षिक कमी	5,195 करोड़ रुपये
ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में अनुमानित वार्षिक कमी	1 करोड़ टन कार्बन डाई ऑक्साइड

षष्ठम् संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण 2016

**Just
Released**

सिविल, बैंकिंग एवं डिफेंस
सेवाओं के लिए उपयोगी

वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर सहित



Code No. 811
Price ₹ 110.00

सिविल, बैंकिंग एवं डिफेंस
सेवाओं के लिए भी उपयोगी
वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर सहित

नवीनतम आँकड़ों एवं
तथ्यों का समावेश

लघु अतिरिक्तांक
प्रतियोगिता दर्पण

मूल्य - ₹ 110.00

द्विभाषित युवा वर्ग के स्टूडेंट्स अविष्य के लिये

सामान्य अध्ययन
अर्थव्यवस्था
एक दृष्टि में

केन्द्रीय बजट, रेल बजट 2016-17

आर्थिक समीक्षा 2015-16

नवीनतम आँकड़ों
एवं तथ्यों का
समावेश

विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी

प्रतियोगिता दर्पण

2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा-282 002 फोन : (0562) 4053333, 2530966; फैक्स : (0562) 4053330

• E-mail : care@pdgroup.in

• Website : www.pdgroup.in

• नई दिल्ली 23251844/66

• हैदराबाद 66753330

• पटना 2673340

• कोलकाता 25551510

• लखनऊ 4109080

• हल्द्वानी नो. 7060421008

• नागपुर 6564222